

Tel. : +91-11-28742357

Mob. : +91-9891095232

GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED

Regd. Off. : R-815, (B-11), New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060

E-mail : genesislimited1995@gmail.com, CIN : L67190DL1995PLC069768

Web-site : www.genesisdevelopersholdings.com

Date: -12-08-2021

To,

The Head-Listing & Compliances
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,
Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 098

Sub: Filing of clipping of the Unaudited Financial Results published in the newspaper for the quarter ended 30.06.2021 as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SYMBOL: GDHL)

Dear Sir,

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of Hindi Daily Open Search (Hindi News Paper) and English Daily Open Search (English News Paper) dated **12-08-2021** in which Unaudited Financial Results of the company has been published for the quarter ended **30.06.2021**, as approved by the Board of Directors of the company in their meeting held on **11.08.2021**.

You are requested to take on your records and acknowledge the same.

**For and on behalf on
GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED**



**Deepak Tyagi
(Managing Director)
DIN: 02760361**

Encl: a/a



सिद्धार्थ, कियारा ने आई-डे स्पेशल में... पृष्ठ-8

वर्ष : 06 अंक : 132

नई दिल्ली, गुरुवार 12 अगस्त-2021

नई दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से प्रसारित

मूल्य : 02 रुपए

पृष्ठ : 08

किन्नौर भूस्खलन : 10 लोगों की मौत, 13 लोग बचाए गए

कई अब भी फंसे, दबे हैं एचआरटीसी की बस समेत छह वाहन

भावनगर/किनांगपिओ, एजेंसी

हिमाचल प्रदेश के किनांगपिओ में गिनुल्सरी में राखीय राजमार्ग पांच पर पहाड़ टूटने से हुए हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है जबकि थपल हुए 13 लोगों को बचा लिया गया है। बायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावनगर भेजा गया है जबकि एक कार आंशिक रूप से और दूसरी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पहाड़ी से दरक फलने की चपेट में स्वर्णगो से थोड़ी दूरी पर भी आ गई है। बताया जा रहा है कि 24 वाजरी सवार थे। मलबे में 60 से अधिक लोग दबे बचाए जा रहे हैं।

जिना प्रशासन समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ समेत सीआरपीएफ व आइटीबीपी की टीम मौके पर पहुंच गई है व राहत कार्य शुरू कर दिया है। सीएम जयराम ठाकुर हादसे का जायजा लेने झाड़वी पहुंचे, वहां से सड़क के माध्यम से गिनुल्सरी पहुंचे। एनडीआरएफ टीम ने 13 लोगों को रेस्क्यू किया है। 10 लोगों के शव

पहाड़ी से दरक मलबे की चपेट में सवारियों से भरी एक बस भी आ गई है। बताया जा रहा है बस में 24 वाजरी सवार थे। मलबे में 60 से अधिक लोग दबे बताए जा रहे हैं।



बचामद किए गए हैं। बताया जा रहा है चार लोग खुद जखमी हालत में मलबे से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच गए। बचाव कार्य जारी है, लेकिन एक बचामद मलबा गिरने से बचाने कार्य प्रभावित हो रहा है। आइटीबीपी के प्रवक्तृत्वताम पावनी निवासी, नरप्राजित

निवासी पंजाब, अरविंद शर्मा निवासी नेपाल, सबकी देवी सराहन, गुलाब सिंह मंडी, अरण निवासी मरहत, चंद जान रोपा निवासी को रेस्क्यू किया गया है, इन्हें इन्फो चौटे लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सीएनडी भावनगर ले जाया गया है। जवानों ने

पीएम मोदी व अमित शाह ने की जयराज ठाकुर से बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन्नौर हादसे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने बचाव अभियान में हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा किन्नौर हादसे के बाद आइटीबीपी के डीजी ने बात की है व टीमों राहत व बचाव कार्य में जुट गई हैं। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की है।

राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे से 13 लोग जिता निकाले जा चुके हैं। 10 लोगों के शव बचामद किए जा चुके हैं। अभी कई लोग फंसे हुए हैं। घटनास्थल पर एक-एक कर भूस्खलन होने में बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। घटनास्थल के दोनों तरफ अभी भी

पाथर और मलबा गिर रहा है। सड़क पर भारी मलबा गिरने के कारण प्रशासन व बचाव दल को मौके पर पहुंचने के लिए काफी मुश्किलें/कठिनाई पड़ी। हादसे के बाद राहत व बचाव कार्य टीमों के खाना हो चुका है। फिलहाल हादसे में छताहत होने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में अवगत करवाया कि किन्नौर में एक हादसा हो गया है। जिनमें राहत कार्य करने के लिए एनडीआरएफ, आइटीबीपी, सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। स्थानीय प्रशासन को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था उन्होंने भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। राहत के नीचे दबी बस से लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही मौके पर होगी। इस घटना में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल तक लाया जा सके।

मानसून सत्र में सिर्फ 22% कार्यों का हुआ निष्पादन

नई दिल्ली (एजेंसी)

पेगामस जापूरी मामले, किसानों के मुद्दे और महंगाई को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध के कारण सदन में सिर्फ 22 प्रतिशत कार्यों का निष्पादन हुआ। लोकसभा अंकुश ओम बिरला आम बिरला ने बुधवार को 17वीं लोकसभा के छठे सत्र के समापन पर कहा कि इस सत्र में सदन का काम काज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक का ही कार्य संवाहित किया गया।

उन्होंने कहा कि व्यवधान के कारण बैठक के लिए नियत 96 घंटे में से कुल 74 घंटे 46 मिनट तक सदन में काम काज नहीं हो सका। इसके कारण इस सत्र में सदन का कार्य निष्पादन मात्र 22 प्रतिशत रहा। श्री बिरला ने कहा कि सत्र के अंतर में लोकसभा के चार नए सदस्यों ने 19 जुलाई को सदस्यता की शपथ ली। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक और विधायी कार्यों का निष्पादन किया गया।

इस सत्र के दौरान 13 सरकारी विधेयक पुरस्चित किए गए। सविधान (127वां) संशोधन विधेयक, 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। सत्र के



लोकसभा अंकुश ओम बिरला आम बिरला ने बुधवार को 17वीं लोकसभा के छठे सत्र के समापन पर कहा कि इस सत्र में सदन का काम काज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। निरंतर गतिरोध के कारण इस सत्र में सदन की कुल 17 बैठकों में मात्र 21 घंटे 14 मिनट तक का ही कार्य संवाहित किया गया।

दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद सत्र काल में 66 तारकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने नियम 377 के अधीन कुल 331 मामले उठाने तथा स्थायी समितियों द्वारा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। गतिरोध के कारण महत्वपूर्ण विधेयक पर कुल 52 वक्तव्य दिए गए और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्यों के संबंध में तीन वक्तव्य

भी दिए गए। सत्र के दौरान, संबोधित माननीय सदस्यों द्वारा 1243 पत्र सभा पटल पर रखे गए। अध्यक्ष ने कहा, मैं सभा की कार्यवाही को पूरा करने में सहायता तालिका में शामिल अपने साथियों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सभी दलों के नेताओं और सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

एक नज़र

आत्मनिर्भर भारत की सफलता का दायित्व भारतीय उद्योग पर : मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की भारतीय उद्योग जागतिक का नए संकल्पों और नए लक्ष्यों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर बताते हुए आज कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। श्री मोदी ने भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सीआईआई की ये बैठक इस बात का 75वां स्मरणोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही है। ये बहुत बड़ा अवसर है। भारतीय उद्योग जागतिक के नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए उद्योगों को आज का नया भारत, नई युनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। जो भारत को भी निवेश को आकर्षित पा, आज जो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। आज स्थिति तेजी से बदल रही है। देशवासियों की भावना, भारत में बने उत्पादों के साथ है। कगने भारतीय हो, ये जल्दी नहीं, लेकिन आज हर भारतीय, भारत में बने उत्पादों को अपनाया चाहता है।

संसेक्स 29 अंक लुढ़का, निफ्टी मामूली बढ़त में

मुंबई (एजेंसी) बैंकिंग स्तर से मिले सकारात्मक संकेतों के बावजूद घरेलू पार इंडेक्स, बैंकिंग, फिन, सोप्टी जैसे समूहों में हल्की बिकवाली के कारण बीएसई का 30 सेक्टर वाला संसेक्स 29 अंक टूटकर 54525.93 अंक पर रहा जबकि एनएसई का निफ्टी 2.15 अंक बढ़कर 16282.25 अंक पर रहा। दिग्गज कंपनियों के साथ ही छोटे और मझोली कंपनियों में बिकवाली का दबाव बना रहा। बीएसई का मिडकैप 0.22 प्रतिशत गिरकर 22710.96 अंक पर और स्मॉलकैप 0.33 प्रतिशत फिसलकर 25449.20 अंक पर आ गया। बीएसई में कुल 3332 कंपनियों में कारोबार हुआ जिनमें से 2142 कंपनियां निरपेक्ष में खी जबकि 1063 बढ़त में रही। इस दौरान 127 कंपनियां उधार बहाव के बीच गिरा रहने में सफल रही।

देश में रिकवरी दर बढ़कर 97.45 फीसदी

नई दिल्ली (एजेंसी)

देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के 38,353 नये मामले सामने आए हैं और इस बीच स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने से रिकवरी दर बढ़कर 97.45 फीसदी हो गई है। देश में मंगलवार को 41



लाख 38 हजार 646 लोगों को कोरोना के टीके लगाये गये तथा अब तक 51 करोड़ 90 लाख 80 हजार 524 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,353 नये मामले सामने आने के साथ ही रिकवरी दर अंकुश बढ़कर तीन करोड़ 20 लाख 36 हजार 511

हो गया है। इस दौरान राज्य में 7720 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कोरोनामुक्त होने वाली की तादाद बढ़कर 6159676 हो गयी है, जबकि 137 मरीजों की मौत होने से मृतकों का अंकुश बढ़कर 134201 हो गया है। केरल में इस दौरान सक्रिय मामलों 2474 बढ़कर 172505 हो गये हैं।

बारहवीं पास चंपा ने 5500 परिवारों को जैविक खेती सिखा पाया सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संवाद

अनुपपुर (एजेंसी)

बेहद गरीबों में पत्नी-बहू और महज बारहवीं तक पढ़ी चंपा सिंह की मेहनत और आर्थिक मदद से चंपा ने 5500 परिवारों को जैविक खेती सिखाया। जैविक खाद निर्माण, उपयोग और उपज बढ़ाने की प्रशिक्षण देने वाली चंपा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर नारे शक्ति से संबद्ध कार्यक्रम के तहत बातचीत करेगी।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कृषि सखी मास्टर ट्रेनर के रूप में चंपा अब तक 5500 परिवारों को जैविक खाद (कमी कंपोस्ट) आगाने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दे चुकी हैं। सफलता की कथाओं को छूने वाली चंपा का पूरा आत्म जीवन बहुत कठिनाई में बीता। अनुपपुर जिले के आदिवासी बहुल पुष्पाजगढ़ विकासखंड के सोनिकामर गांव की निवासी चंपा ने साल की थी, तभी पिता जान सिंह का निधन हो गया। मा ने शहखाल बालिका



छात्रावस में प्रवेश दिनवाकर चंपा को आठवीं तक पढ़ाया लेकिन इसके बाद आर्थिक मजबूतियों के कारण वे गांव आ गईं। उन्होंने ओपन स्कूल से बारहवीं तक पढ़ाई की। कुछ समय बाद भाइयों ने विवाह कर दिया और सखी के रूप में जैविक खेती से जुड़े प्रयोगों का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भी चंपा ने जैविक कृषि पद्धति का प्रशिक्षण दिया। उन्हें हरियाणा के इज्जत विकास खंड में कार्य करने का मौका मिला।

15 दिन के मानदेय के रूप में पहली आय 11600 रुपये हुई। इसके बाद उन्होंने जैविक खेती के प्रशिक्षण को ही मुख्य काम बना लिया। चंपा अब तक करीब 5500 परिवारों को यह प्रशिक्षण दे चुकी हैं। एक बार के प्रशिक्षण के बदले 700 रुपये मानदेय प्राप्त होता है।

चंपा स्वसाक्षरता समूह की मदद से जैविक खाद और कीटनाशक भी तैयार करती हैं। जैविक कीटनाशक दवा पत्तियों, गोबर और गोमूत्र के माध्यम से तैयार किया जाता है। अनुपपुर जिले में करीब दो हजार किसानों ने उनसे प्रेरित होकर जैविक खेती अपना ली है।

काम घर बैठे ही कर सकेगी। इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश महलोन, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (ट्रांसपोर्ट) समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने ट्वीट कर कहा, "परिवहन विभाग के इस दफ्तर पर ताला लगाकर इसकी फ़ैसलेस सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरटीओ कार्यालय में ताला लगाकर यह संकेत दिया कि अब किसी काम के लिए आपको आरटीओ कार्यालय नहीं आने होंगे। अब आप अपने खोए

सखी के रूप में जैविक खेती से जुड़े प्रयोगों का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भी चंपा ने जैविक कृषि पद्धति का प्रशिक्षण दिया। उन्हें हरियाणा के इज्जत विकास खंड में कार्य करने का मौका मिला।

15 दिन के मानदेय के रूप में पहली आय 11600 रुपये हुई। इसके बाद उन्होंने जैविक खेती के प्रशिक्षण को ही मुख्य काम बना लिया। चंपा अब तक करीब 5500 परिवारों को यह प्रशिक्षण दे चुकी हैं। एक बार के प्रशिक्षण के बदले 700 रुपये मानदेय प्राप्त होता है।

चंपा स्वसाक्षरता समूह की मदद से जैविक खाद और कीटनाशक भी तैयार करती हैं। जैविक कीटनाशक दवा पत्तियों, गोबर और गोमूत्र के माध्यम से तैयार किया जाता है। अनुपपुर जिले में करीब दो हजार किसानों ने उनसे प्रेरित होकर जैविक खेती अपना ली है।

काम घर बैठे ही कर सकेगी। इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश महलोन, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (ट्रांसपोर्ट) समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने ट्वीट कर कहा, "परिवहन विभाग के इस दफ्तर पर ताला लगाकर इसकी फ़ैसलेस सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरटीओ कार्यालय में ताला लगाकर यह संकेत दिया कि अब किसी काम के लिए आपको आरटीओ कार्यालय नहीं आने होंगे। अब आप अपने खोए

सखी के रूप में जैविक खेती से जुड़े प्रयोगों का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भी चंपा ने जैविक कृषि पद्धति का प्रशिक्षण दिया। उन्हें हरियाणा के इज्जत विकास खंड में कार्य करने का मौका मिला।

काम घर बैठे ही कर सकेगी। इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश महलोन, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (ट्रांसपोर्ट) समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने ट्वीट कर कहा, "परिवहन विभाग के इस दफ्तर पर ताला लगाकर इसकी फ़ैसलेस सेवाओं की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आरटीओ कार्यालय में ताला लगाकर यह संकेत दिया कि अब किसी काम के लिए आपको आरटीओ कार्यालय नहीं आने होंगे। अब आप अपने खोए

राज्यों को मिला ओबीसी सूची बनाने का अधिकार

नई दिल्ली (एजेंसी)

राज्यसभा ने आज 105वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया जिससे अब राज्यों को फिर से अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की सूची बनाने का अधिकार मिल गया है। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है और इस तरह से इस संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर लग गयी है।

इस विधेयक के पक्ष में 187 मत पड़े जबकि विरोध में शून्य। राज्यसभा में करीब पांच घंटे तक चली चर्चा का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पंजी डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा बचाव देने के बाद सदन ने इसे मत विभाजन के जरिए पारित कर दिया। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान करना गड़ा क्योंकि इस तरह के विधेयक के लिए सदन में उभरथान दो सिद्धांत सदस्यों की सहमति की जरूरत होती है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के हितों को रक्षा को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों माफ है। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के समय सवने उसका समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के हितों को रक्षा को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों माफ है। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के समय सवने उसका समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के हितों को रक्षा को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों माफ है। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के समय सवने उसका समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के हितों को रक्षा को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों माफ है। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के समय सवने उसका समर्थन किया था।

और इसे पारित करने का आश्वासन दिया था। विधेयक को पारित करने से पूर्व संविधान (127 वें संशोधन) विधेयक के नाम को बदल कर संविधान (105वां संशोधन) विधेयक किया गया।

चर्चा का जवाब देते हुए डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक को पारित होने के बाद राज्य



सरकारों की सूची के अनुसार ओबीसी समुदाय के लोगों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के हितों को रक्षा को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों माफ है। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के समय सवने उसका समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के हितों को रक्षा को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों माफ है। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के समय सवने उसका समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के हितों को रक्षा को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों माफ है। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के समय सवने उसका समर्थन किया था।

उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के हितों को रक्षा को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों माफ है। वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के समय सवने उसका समर्थन किया था।

एक नज़र

परफॉर्मेंस ग्रांट योजना में चयनित गांव बनेंगे मॉडल, अपनाई जाएगी ई-निविदा प्रक्रिया: जिलाधिकारी

गोरखपुर (एजेंसी) गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किशन आनंद ने बुधवार को परफॉर्मेंस ग्रांट की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन गांवों के विकास कार्य के लिए ई-निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इसलिए सम्बंधित विभाग शासन के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी शुरू कर दी। जिलाधिकारी सभागाए में बुधवार को होने वाली सम्पूर्ण बैठक के दौरान अध्यात्मता कर रहे डीएम विजय किशन आनंद ने कहा कि परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के तहत चयनित गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करना ही योजना का लक्ष्य है। चयनित गांवों का विकास शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए सम्बंधित अधिकारी अभी से यह सुनिश्चित करें कि योजना के तहत होने वाले विकास कार्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप के मुताबिक ही पूरे किए जाएं।

उन्होंने कहा कि योजना के लिए बनाए गए विनियम और प्रशासनिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना सम्बंधित विभागों के जिम्मेदारों का दायित्व है। नेतृत्वहीन दौरे हुए डीएम ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं चाहिए और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे करने होंगे। यह कार्य निविदा ई-निविदा प्रक्रिया का पालन करते हुए करना है। बैठक में डीपीआरओ हिमंशू श्रेष्ठर त्रकुर और सम्बंधित विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल रहे।

मुरादाबाद: डिवाइडर से टकराकर डबल डेकर बस खाई में पलटी, 20 यात्री घायल

मुरादाबाद (एजेंसी) मुरादाबाद शानाक्षेत्र में मंगलवार की देर रात को दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबल डेकर बस खाई में पलट गई। हादसे में 20 लोग घायल हैं, जिनमें दस लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में करीब 100 से अधिक लोग सवार थे। इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर अधिकारियों मौके पर पहुंचकर पाँड़ितो वधासमभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी नवाब सिंह के मुताबिक, डबल डेकर बस मंगलवार की रात को सीतापुर से पनौत जा रही थी।

इसमें करीब 130 सवारों थे। बस रामपुर से निकलकर मुहण्डा क्षेत्र में मिहोरा बाजे गांव के पास पहुंची थी, तभी अचानक बस किसी बहाने से टकराने के बाद डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित बस दूसरी साइड में जाकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में चीख फकार मच गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव का कार्य करते हुए पावलों को खुल्लेम के जरिये रामपुर और मुरादाबाद भेजा गया है। घायलों में 10 की हालत गंभीर है।

पुरादाबाद के जिला अस्पताल में मोनू, अनिल, रामोतार, सौरभ, मनोज, पूजा, प्रतीक, शादव, रूपरानी, योगिता, मालती व रामसेवक को भर्ती कराया गया है। मौओ इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि घायलों का जिला अस्पताल में बेहतर इलाज कराया जा रहा है। वहीं, रामपुर के अस्पताल में करीब आठ से दस लोगों को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग मजदूर हैं। वे काम पर सौंपे जा रहे थे। घटना के बाद से बस का चालक पार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

अयोध्या: मणि पर्वत मेले के साथ शुरू हुआ सावन झूला मेला, सामूहिक सरयू स्नान पर पाबंदी

अयोध्या (एजेंसी) मणि पर्वत मेला से बुधवार को राम नगरी का सावन झूला मेला शुरू हो गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सावधानी के तौर से श्रद्धालुओं से रूम की नगरी खाली कराई गई। देर रात प्रशासन ने मंदिरों से अपील की, कि अयोध्या में भीड़ न बढ़ने दिया जाए और बाहर से आए श्रद्धालुओं को समझा-बुझाकर प्रशासन ने वापस उनके घरों को भेजा गया। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सावन मेले में बड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि सामूहिक सरयू स्नान नहीं करने दिया जाएगा और इस पर सख्ती से पाबंदी भी लगाई गई है।

अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को नैगेटिव कोरोना की लैपेट रिपोर्ट देना होगा। परंपरा को मंदिरों के अंदर ही निभाना रहेगा। मंदिर प्रबंधन मंडल परिसर में ही भगवान को झुलोलव का आनंद कराएंगे। सावन झूला मेला के प्रथम दिन सावन शुक्ल तृतीया को मणि पर्वत का प्राचीन मेला लगता है। अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों के विश्व मणि पर्वत जाते हैं। मणि पर्वत पर भगवान के निवास को झूला झुलाना जाता है। इस बार कोविड-19 देखते हुए अयोध्या के मंदिरों के विग्रह मणि पर्वत नहीं जाएंगे।

प्रशासन के अनुरोध पर मणि पर्वत पर मेले की दुकानें नहीं लगेगी। आज से सावन झूला मेला शुरू हो गया है। नगर के सभी मंदिरों में झूले पड़ेगे, जहां भावजन झुलोलव का आनंद लेंगे। आज से सावन भर यह उत्सव चलेंगा। बताते चलें कि, कोविड-19 महामारी के चलते बीते दो साल से राम की नगरी में मेलों पर पाबंदी लगी हुई है। इस वर्ष भी अयोध्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और पाबंदी का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

गर्भवती महिला से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस के हथ्थे चढ़ा

कानपुर (एजेंसी) कानपुर शानाक्षेत्र में गर्भवती महिला से दुष्कर्म का मामला दो दिन पूर्व प्रकाश में आया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर पार आरोपित को तलाश शुरू कर दी थी। आरोपित को पुलिस ने शहर से पकड़ लेने से पूर्व दबोच लिया और उसे जेल भेज दिया है। आरोपी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के घर पहुंची, लेकिन वह पार हो चुका था। पुलिस की टीमों ने आरोपी को पकड़ने के लिए सुशुद्ध तंत्र को लगाते हुए खोजबीन शुरू की। बीते देर रात गर्भवती से दुष्कर्म के पार आरोपी को इस्पेक्टर कुंज बिहारी मिश्रा ने पुलिस टीम के साथ शहर में भागने से पूर्व दबोच लिया। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।

ऑपरेशन क्लीन: पुलिस मुठभेड़ में शांति बंदमाश घायल

झांसी (एजेंसी) पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। अब तक पुलिस का मुठभेड़ को अंजाम दे चुकी है। इसमें 10 लोगों को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ दिन शांत रहने के बाद देर रात पुलिस की वृक्षार पार गलत डो। थाना एएच क्षेत्रांतर्गत रावि में समय करीब 2 बजे थानाध्यक्ष एच व स्कट की संयुक्त पुलिस टीम भी गुरसराय-एच रोड, गुप्तमय बाईपर पर चौकिया के दौरान काले रंग की पकड़ सवार दो बंदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गयी।

इसमें से एक घायल हो गया जबकि दूसरे को दबोच लिया गया। मुठभेड़ में बंदमाश 42 वर्षीय सुनील कुमार गौड़ पुत्र तारकेश्वर प्रसाद गौड़ निवासी सक्की गण्डई नैनी थाना नैनी जनपद प्रतापगढ़ के घर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे बंदमाश गुरांज पुत्र श्रीराम निवासी पुरावैतपुर थाना जरावा जनपद प्रतापगढ़ अब 55 वर्ष का बौद्धिक पकड़ गया।

बंदमाशों के कब्जे में चोरी किये गये सम्मान का बैचकर अर्जित किये गये 50 हजार रुपये,01 बोरे में बिजली का सामान,02 तम्बाकू 315 बोरे, 04 छोटा कार्टूस व 03 जिन्दा कार्टूस बरामद किए। पकड़-ताकड़ में बंदमाशों ने स्वीकार किया कि बीते 1 जुलाई को थाना बड़ागांव क्षेत्र के ज्ञानछाड़ नहर, बिट्टुल उपखण्ड के त्रैमपर में 700 लीटर तेल चोरी व तंबाकू उन्होंने ही निकाला था। बंदमाशों के पास से बरामद 50 हजार रुपये उसी सामान को बैचकर अर्जित किए गए थे।

वाराणसी में गंगा और वरुणा के कहर से मोदी चिंतित, डीएम से जाना हालात

वाराणसी (एजेंसी) वाराणसी में गंगा की रौंद लहरों की विभीषिका झेल रहे नागरिकों की पीड़ा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक पहुंची है। अपने संसदीय क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के उच्चतम बिंदु की ओर तेजी से बढ़ने की जानकारी पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिलाधिकारी कोशलराज शर्मा को गेन कर हालत की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारी को बाढ़ के हालात से निपटने के लिए हस्तसंभव मदद का पुरोस दिया। प्रधानमंत्री ने हालात और व्यवस्थाओं पर भी बातचीत की। जिलाधिकारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत एवं बचाव कार्य के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी।

प्रधानमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश देकर उनके सुरक्षा की कामना की। बनारस में बाढ़ के भयावह रूप को देख प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरुवार को हालात का जायजा लेने शहर में आ रहे हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव और बारिश से जनजीवन दहशत सा गया है। गंगा और वरुणा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ शहर के अन्य हिस्सों में भी बाढ़ का पानी

पहुंच गया है। इसका वयाग भी बढ़ने लगा है। शहर की सड़कों और गलियों में आने-जाने के लिए नाव हो सहाय बन गई है। गलियों में नाव के जरिये ही राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बुधवार सुबह 10 बजे तक गंगा का

तो गुरुवार देर रात तक गंगा की लहरें उच्चतम बिंदु 73.901 मीटर को भी पार कर जावेगी। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से सामने घाट की सड़कों पर नाव चलने लगी है। दशाभ्येष्ट घाट से गोदालिया की ओर पानी बढ़ चला है।

माणिकगंगा घाट पर गलियों में पानी भर गया है। शव घाट तक नावों से ले जाए जा रहे हैं। मंदिर के छत पर शवदाह हो रहा है। गंगा किनारे द्वाब क्षेत्र के नागरिक भी बाढ़ से बेहाल हैं। गंगा में आई बाढ़ से बैदावर, रमना, नैपुसकाली, नैपुस खुर्द, टिकरों, डोमरी, सृजाबाद, मुस्ताफाबाद, चांदपुर, छितौनी, तातेपुर, कलसर 72.04 मीटर दर्ज किया गया। केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वाराणसी में बाढ़ का उच्चतम बिंदु 73.901 मीटर है। संभावना है कि गंगा में बढ़ाव का क्रम ऐसे ही बना रह

गाजपुर, कोंटवा, मेहवार, शिवदरा, बर्धवा, गंगापुर, देवरिया, धाराधर, रामपुर, गोंबखंड, रामचंद्रपुर, अजयग, इमलिया, लुटकाला, मोकलपुर, छितौनी, गौर, पिपरी, डूडका, कमीनी, लुटखुर्द, बर्धवाकाला, कैथी, शहंशाहपुर, करसड़ा, परसपुर, माधोपुर,



एक सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अभी शिक्षण संस्थानों में 50 फीसद छात्रों के साथ भौतिक रूप से पढ़ाई शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का आकलन करते हुए कक्षा छह से आठ तक के कक्षाओं में भी एक सितंबर से पढ़ाई शुरू की जा सकती है।



लखनऊ (एजेंसी) उत्तर प्रदेश में सभी बोर्डों के कक्षा 9 से 12 तक के माध्यमिक कालेजों और डिग्री कालेजों में प्रवेश शुरू होने के बाद एक सितंबर से पढ़ाई शुरू की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के बाद माध्यमिक, उच्च, प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू हो रही है। इसके दृष्टिगत 18 वर्ष से अधिक विद्यार्थियों के टीकाकरण समाप्त के दिशा-निर्देशों का सभी शिक्षण संस्थान अवश्य पालन करें। कक्षाएं दो पलों में चले और कोविड प्रोटोकॉल का पुरा ध्यान रखा जाए।

यूपी में साप्ताहिक बंदी से मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइन जारी करने के लिए निर्देश

लखनऊ (एजेंसी) उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। अब प्रदेशवासियों को दो दिन की साप्ताहिक बंदी से भी छुटकारा मिल सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इस संबंध में गृह विभाग विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड को नियंत्रित स्थिति को देखते हुए दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट दिए जाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 की बैठक में साप्ताहिक बंदी की नई व्यवस्था के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कलें भी अनावश्यक भीड़भाड़ न हो। पुलिस प्रेडिगन सतत जारी रहे। सरकार को चाहिए है कि आमजन को हर तरह से राहत मिले, लेकिन स्वास्थ्य को बिना भी छेदी नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी



लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। बुधवार को अलीगढ़, अमेठी, मिर्जापुर, पटना, मिर्जापुर, गोंड, धारवा, कासगंज, प्रीतीभीत, प्रतापगढ़, रामगढ़ और सोनभद्र में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रत्येकरी हुई तो लखनऊ में देश के अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी विभिन्न गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गईं। बाजारों या सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ सेकने के लिए चरणवार रातोंके से शुरुवार, शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी लगा दी गई। फिर जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो सरकार ने बाजार, मॉल, मल्टीप्लेक्स, दफ्तर खोलने के साथ साप्ताहिक बंदी को भी घटाकर दो दिन का कर दिया।

अब नूतन प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से कब्जे में नजर आ रहा है, इसलिए सरकार ने माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने का भी फैसला कर लिया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रत्येकरी हुई तो लखनऊ में देश के अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी विभिन्न गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गईं। बाजारों या सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ सेकने के लिए चरणवार रातोंके से शुरुवार, शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी लगा दी गई। फिर जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो सरकार ने बाजार, मॉल, मल्टीप्लेक्स, दफ्तर खोलने के साथ साप्ताहिक बंदी को भी घटाकर दो दिन का कर दिया।

मुरादाबाद में किसान के बेटे ने लौटा दी किसान सम्मान निधि, रकम लौटाते वक्त एसडीएम से क्या कहा

मुरादाबाद (एजेंसी) किसानों के हितों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाते हैं। एक किसान ने खुशी की मियाला पेश की है।

युवा किसान का जब शिक्षक पद पर चयन हो गया तो वह किसान सम्मान निधि का पैसा लौटाने के लिए एसडीएम सदर को प्रार्थना पत्र देते पहुंचा। एसडीएम को पत्र देकर युवक ने कहा कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है।

सरकार जो पैसा देगी, उसमें वह अपने पूरे परिवार का खर्च उठा सकता है। अपसर ने भी इस फैसले को सफलतापूर्वक बताया हुए शुक्रों की पीठ शयनपराज झैलता बहुरा।



उन्होंने कहा कि यह कदम दूसरों की सोख खास गांव निवासी ओमवीर ने बीएड की परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक भर्ती के

जमुनीपुर, तिलंगा और मरुई आदि शामिल हैं। वहीं, शहर का चौकाघाट, सरैया, सलारपुर, सिकरील, कोनिया, नरखीघाट, हुकुलगंज, काशीपुर, दानियालपुर, अमरपुर, चामाबाद, नगवा, शिवगंगा, भगवानपुर, सीरोगवर्धनपुर, मिश्रगंज नगर और छापे प्रभावित हैं।

उपर, गंगा के पलट प्रवास से वरुणा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में जल प्रलय से नागरिक बेहाल हैं। वरुणा के किनारे स्थित मोहल्ल पुराना पुल, सरैया, पुराकाहना, शैलपुरी, लखखीघाट, रेलखरिवा, चौकाघाट, हुकुलगंज, वरुणा पुल,नई बस्ती आदि इलाकों में पानी भर गया है।

नरोयार नाले में वरुणा नदी का पानी भरने से छे किलोमीटर दूरी तक के इलाकों में भी कचर घर पानी लग गया है। सोनातालवाब इलाके की गलियों व सड़कों पर नाला का पानी भर गया है। जिला प्रशासन के अफसरों के अनुसार गंगा और वरुणा की बाढ़ से 41 गांव व शहर के 17 मोहल्ले घिर गये हैं। इनमें रहने वाले 30 हजार 921 लोग प्रभावित हुए हैं। इनके लिए शहर से लेकर गांव तक 21 बाढ़ चौकिया व राहत शिविर बनाये गये हैं। वहां दो हजार, 848 लोगों ने शरण ली है।

मुरादाबाद: डिवाइडर से टकराकर डबल डेकर बस खाई में पलटी, 20 यात्री घायल

मुरादाबाद (एजेंसी) मुरादाबाद शानाक्षेत्र में मंगलवार की देर रात को दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबल डेकर बस खाई में पलट गई। हादसे में 20 लोग घायल हैं, जिनमें दस लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में करीब 100 से अधिक लोग सवार थे। इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर अधिकारियों मौके पर पहुंचकर पाँड़ितो वधासमभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी नवाब सिंह के मुताबिक, डबल डेकर बस मंगलवार की रात को सीतापुर से पनौत जा रही थी।

इसमें करीब 130 सवारों थे। बस रामपुर से निकलकर मुहण्डा क्षेत्र में मिहोरा बाजे गांव के पास पहुंची थी, तभी अचानक बस किसी बहाने से टकराने के बाद डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और अनियंत्रित बस दूसरी साइड में जाकर खाई में पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में चीख फकार मच गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव का कार्य करते हुए पावलों को खुल्लेम के जरिये रामपुर और मुरादाबाद भेजा गया है।

घायलों में 10 की हालत गंभीर है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में मोनू, अनिल, रामोतार, सौरभ, मनोज, पूजा, प्रतीक, शादव, रूपरानी, योगिता, मालती व रामसेवक को भर्ती कराया गया है। मौओ इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि घायलों का जिला अस्पताल में बेहतर इलाज कराया जा रहा है।

लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में महिलाओं को मिलेगी विशेष छूट

लखनऊ (एजेंसी) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में महिलाओं को 15 से 24 अगस्त के बीच सफर करने पर पांच प्रतिशत की विशेष छूट (कैशबैक) देगा। यह छूट महिला यात्रियों के उसी खाते में आएगा जिसमें टिकट बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के मुताबिक, महिला यात्रियों को 15 अगस्त से 24 अगस्त तक तेजस एक्सप्रेस में वाजा करने पर पांच प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। तेजस एक्सप्रेस पहले से ही यात्रियों की कई तरह की नई सेवाएं उल्लेख कर रहा है। तेजस में थाने के दौरान यदि किसी यात्री का जन्मदिन होगा तो आईआरसीटीसी की ओर से ट्रेन में ही केक काटा जाता है। साथ ही



लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच चार घंटों के बाद रात सात अगस्त से तेजस एक्सप्रेस का दोबारा संचालन शुरू हुआ है। आईआरसीटीसी ने अब खाद्यपान के व्यवहार पर महिला यात्रियों को आकर्षित करने के लिए किए गए पांच प्रतिशत की विशेष छूट की पेशकश की है। यह छूट महिला यात्रियों को तेजस एक्सप्रेस के चयनकार और एजीकाउंटिन दोनों ही बराम में सफर के लिए मिलेगा। कैशबैक टिकट बनने के बाद उसी क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कल: कल: जिनमें टिकट के बिना का भुगतान किया जाएगा। आईआरसीटीसी के मुख्य श्रेयच प्रबंधक अनंजित कुमार मिश्रा ने बताया कि तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों की सख्ता में लगातार बढोतरी हो रही है। ऐसे में महिला यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने यह खास पेशकश की है।

प्रदेश में फिर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बदलाव, अब 31 अगस्त से होगी शुरू

लखनऊ (एजेंसी) यूपी में पॉलिटेक्निक की परीक्षा करने वाली ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने फिर एक बार प्रवेश परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है। इस बार परीक्षा की तिथि अगले न बदलाने और पहले की गयी है। पहले 09 से 14 सितम्बर तक होने थी लेकिन अब इसे 31 अगस्त से 04 सितम्बर तक करने का फैसला किया गया है। परीक्षा का कार्यक्रम संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। प्राप्ती संचित राग रान ने बुधवार को बताया कि यह बदलाव शैक्षणिक सत्र नियमित करने के लिए किया गया है। इस बार प्रवेश परीक्षा तीन पाठ्यवर्गों में सुबह 8:00 से 10:30 तक, दोपहर 12:00 से 2:30 तक और शाम 4:00 से 6:30 बजे तक पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। 31 अगस्त, एक व दो सितम्बर को रफ ए की परीक्षा होगी। तीन सितम्बर को ई-1 रफ, चार सितम्बर को पहले वाली में ई-2 रफ, दूसरी वाली में बी, सी, डी, एफ जी, एच व आई रफ और तीसरी वाली में के रफ की परीक्षा होगी।

लड़के का यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उमकैद

मुजफ्फरनगर (एजेंसी) उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पोक्सो अदालत ने एक लड़के का यौन उत्पीड़न और फिर उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को उमकैद की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत की विशेष सचवाधीश मुमताज अली ने दोषी मोनु पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी को जुर्माने की आधी राशि 11 वर्षीय लड़के के पिता को देने का निर्देश दिया है। यह घटना 13 अगस्त 2020 की है, जब मोनु ने लड़के का यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या दवाकर हत्या कर दी थी।

आमचीर ने किसान सम्मान निधि का लाभ न लेने का फैसला किया। उनके इस फैसले पर परिवार ने भी सहमति दी जिसके बाद मंगलवार को आमचीर सदर तहसील में एसडीएम प्रशांत निवासी से मिले। इस दौरान उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर किसान सम्मान निधि का पैसा वापस लेने के साथ ही लाभ की सूची से नाम हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। एसडीएम सदर प्रशांत निवासी ने बताया कि शिक्षक पद पर चयन होने के बाद आमचीर ने किसान सम्मान निधि का लाभ न लेने का फैसला किया है। उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर लाभार्थियों की सूची से नाम हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। मोदी ने की 'प्रधानमंत्री ग्रोव कल्याण अन्न योजना' के लाभार्थियों से बात

लिए, बीते वर्ष आवेदन किया था। परीक्षा में पास होने के साथ ही उनका शिक्षक पद के लिए चयन भी हो गया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक बीधा खेती है। पिता जयवीर सिंह उस एक बीधा खेती में आमचीर को काम करते हैं, साथ ही मेहनत मजदूरी करके दो छोटे भाई उदयवीर और अशोक सिंह को पढ़ाई की फीस भी दी जाती है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था।

इस योजना का प्रथम चरण से ही आमचीर को लाभ मिल रहा था। पिता का बैंक खाता न होने के कारण उन्होंने बेटे का खाता नंबर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए दिया था। लेकिन बीते मास शिक्षक पद पर चयन होने के बाद

सम्पादकीय...

ओपन सर्व

अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात और भारत

दुनिया में लगता है शांति संभव नहीं है। गोबखेल स्तर पर युद्ध की अशांति फैली हुई है। बुद्ध का रस्ता कहीं नहीं दिख रहा है। शॉकशाली स्थितियाँ निर्बलन को कमजोर बना रही हैं। दुनिया की सारी शक्तियाँ कुछ देशों के साथ मिश्रित कर रह गई हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी संस्थाएँ बेमसलब साबित हो रही हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में अशांति फैली है। तालिबान की वजह से लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को बाध्य हैं। हजारों की संख्या में रोज पलायन हो रहा है। तालिबान निर्दोश लोगों का कलहाम कर रहा है। जिसमें सेना, शिक्षाविद, पत्रकार, साहित्यकार और दूसरे तमाम लोग शामिल हैं। हजारों निर्दोश बच्चे में शौदे हो चुके हैं। अफगानिस्तान जैसा संघर्ष मुल्क अशांत है। दुनिया सात लेकर इस युद्ध को देख रही है। फिलिस्तीन और इजरायल की तरह युद्ध में बेगुनाह और बेजुबान लोग मारे जा रहे हैं। मानवीय अधिकारों का खूना इनन हो रहा है।

तालिबान दुनिया के शॉकशाली देशों को चुनौती दे रहा है। जबकि तालिबानी जिहादियों को भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खद-पानी दे रहा है। अफगानिस्तान में कब शांति लौटेंगी अपने आप में यह बड़ा सवाल है। गुप्तों में विभाजित वैश्विक शक्तियाँ जानबूझकर इस खेल पर मौन हैं। अफगानिस्तान में विपद्शी स्थितियों को लेकर रुस ने चिंता जारित की है। शुभ संकेत मिले है कि इस मसले पर अमेरिका, चीन और रुस के साथ

अफगानिस्तान जैसा संघर्ष मुल्क अशांत है। दुनिया शांत लेकर इस युद्ध को देख रही है। फिलिस्तीन और इजरायल की तरह युद्ध में बेगुनाह और बेजुबान लोग मारे जा रहे हैं। मानवीय अधिकारों का खूला हनन हो रहा है। तालिबान दुनिया के शॉकशाली देशों को चुनौती दे रहा है। जबकि तालिबानी जिहादियों को भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खद-पानी दे रहा है। अफगानिस्तान में कब शांति लौटेंगी अपने आप में यह बड़ा सवाल है।

पाकिस्तान को एक बैक करार में लेनी है। जिसमें अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार किया जाएगा। हालांकि इस बैक में भारत को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि रुस की निगाह में तालिबान पर भारत का कोई असर नहीं है। इस बैक में जहाँ देशों को शामिल किया गया है तो दक्षिण एशिया के देशों पर अपना-अपना प्रभाव रखते हैं। हालांकि अफगानिस्तान के कई इलाकों पर तालिबानी लड़कों द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। समझते हैं अगर कोई हल निकलता भी जाता है तो इसके बावजूद अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगी।

क्योंकि तालिबान जितनी जमीन पर कब्जा बना लेगा उसे वह छोड़ना नहीं चाहेगा। जिसकी वजह से अफगानिस्तान और तालिबान के बीच संघर्षों में हमेशा तनाव बना रहेगा। पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों को खुलेआम मिलिटी ट्रेनिंग दी जा रही है। वह बात चीन, रुस और अमेरिका का

अच्छे तरह मालूम है। इसके बावजूद तीनों महाशक्तियों ने चुपेी साथ रखी है। क्योंकि वह चाहती हैं कि दक्षिण एशिया में अशांति का माहौल बना रहे। पाकिस्तान आतंकी को नसरे पैदा करता रहे। कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर आतंकवाद फलता-फूलता रहे। अफगानिस्तान में तालिबान अपना काम करता रहे। अगर दक्षिण एशिया में शांति रहेगी तो बिच महाशक्तियों को कौन पड़ेगा। कैसे अमेरिका, रुस, फ्रांस और चीन का रैकब कारोबार चलेगा। उनकी पावरफुलनेस, युद्धपैत, रदार, युद्धक विमान और आधुनिक हथियार कौन खरीदेगा। अपनी दावापिपी कायम करने के लिए विश्व की शक्तियाँ शांति का कपी समर्थन नहीं करना चाहती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ जितनी मजबूत होगी, भारत के लिए उना खतरा बढ़ेगा। अफगानिस्तान भारत का समर्थक रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए कई बिलियन डॉलर का निवेश किया है। अफगानिस्तान में भारत की सक्रियता तालिबान को नहीं पसंदी। पाकिस्तान का आका चीन भी भारत के इस सहयोग से जलता है।

क्योंकि पाकिस्तान में उसकी दल गल जाती है लेकिन अफगानिस्तान में उसकी एक भी नहीं चलती। अफगानिस्तान अमेरिका और भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती है। जिसकी वजह से पाकिस्तान और तालिबानियों को मिचो लगती है। तालिबान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। वह कहूँ इस्लामिक संस्कृति का समर्थक है। जबकि कुछ इस्लामिक मुल्क इसकी उपाजत नहीं देते, जिसकी वजह से वह अलग-बलग पड़ जाता है। शांति के प्रतीक भावना युद्ध की अनर्गलत मूर्तियों को तालिबान दहा चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान अगर मजबूत हो गया तो चीन पाकिस्तान की मदद से भारत को अस्थिर करने का जान बुझा। क्योंकि दक्षिण एशिया में चीन सिर्फ भारत से डरता है। हाल के दिनों में नेपाल से भी भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। वहाँ चीन की दखलअंदाजी बढ़ी है। जिसकी वजह से यह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दक्षिणी अफगानिस्तान के हेलाद राज्य के लश्कर गढ़ा और कंधार के जिलों में तालिबानी और अफगानिस्तान के सैन्य बलों के बीच बमासान मचा है।

भरत झुनझुनवाला

मेरे समेत तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना रहा है कि देश के आर्थिक विकास के लिए हम बुनियादी संरचना को सही करना होगा, जैसे हाईवे, बिजुल, इंटरनेट इत्यादि को। सड़क सही नहीं होती है तो व्यापार नहीं फलता है। अर्थव्यवस्था में पाया गया है कि ग्राम विकास के लिए सबसे अधिक प्रभावी निवेश पक्की सड़क में होता है। सड़क उपलब्ध हो जाने से गांव के लोग अपने माल को आसानी से शहर तक ले जाकर बेच सकते हैं और गांव का विकास होने लगता है। वर्तमान एनडीए सरकार ने बुनियादी संरचना में निवेश में भारी प्राप्ति की है, विशेषकर हाईवे और जलमार्ग में।

सरकार के गुनी निवेश में बुनियादी संरचना प्रमुख हिस्सा होता है। पिछले वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने 4.39 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया था जो वर्तमान वर्ष 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इसमें 29 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई है। फिर प्रश्न उठता है कि बुनियादी संरचना में इतने निवेश के बावजूद एनडीए सरकार के हैं पिछले 6 वर्षों में हमारी आर्थिक विकास दर लगातार गिर क्यों रही है? इसका कारण संभवतः यह है कि हम गलत बुनियादी संरचना में निवेश कर रहे हैं, जैसे मरीज को दवा देना जरूरी होता है, लेकिन गलत दवा देने में नुकसान हो जाता है। वह बात में आपके सामने कुछ उदाहरणों से रखना चाहता हूँ। पहला उदाहरण शहर में फुटओवर ब्रिज का लो। चौगहे पर पैदल यात्रियों के लिए फुटओवर ब्रिज बना दिया जाता है। इससे आम आदमी को सड़क पार करने में समय अधिक लगता है। ऊपर चढ़ने और उतरने में उसकी ऊर्जा व्यय होती है, जबकि नीचे कर के सरफ्ट भागने और लाल बत्ती के हटए जाने से उच्च वर्ग को आसानी होती है। वह अपने गंतय स्थान पर शीघ्र पहुंच सकते हैं। हा, आम आदमी के जीवन को रक्षा होती है और उच्च वर्ग को दुर्घटना से बचाने में मदद भी मिलती

है। लेकिन अंत में आम आदमी पर फुटओवर ब्रिज का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि उच्च वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका उपाय यह है कि फुटओवर ब्रिज के साथ स्वचालित एस्केलेटर लगाया जाए जिससे कि आम आदमी के समय की बर्बादी न हो और एस्केलेटर चलाने का खर्च नीचे दौड़ने वाली

वाले माल का दुवाई खर्च कम हो जाता है। लेकिन ट्रक पर दुवाई किए जाने वाले माल को खपत में अनुमान से 80 प्रतिशत उच्च वर्ग द्वारा ही को जाती है। साथ-साथ हाईवे बनाने में जो सीमेंट, स्टील और मशीन का उपयोग किया जाता है, वह भी बड़े कंपनियां ही सप्लाई करती हैं। हाईवे का अंतिम परिणाम आम

उसकी भरपाई करने की अच्छी सड़क में हो जाए। तीसरा उदाहरण जलमार्ग का लीजिए। जलमार्ग बनाने से नदी पर बड़े जहाज चलने लगते हैं और मछुआरों का धंधा समाप्तप्राय हो जाता है। छोटें नाविक का धंधा भी कमजोर पड़ जाता है। इसके विपरीत जलमार्ग से कांवल आदि माल को दुवाई को लागत कम हो जाती



कार में बसल किया जाए। दूसरा उदाहरण हाईवे का लो। हाईवे पर गाड़ी बिना व्यवधान के दौड़ सके, इसलिए दोनों तरफ तार लगा दिए जाते हैं। हाईवे के एक तरफ खड़े वाले को हाईवे के दूसरी तरफ अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए अब 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, क्योंकि ट्रैक्टर को हाईवे पार करना अब संभव नहीं रह गया है।

इसलिए हाईवे में किसान की लागत बढ़ जाती है। इसके विपरीत हाईवे पर चलने वाले ट्रक को सुविधा होती है। ट्रक पर दोर जाने

आदमी पर नकारात्मक पड़ता है। इतना अवश्य है कि उसके द्वारा भी बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं के दाम में गिरावट आती है। लेकिन बाजार से आम आदमी माल कम खरीदता है और उच्च वर्ग ज्यादा। इसलिए उच्च वर्ग को विशेष लाभ होता है। इसका उपाय यह है कि हाईवे बनाने के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों पर भी भारी निवेश किया जाए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों एव कस्बों में आम आदमी के लिए भी कार्य करना लाभप्रद हो जाए। हाईवे बनाने में उसे जो नुकसान होता है,

है। कोचले से उत्पादित बिजली की भी लागत कम हो जाती है। लेकिन उस बिजली की खपत भी एलुमिनियम जैसे वस्तुओं और बड़े शहरों में एयर कंडीशनर इत्यादि उपकरणों को चलाने में अधिक होती है। इस प्रकार जलमार्ग का मछुआरों और नाविकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि उच्च वर्ग को सस्ती बिजली और सस्ते माल की उपलब्धि होने से लाभ होता है। इसका विकल्प यह है कि जलमार्ग के स्थान पर रेल मार्ग में दुलाई की जाए जिससे आम आदमी पर दुष्प्रभाव कम

पड़े। चौथा उदाहरण खनिज के खनन का लो। आज तमाम खनिज खनन जगहों के नीचे दबे पड़े हैं। इनके निकालने के लिए उनके ऊपर के जंगलों को काटा जाता है। इससे स्थानीय लोगों को मछुा के फूल, चिरई के वने, तेंदुए की पत्ती, मसुओं का चारा इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हैं। आम आदमी को आय में गिरावट आती है। खदान में जो खनिज निकाले जाते हैं लोहा, एलुमिनियम अथवा ताम्र इत्यादि जो मान बनाया जाता है, उसको खपत भी उच्च वर्ग ही ज्यादा करते हैं। अंतिम परिणाम आम आदमी के लिए नकारात्मक और उच्च वर्ग के लिए सकारात्मक होता है। इसका उपाय यह है कि जंगल काटने से पहले आम आदमी को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और खदान करने के बाद उस भूमि पर पुनः जंगल को लगाया जाए। अब आम आदमी पर मछुा, चिरई, तेंदु पत्त इत्यादि के समाप्त होने से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भरपाई हो जाएगी।

पांचवां उदाहरण 5जी इंटरनेट का लो। आम आदमी के लिए 4जी पर्याप्त है। उसके बच्चे को ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित होना होता है अथवा उसे बंगाल के शहर में फसल के मूल्य की जानकारी को जरूरत होती है। लेकिन 5जी इंटरनेट से भारी मात्रा में सुचना का आदान-प्रदान आसान हो जाता है। जैसे डाटा एनालिसिस करने वालों का कार्य सुचारु हो जाता है। अतः 5जी इंटरनेट से उच्च वर्ग को अधिक लाभ होता है।

इसका विकल्प यह है कि 5जी के साथ-साथ 4जी इंटरनेट की सुविधा को सबको उपलब्ध कराया जाए और आम आदमी को मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराया जाए। मात्र बुनियादी संरचना में निवेश करना पर्याप्त नहीं होता है, जिस प्रकार केवल दवा देना रोगी के उपचार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। सही संरचना बनानी होगी और सही दवा देनी होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि बुनियादी संरचना के खोफसे बचे। उच्च वर्गीय बुनियादी संरचना में निवेश करने से देश की आर्थिक विकास दर लगातार गिर रही है।

किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

एक तरफ दिखे सीमा पर किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ सरकार किसानों की आय बढ़ाने के कदम उठा रही है। अब तो लगता है कि यह आंदोलन किसानों के विरोध में है। आंदोलन के नेताओं को छोटे व गरीब किसानों की कोई निति नहीं है। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग चल रही है। इनके द्वारा कानूनों को कानून बनाया जा रहा है। यह बात अलग है कि आंदोलन के नेता आन तक यह स्पष्ट नहीं कर सके कि इन कानूनों में काला काा है। इन्होंने तब भी नहीं बताया कि इन कानूनों के पहले तत्कालीन सरकारें कृषि मंत्री ने कितनी खरीद करती थीं।

जो सरकारों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि की थी। वर्तमान सरकार ने आंदोलन के नेताओं के कहान बरवा की लेकिन इन नेताओं ने समाधान में हाथ नहीं दिखाई। जबकि सरकार कृषि व किसान कल्याण के अपने एजेंडे को आगे बढ़ रही है। इस आंदोलन को समर्थन देने ट्रैक्टर से सड़क तक बाधा की गई। जंगर पंजर तक लड़े लगाई गईं। लेकिन इनमें से किसी नेता ने यह नहीं बताया कि उनकी सहा। साहेब खरोड़ भरवाई हुई। जबकि उस समय वे तीन कृषि कानून नहीं थे। फलतः में कृषि मंत्रियों से किसी ना किसी रूप में जुड़े लोगों की नाजगी सीमझ में आती है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की अस्सी प्रतिशत कृषि उाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है। इस व्यवस्था में विचौलिया होने थे। उनको कमिशन देना होता था। नई व्यवस्था से उनकी दुकान बंद हुई है। देश में पहले तीन चार प्रतिशत तक ही किसानों

का अनाज न्यूनतम समर्थन पर खरीद जाला था। ऐसे में अन्य प्रदेशों में आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था। यहां के किसानों को तो बाजार विकल्प दिया गया है। इस तथ्य को गैर भाजपा सरकारों व विपक्षी दल समझने में असमर्थ रहे हैं। उन्होंने केवल इतना देखा कि आंदोलन केन्द्र को मोदी सरकार के विरुद्ध है वे आंदोलन को समर्थन देने लगे। इसमें से किसी नेता ने यह नहीं बताया कि कृषि कानून से उनके प्रदेश के किसानों को क्या लाभ नुकसान होगा। कांग्रेस नेताओं ने पहले कहा था कि पूरी जमीन पर पुंजीपतियों के कब्जा हो जाएगा। यही अन्य क्षेत्रों पाटिया भी देहरादून लगी। यह नागरिकता संशोधन कानून जैसा ही विरोध है। तब कांग्रेस ने कहा था कि इस कानून में वर्ग विरोध की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसी तर्ज पर कहा जा रहा है कि कृषि कानून से किसान को जमीन छीन ली जाएगी। कृषि कानूनों में जमीन की बात ही नहीं है। कॉन्स्टीट्यूट कौल फलतः का हाना है। यह भी वैकल्पिक है। इस राजनीति ने पाज्जा को अवसर प्रदान किया। बसने अपने कार्यकाल में हुए किसान कल्याण कागो का खोरा दिया। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय दलों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। साहेब खरोड़ किसानों के जैडिट कार्ड है। तीन करोड़ किसानों को जैडिट कार्ड और दिया जाना है। इससे किसानों को जैडिट कार्ड और दिया जाना है। समाज कर्मी के रूप में उसकी हजार करोड़ रुपया का निवेश किया गया। कृषि इंड्रस्ट्रिकर के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छोटी अरबों के लिए किसानों को आत लाख करोड़ का ऋण दिया गया है। इस पद्धत लाख करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। नाबाई अबतक कृषि क्षेत्र में नब्बे हजार करोड़ रुपये

खर्च करता था। अब उसके खर्च का बजट तीस हजार करोड़ और बढ़ दिया गया है। गहूं खरीद की मात्रा घटोए सरकार के समय दस वर्ष पहले के मुकाबले वर्तमान वर्ष एक सौ सतर प्रतिशत तक हो गई। दस वर्ष पहले गेहूं खरीद करीब सवा दो सौ लाख मॉट्रिक टन थी। इस वर्ष करीब तीन सौ नितानबे लाख मॉट्रिक टन हो गया। घूरोए में गेहूं में अधिकतम पचास रुपए की बढ़ोतरी एप्रैप्रसी में की गई, जबकि मोदी सरकार ने वर्ष दो वर्ष पहले इससे दुगुनी से अधिक की बढ़ोतरी की थी। यह फिले आठ वर्षों का अधिकतम बढ़ोतरी का रिकॉर्ड था। धन खरीद में दस वर्ष पहले घूरोए के मुकाबले डेढ़ सौ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। दलों की खरीद मोदी सरकार के समय रुए हुई। पिछली सरकारों के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य तो घोषित होता था। लेकिन एप्रैप्रसी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। किसानों के नाम पर बड़े-बड़े कर्ज माफ़े के पैकज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक यह पहुंचते ही नहीं थे। पहले अवसर प्रदान किया। बसने अपने कार्यकाल में हुए किसान कल्याण कागो का खोरा दिया। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय दलों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। साहेब खरोड़ किसानों के जैडिट कार्ड है। तीन करोड़ किसानों को जैडिट कार्ड और दिया जाना है। समाज कर्मी के रूप में उसकी हजार करोड़ रुपया का निवेश किया गया। कृषि इंड्रस्ट्रिकर के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छोटी अरबों के लिए किसानों को आत लाख करोड़ का ऋण दिया गया है। इस पद्धत लाख करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। नाबाई अबतक कृषि क्षेत्र में नब्बे हजार करोड़ रुपये

कोई पुराने मिस्टर से ही लेनेदरन ट्रैक समझता है तो उसपर भी एक लगाई नहीं लगाई गई है। स्वामीनाथन रिपोर्ट घूरोए के समय आ रड थी। लेकिन उसने इसे लागू नहीं किया। नेंद मोदी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया है। अब गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ भंडारा, कोल्हटन हो गया। घूरोए में गेहूं में अधिकतम पचास रुपए की बढ़ोतरी एप्रैप्रसी में की गई, जबकि मोदी सरकार ने वर्ष दो वर्ष पहले इससे दुगुनी से अधिक की बढ़ोतरी की थी। यह फिले आठ वर्षों का अधिकतम बढ़ोतरी का रिकॉर्ड था। धन खरीद में दस वर्ष पहले घूरोए के मुकाबले डेढ़ सौ प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई। दलों की खरीद मोदी सरकार के समय रुए हुई। पिछली सरकारों के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य तो घोषित होता था। लेकिन एप्रैप्रसी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। किसानों के नाम पर बड़े-बड़े कर्ज माफ़े के पैकज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक यह पहुंचते ही नहीं थे। पहले अवसर प्रदान किया। बसने अपने कार्यकाल में हुए किसान कल्याण कागो का खोरा दिया। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य क्षेत्रीय दलों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। साहेब खरोड़ किसानों के जैडिट कार्ड है। तीन करोड़ किसानों को जैडिट कार्ड और दिया जाना है। समाज कर्मी के रूप में उसकी हजार करोड़ रुपया का निवेश किया गया है। छोटी अरबों के लिए किसानों को आत लाख करोड़ का ऋण दिया गया है। इस पद्धत लाख करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। नाबाई अबतक कृषि क्षेत्र में नब्बे हजार करोड़ रुपये

के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। उस आग्रह को देश के किसानों ने स्वीकार किया। परिणाम यह हुआ कि बोटे छह साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग पचास प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने खरीफव रबी सीजन, किसानों से एम एम पी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे, धान किसानों के खाते में लगभग एक लाख सतर हजार करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग पच्चासी हजार करोड़ रुपए खरोबर पहुंचने हैं। जैविक उत्पादों की मांग बढ़े है। महागरी के दौरान किसानों ने रिकॉर्डे उत्पादन किया है। मिशन हनी बी के तहत सात सौ करोड़ रुपए मूल्य के सहद का निर्यात किया गया है। जामू और कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध केसर की मांग बढ़ी है।

नेंद मोदी ने कहा कि डीएपी का मूल्य बढ़ने पर राज्य सरकार द्वारा सहस्रों की रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी दी गई जिससे डीएपी के मूल्य नियंत्रित हैं। किसानों को पर्याप्त लाभ हो जाय और बीज उपलब्ध करवा जा रहे हैं। उनका उत्पादन बढ़ने के लिए उन्हें नई तकनीकों से जोड़ जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दो करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को किसान जैडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें कोरोना संकेत के दौरान लॉक डाइल नहीं हुई। इस मिशन के माध्यम से खाते के तल से जुड़े इकोसिस्टम पर ग्यारह हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ने सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उतम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी आदि सब कुछ प्राप्त हो सके। लेकिन अब छोटे दलों की बहुत कमी हो गई थी। तब उन्होंने देश

लौटने लगे हैं भारतीय हॉकी के पुराने दिन ?

योगेश कुमार गोयल

दोबो ओलम्पिक का समापन हो चुका है। लेकिन हर भारतीय इस ओलंपिक को भारतीय हॉकी के पुनर्जन्म के रूप में रेखांकित करेगा। जिसमें भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों का सूखा खत्म कर भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। जिस प्रकर दस घंटे काटने में 3-1 से पिछड़ने के बाद टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए जर्मनी की मजबूत टीम को 5-4 से मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया, उसके लिए हमारे हॉकी खिलाड़ियों की जितनी सराहना की जाए, उतनी ही सही। दरअसल जर्मनी को हॉकी टीम अपने आक्रमक खेल के लिए जानी जाती है और हमारे खिलाड़ियों ने न केवल उसके आक्रमक का बखूबी जाबाब दिया बल्कि अक्सर मिलते ही गोल करने में भी नहीं चूकें।

कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत की श्रुति दस्ता जर्मनी के मुकाबले बेहतर रही। भारत के खिलाड़ियों की यह करीब 45 अंशरी तो जर्मनी के खिलाड़ियों की ओर में पहज 17 फीसदी रही। शुरूआती मैच न्यूजीलैंड से जीतने के बाद टीम पहले तो आस्ट्रेलिया से हार गई थी लेकिन वह फुल से आगे बढ़कर अपने खुद इरादों के बूते सेमीफाइनल तक पहुंची। वैसे इसका भारत की दोनों हॉकी टीम जिस जोश और ऊर्जा के साथ खेल रही थी, उससे दोनों से पटक जीतने की उम्मीद शुरू से ही थी। विश्व हॉकी की केंद्रों में आखिरी से जोष स्थान पर आने वाली पुरुष टीम ओलंपिक के लिए इंग्लैंड आई। इसके बाद अपने सभी मुकाबलों में जिस प्रकार दुनिया की मजबूत मानी जाने वाली टीमें के खिलाफ भी पूरे जोश के साथ सफलतापूर्वक लड़ी, उससे आस बंधी थी कि यह टीम

ओलंपिक में भारत का लंबा सूखा खत्म करने में अवश्य सफल होगी। भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक मिलाना भी इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी ओलंपिक खेलों में हॉकी का सिस्पी रहा भारत 41 वर्षों बाद ओलंपिक में जीत का स्वाद चख सक्ता है। भारतीय हॉकी के भविष्य से निराश हो चुके देश के युवाओं में इस जीत में जो नई आशा जागूई है, उस देखते हुए ही दोबो ओलंपिक में मिले कांस्य पदक को स्वर्ण से कम नहीं माना जा रहा। भारत की हॉकी की महिला और पुरुष, दोनों ही टीमों इस बार सेमीफाइनल में पहुंची और 6 अगल की हुए कांस्य पदक के मुकाबले में महिला हॉकी टीम पहले ही खिले में हार गई लेकिन ओलंपिक में अपने सभी मैचों में इस टीम ने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया, उसकी बदौलत ओलंपिक में हारकर भी इसने तमाम भारतवासियों का दिल जीत लिया। महिला हॉकी टीम इसमें पहले केवल दो बार ही ओलंपिक में खेली है। 1980 में ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल फीट नहीं था, तब टीम शीर्ष-4 में पहुंची थी जबकि दूसरी बार 2012 रियो के ओलंपिक में 12वें स्थान पर रही थी लेकिन इस बार महिला टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। महिला टीम पहले ही हार गई और पुरुष टीम कांस्य ही जीत सकी। फिर अगर ओलंपिक में भारत के इस प्रदर्शन को गौरवान्वित करने जाला माना खा है तो इसका कारण निम्नलिखित सभ है। दरअसल हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी में हमारा गौरव कहीं छोटा गया था, जो 41 वर्षों के बेहद लंबे अंतराल के बाद पुनः हासिल करने का अवसर मिला है। 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय टीम ओलंपिक में कभी भी पॉवरवंत स्थान से ऊपर नहीं जा सकी थी। कभी उसे 7वें तो कभी 8वें



और 12वें स्थान से भी संतोष करना पड़ और 2008 में तो वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सकी थी। एक समय था, जब हमारे हॉकी टीम विश्व चैंपियन थी लेकिन लंबे समय से भारत अपने इसी खेल में एक पदक नहीं के लिए भी तयस रहा था। आज यह एक दिवाखन जैसा ही लगता है कि भारत ने हर चार वर्ष के अंतराल पर होने वाले ओलंपिक खेलों में 1928 से लेकर 1956 तक लगातार छह बार स्वर्ण पदक जीते थे। अभीतक भारत हॉकी टीम ने कुल 8 स्वर्ण, 1 खत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में स्वर्ण, 1960 में खत और 1968, 1972 तथा 2020 के दोबो ओलंपिक में कांस्य पदक होने टीम ने जीते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी के स्पर्धामं शुा की शुरूआत हुई थी, जब भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद की कालानी में टीम ने पांच मैचों में बिना एक भी गोल खाए कुल 29 गोल करते हुए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 14 गोल दगे थे। 1932 के लॉस

एंजिल्स और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भी ध्यानचंद के ही नेतृत्व में भारत स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुआ। 1932 के ओलंपिक में ध्यानचंद ने 12 और 1936 के अपने आखिरी ओलंपिक में 13 गोल दगे थे। इस प्रकार तीन ओलंपिक में उन्होंने कुल 39 गोल किए थे। उसी के बाद से ही मेजर ध्यानचंद को 'हॉकी का जादूगर' कहा जाने लगा था। दरअसल उसने बंद में माना जाने लगा था कि गैर उन्सी हॉकी खिलाड़ियों को देखे बिना जीत ली, जैसे उस पर ओसी लगा हो। 1948 के ओलंपिक में बल्लबीर सिंह सोनियर के नेतृत्व में भारत ने फिर स्वर्ण पदक जीता और खर्षिम जीत का यह सिलसिला 1952 तथा 1956 के ओलंपिक में भी बरकरार रहा। 1960 के रोम ओलंपिक में भारत को खत से ही संतोष करना पड़ लेकिन 1964 के टोक्यो ओलंपिक में अपने 7वें स्वर्ण पदक के साथ भारतीय टीम हॉकी के विश्वर पर पहुंच गई। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में भारत को 16 वर्ष बाद स्वर्ण पदक मिला। उस ओलंपिक में सुरेश सिंह सोनो ने कुल 15 गोल दगकर मेजर ध्यानचंद के सर्वाधिक गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। यह अतक किसी भारतीय हॉकी खिलाड़ी द्वारा एक ओलंपिक में किए गए सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक पुणर जीतने में ही जीते हैं लेकिन 1980 के बाद से भारत ओलंपिक में हॉकी में जीत के लिए

तयस रहा था। ऐसे में इस सवाल को पड़ताल जरूरी है कि जो भारत दशकों तक हॉकी चैंपियन रहा, उसकी अपने इसी राष्ट्रीय खेल में इतनी बरीबें हुई? जिस हॉकी की बदौलत भारत बड़ी शान से दुनिया को दिखा रहा था। इस प्रकार तब, आखिर क्या कारण रहे कि उसी हॉकी में पदक जीतना तो दूर की बात, भारत की सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए भी नाइरक लंबा इंतजार करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण तो रहीं कि वह कि जिन लोगों ने स्वर्ण कभी हॉकी में बड़ा कमाल नहीं किया, बरसों तक जूरी के हाथों में भारतीय हॉकी की कमजोरी रही। खिलाड़ियों के चयन के मामले में भारी-भारीकाद की बात हो या ध्यानचंद और रिश्ताखोरी अथवा नीतियों के निर्धारण की, भारतीय हॉकी संघ पर काबिज ऐसे ही मजबूतीश ने हॉकी का नेड र्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

भारत में क्रिकेट की चमकौरी ने भी हॉकी जैसे परम्परागत खेलों को खस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने खेल मैदानों से लेकर नियमों तक में अपने अनुकूल जिस प्रकार के परिवर्तन समय-समय पर किए हैं, उनके कारण भी भारतीय हॉकी कुलान पर आई। बावतवाल, हॉकी में बरसों बाद मिली जीत के पश्चात देश में हॉकी के पुनरुत्थान की आस जगने है और निश्चित रूप से वह देश में हॉकी के बेहतर भविष्य की उमीद करता है। ऐसे में जीत के इस उत्साह को बरकरार रखते हुए जरूरत अब इस बात की है कि देश में हॉकी तथा अन्य खेलों को भी किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए खेलनी या किसी एक सीजन का खेल मानकर चलने की सोच तक सीमित रखने के बजाय मिनटों खेल खड़े की राष्ट्रियों को दूर करते हुए इन्हें समाय का अट्टा आ बनने की और विशेष ध्यान दिया जाए।

सुबह होते ही डल गए झूले, हरियाली तीज पर सजी-धजी नजर आई महिलाएं



हिसार (एजेंसी) सावन के महीने में हरियाली तीज का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। हरियाली तीज के दिन सब जगह एक अलग ही रौनक होती है। आज हरियाली तीज है और हरियाणा में हर जगह अलग ही माहौल

दिखा रही है। हरियाली तीज पर कोरोग काल होने के चलते इस बार बाकी सालों की तुलना में तो रौनक कम है मगर फिर भी त्योहार का माहौल जरूर नजर आया है। सूरुह होते ही गांव शहरों में झूलों पर झूलते बच्चे और महिलाएं नजर आईं। झूल झूलने की लेकर बच्चों में ख़ासा उत्साह देखने को मिला। गांवों में तालाब किनारे पेड़ों पर झूलें खड़े हुए नजर आए। मस्ती का आलम देखते ही बन रहा था। सावन के महीने में भाई अपनी बहन के यहाँ मित्राई और प्यार लेकर जाता है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। इसी महीने में खाबंभन भी आता है। इसलिए इस महीने को भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला माना जाता है। हरियाणा में इस त्योहार को और भी महत्ता है। भाई अपनी बहन के यहाँ प्यार, फ़िरनो, बिस्कुट, मटरी, मटर, पत्र और अन्य तरह के पकवान लेकर जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं नए कपड़े पहन श्रृंगार करती हैं और बच्चे भी नए रंग में नजर आते हैं। शाम के वक़्त फुलपुल और सुहाली को सरसों के तेल में बनाया जाता है।

पीएम मोदी से मिलेंगे पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर, कहा- पाक से बढ़ा खतरा व केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां मिले



चंडीगढ़ (एजेंसी)

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी से मिल सकते हैं। वह प्रधानमंत्री को राज्य की स्थिति और पाकिस्तान की ओर से पंजाब को बढ़ा रहे खतरों के बारे में अवगत करायेंगी। बताया जाता है कि कैप्टन अमरिंदर इस मुलाकात के दौरान पीएम से किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए पहल करने का अनुरोध भी करेंगे।

कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि पंजाब को पाकिस्तान से खतरा बढ़ गया है और कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की राज्य में गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे में राज्य की केंद्रीय बलों की 25 अतिरिक्त कंपनियां दो जाएं। बता दें कि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने कृषि की अंतरिम राष्ट्रीय अस्थाय मॉनिटरिंग गांथी और केंद्रीय जूट मंत्री अमित शाह

से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के दौरान कैप्टन ने मांग की कि पंजाब को केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों की 25 कंपनियां और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को ड्यून नष्ट करने वाले जफ़्तार उरलब्ध कराया जाए। कैप्टन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पाकिस्तान की आइएसआइ एजेंसी की गतिविधियां बढ़ रही हैं।

राज्य में हथियारों, हैंड ग्रेनेड और आइडेंटि की बड़ी स्तर पर घुसपैठ का खतरा बढ़े हुए उन्होंने अमित शाह को बताया कि सुरक्षा की स्थिति बहुत भयानक है। इसे देखते हुए केंद्र को तुरंत दखल देना चाहिए। कैप्टन ने शाह से अमृतसर, जालंधर, जलंधर, मोहाली, पटियाला, बठिंडा, फ़ावाड़ और मोगा के लिए केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों की मांग की। केंद्रीय व प्रांतीय एजेंसियों और

कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलनकारियों पर भारी तिरंगा यात्रा, हरियाणा में क्या हुआ असर

पंचकुला (एजेंसी)

हरियाणा में किसान संगठन पिछले आठ माह से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की अनावश्यक जिद पर अड़े हैं। इन आठ माह में खूब उपद्रव हुए। अराजक एवं हिंसक घटनाओं का अंजाम दिया गया, लेकिन भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकालकर न केवल आंदोलनकारियों के भयंकों पर पानी फेर दिया, बल्कि पूरे प्रदेश में देशभ्रम की लौ जगा दी है। दरअसल केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध करते-करते आंदोलनकारी इतने अराजक हो चुके थे कि उन्होंने मत्तारूढ़ भाजपा और जजपा (जननायक जनता पार्टी) गठबंधन के नेताओं का धरो से निकलना मुश्किल कर दिया था।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्रफेले का बेराब, उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने-प्रदर्शन और मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की गाड़ी पर पथराव इन आंदोलनकारियों के हिंसक होने के प्रमाण हैं। किसान संगठनों के आंदोलन स्थलों पर आए दिन होने वाले अपराध आंदोलनकारियों के अराजक होने की कलनी को बढ़ा रहे हैं। इन सबके बीच हरियाणा के सतारूढ़ दल भाजपा ने पूरे प्रदेश में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का ऐस खका खोसा कि आंदोलनकारियों तो निरुत्तर हुए ही,



साथ ही जनता भी देशभ्रम के रंग में रंगी नजर आने लगी। हरियाणा में इस समय सभी विधानसभा क्षेत्रों में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ की जोड़ी ने आजादी का जयन मनाने तथा शहीदों को सम्मान देने के लिए ये तिरंगा यात्रा शुरू की है, जो 15

अगस्त तक चलेगी। भाजपा सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी इन तिरंगा यात्राओं का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस तरह से किसान संगठनों ने अपने आंदोलन में ट्रैक्टरों को शामिल किया, उसी का जवाब देते हुए भाजपा की तिरंगा यात्राओं में अनर्गल ट्रैक्टर शामिल किए गए हैं। किसान संगठनों के आंदोलन में

खासियत के समर्थन में नारे लिखे झंडे-बैनर थे तो भाजपा की तिरंगा यात्राओं में भारत माता की जय लिखे नारे हैं। हरियाणा सरकार यदि चाहती तो इन किसान संगठनों के अराजक भयंकों पर समय रहते शिकजा कर सकती थी, लेकिन प्रदेश सरकार उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्रवाई कर उन्हें पगपने का मौका नहीं देना चाहती थी। सरकार की इस नरमी को किसान संगठनों ने कमजोरी मान लिया।

बावजूद इसके प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को बेरकर उनके प्रति गलत रवैया अपनाने का किसान संगठनों का सिलसिला नहीं थमा। अब भाजपा ने तिरंगा यात्रा के जरिये न केवल प्रदेश भर के लोगों को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भी पूरी सज्जता के साथ फौलड़ में ढाकर दिया है। हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। भाजपा अभी तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुजौर, सांसद मंजव भारिया, धर्मवीर सिंह, नायब सिंह सैनी, रोश कोशिक, सुनील दुमाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, मंत्री अनिल बिज, पंडित मूलचंद शर्मा, संदीप सिंह, कमलेश डांडा, कंवरपाल गुजौर,

सौकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व मंत्री रमबिलास शर्मा और कविता बेंन के नेतृत्व में निकली इन तिरंगा यात्राओं में ऐसा माहौल बना कि आंदोलनकारियों बैकफुट पर आते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल में भी तिरंगा यात्रा निकल चुकी है। भाजपा सांसदों, मंत्रियों और विधायकों द्वारा निकाली जा रही इन यात्राओं का सकारात्मक असर उसके सहयोगी दल जजपा पर भी पड़ा है।

भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सहभागी उप मुख्यमंत्री दुयंत चौटाला लंबे समय से आंदोलनकारियों के निशाने पर चल रहे थे, लेकिन जब से राज्य में तिरंगा यात्रा निकली है और पूरा प्रदेश देशभ्रम के रंग में ओतप्रोत हो गया है, तब से भाजपा को सहयोगी जजपा के विधायकों को भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में गव के साथ सिर उठाकर चलने का मौका मिला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ का कहना है कि किसान संगठनों का आंदोलन अपनी जगह है और तिरंगा यात्राओं का अपना अलग सम्मान है। इसके बावजूद यदि किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर केंद्र से वार्ता करने को तैयार होते हैं तो हम इसके लिए मध्यस्थता करने के लिए आगे आएंगे।

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED				
CIN:L65929DL1985PLC021037				
Regd. Off: R-815 NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI North East DL 110060 IN				
Corporate Off: 47/18, Basement Rajendra Place Metro Station New Delhi-110060				
Email Id- alstonetextiles@gmail.com, Website- www.alstonetextiles.in Ph. 011-25755261				
Unaudited Financial Result for the Quarter Ended 30.06.2021				
₹ IN LACS				
S.N	Particulars	Quarter Ended		
		CURRENT QUARTER	PREVIOUS QUARTER	CORRESPONDING QUARTER
		01.04.2021 to 30.06.2021 (₹)	01.01.2021 to 31.03.2021 (₹)	01.04.2020 to 30.06.2020 (₹)
		Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from operation	-	-	-
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	(0.39)	(2.73)	(4.23)
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional itmes)	(0.39)	(2.73)	(4.23)
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional itmes)	(0.39)	(2.73)	(4.23)
5	Total [Comprehensive income/ loss for the period [comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	(0.39)	(2.73)	-
6	Paid up equity share capital	1,274.80	1,274.80	1,274.80
7	Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in the balance sheet for previous years	11,153.75	11,153.75	11,153.75
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) not Annualised-Basic & Diluted	(0.00)	(0.02)	(0.03)
				(0.15)
Note 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations 2015. the full format of the quarterly unaudited financial result are available on the company's website www.abhijitrading.in and also on the website of BSE Limited i.e www.bseindia.com				
For and on behalf of board of directors of ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED				
Deepak Kumar Bhojak Managing Director DIN: 06933359				

GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED				
CIN: L67190DL1995PLC069768				
Regd. Off: R-815 NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060				
Email Id: genesislimited1995@gmail.com, Website: www.genesisdevelopersholdings.com				
Ph: +91-11-28742357, +91-9891095232				
Unaudited Financial Result for the Quarter Ended 30.06.2021				
₹ IN LACS				
S.N	Particulars	Quarter Ended		
		CURRENT QUARTER	PREVIOUS QUARTER	CORRESPONDING QUARTER
		01.04.2021 to 30.06.2021 (₹)	01.01.2021 to 31.03.2021 (₹)	01.04.2020 to 30.06.2020 (₹)
		Unaudited	Audited	Unaudited
1	Total Income from operation	-	-	-
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	(0.41)	1.19	(0.10)
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional itmes)	(0.41)	1.19	(0.10)
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional itmes)	(0.41)	1.19	(0.10)
5	Total [Comprehensive income/ loss for the period [comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	(0.41)	1.19	(0.10)
6	Paid up equity share capital	816.52	816.52	816.52
7	Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in the balance sheet for previous years	2,790.00	2,790.00	2,790.00
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) not Annualised-Basic & Diluted	(0.00)	(0.01)	(0.00)
				(0.03)
Note 1. The above unaudited standalone financial results for the quarter ended June 30, 2021 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors and taken on record at the meeting held on 11/08/2021.				
Note 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations 2015. the full format of the quarterly unaudited financial result are available on the company's website www.genesisdevelopersholdings.com and also on the website of MSEI Limited i.e www.msei.in				
Date: 11.08.2021 Place: New Delhi				
DEEPAK TYAGI Managing Director DIN: 02760361				

लाहौर जेल में रतिराम को देते थे आधी रोटी, महात्मा गांधी के साथ लाठीचार्ज में हुए शहीद

रोहतक (एजेंसी) ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जन-जन ने भारत आंदोलन छोड़े आंदोलन में साहसीयों की थी। रोहतक में भी अंग्रेजों की क्रांतिकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। रोहतक के बाहर गंव निवासी आजादी दिलाने के लिए सर्वस्य त्यागने वाले रतिराम भी थे। महज 21 साल की उम्र में ही लाहौर (पाकिस्तान) की जेल में अंग्रेजों की यातनाओं का शिकार हुए और शहीद हो गए। अंग्रेजों की ज्वादी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी शहादत के बाद गतो-गत लाहौर में ही शव दफन दिए। इसके विरोध में देशभर से करीब 10 हजार क्रांतिकारियों के अलावा महान्या गांधी भी रोहतक में अनाशन करने आए थे।



और स्वजनों की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दी। 1940 में रोहतक में पहली बार एक साल की सजा मिली। हालांकि सरकार ने तीन माह बाद ही छोड़ दिया। इसके बाद तीन-चार बार ऐसे ही पुलिस पकड़ों और कुछ माह बाद छोड़ देती। उन्हें कहते हैं कि महात्मा गांधी की 1942 में पलकट में आना था। उसी सत्याग्रह में शामिल होने के लिए रतिराम अपने सहयोगियों के साथ चल दिए। पुलिस ने रास्ते में ही सभी को पकड़ लिया और लाहौर जेल में भेज दिया। अंग्रेजों ने सत्याग्रह में शामिल होने वाले सभी क्रांतिकारियों का इतना उपरोध किया कि सुनने वालों की रूढ़ तक कांप जाता। जेल में आधी रोटी, आधा गिलास पानी और सड़ी हुई सब्जी दी जाती। शरीरिक यातनाएं दी जाती। कुछ सलापहरियों की तबियत लगातार बिगड़ने लगी तो रतिराम ने दूसरे साथियों के साथ अनशन शुरू कर

दिया। अंग्रेजों ने विरोध को थामने के लिए क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज करवाना शुरू कर दिया। रतिराम के पैर, सिर और गाल पर ताबड़तोड़ लाठियों बरसाईं और वह वहीं शहीद हो गए। जेल के मुताबिक, लाहौर जेल में उस दौरान पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित नरसिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे चुके गोपीचंद भार्गव, चौधरी देवीलाल के भाई सार राय, चौधरी रणवीर सिंह, चौधरी लहरी सिंह आदि भी जेल में बंद थे। विरोध की देखते हुए रातो-रात लाठीचार्ज में शहीद होने वालों के शव अंग्रेजों ने दफन दिए। अभियंता जेम्स कहते हैं कि 1942 में महज 21 साल की उम्र में उनके ताऊ शहीद हो गए। आखिरी चेहरा तक देखने को नसीब नहीं हुआ। विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में 10 हजार मर्यादाली रोहतक में एक दिन के अनशन में शामिल हुए। इनका कहना है कि तब उम्र के देवों ने अपने पति को शहादत को सलाह करते हुए दूसरी शायी करने में इत्तफा कर दिया था। समुदाय में ही 1950 में उनका निधन हो गया। स्वजन कहते हैं कि रामपत्र तो मिल गया, लेकिन कंडे सम्मान नहीं मिला। जब हुआ सिटी पार्क वाली जमीन पर जेल थी तब वहां शहीद रतिराम के नाम की पड़िका लगी हुई थी।

एक नज़र

लालू यादव ने दी जनगणना के बहिष्कार की धमकी, बिहार में तेजस्वी यादव ने जाति के मसले पर कसा तंज

पटना (एजेंसी)। बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जाति और आरक्षण के मसले को लेकर आक्रामक रुख अखिरबार कर लिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जाति आधारित जनगणना नहीं लेने की स्थिति में उसका बहिष्कार करने की धमकी दे दी है जो तेजस्वी यादव ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार इससे डर क्यों रही है राजद के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना स्थापित किया गया है। बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी



यादव के अलावा पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ताबड़तोड़ ट्वीट कर इसका साफ संकेत दे दिया गया कि पार्टी एक बार फिर से मंडल की राजनीति पर खुल कर चलने का इरादा कर लिया है। लालू ने

कहा कि अगर 2021 जनगणना में जातिवर्गीय को गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े-अतिपिछड़े के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। देश की बहुसंख्यक आबादी का जब जनगणना से भला नहीं हो रहा है तो फिर जानवरों की गणना खाले आंकड़ों का अंधा खंडे ही खलेंगे। इधर, तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना से इसलिए डर रही है कि पिछड़े जातिवर्गीय की वार्षाविक संख्या सामने आने पर यह पता चल जाएगा कि कैसे मुझे भर लोग सत्ता, देश के संस्थान और संसाधनों पर कुंडली मार कर बैठे हैं। इधर, राजद के अकाउंट से ट्वीट कर आरक्षण के मसले पर आरएसएस को आलोचना करते हुए इसे मुझे भर चित्तावन ब्राह्मणों का जितनाही संगठन बताया गया है। राजद ने कहा है कि इस संगठन की ओकांत नहीं है कि बैंक डोर से आरक्षण बंद कर दे। मोहन भागवत एक बार बयान देकर देखा चुके हैं कि इसका इश्र क्या होगा। आपको बता दें कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि वे खुद और उनका संगठन आरक्षण का समर्थन करता है।

जगदानंद सिंह को हम में शामिल होने का न्योता, प्रवक्ता ने कहा-हम करेंगे सम्मान

पटना (एजेंसी)। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजप्रताप यादव के बीच चल रहा विवाद अब सड़क पर आ गया है। तेजप्रताप के बयान से स्थान होकर राजद प्रदेश अध्यक्ष अज्ञातवास पर चले गए हैं। वे किसी से मिल भी नहीं रहे हैं। इस बीच हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (संयुक्त) के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने राजद के वरिष्ठ नेता को अपनी पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। दानिश रिजवान ने कहा है कि जगदानंद के अपमान को लेकर अब गली-चौराहे पर चर्चा होने लगी है। लेकिन उनके जैसे वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का व्यवहार काफी निंदनीय है। हम चाहते हैं और निमंत्रण देते हैं कि वे हम में शामिल हों। यहां उनकी मान-सम्मान का पूरा खयाल रखा जाएगा। हम प्रवक्ता ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के इशारे पर उनके पुत्र जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को अपमानित कर रहे हैं। उन्हें ऐसा चोट पहुंची है कि वे तीन दिनों से राजद कार्यालय तक नहीं आ रहे हैं। हम उनकी मनोभावना और मन-दशा को समझ सकते हैं। ऐसे समाज और परिवार से आने के बावजूद उन्हें अपमान का घूट पीना पड़ रहा है। ऐसा उनके जैसे गजबूत और गंभीर सोच वाले नेता हो कर सकते हैं। ऐसे नेता को राजद में सम्मान मिलना चाहिए था लेकिन उन्हें अपमान का विष पिलाया जा रहा है। यह पोज़िशन है। दानिश रिजवान ने आग्रह किया है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार समेत राजद का मोह छोड़ें। परिवर्त और दलितों को मदद के लिए हम में शामिल हों। बिहार के पूर्व सीएम जीवन राम मांडवी के साथ दलित और गरीबों के विकास की लड़ाई लड़ें। बता दें कि तेजप्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच मनमुटाव को बात राजद के स्थापना दिवस के दिन भी सामने आई थी। हालांकि मुगों का कहना है कि तब लालू प्रसाद के सभाजने पर जगदा बाबू मान गए थे।

गड़बड़ी करने वाले जाएंगे जेल, शराब के पुराने धंधेबाजों की संपत्ति की होगी जांच

बगहा (एजेंसी)। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से सफल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनाव के समय किसी प्रकार की अशांति नहीं फैले इसके लिए शराब से जुड़े लोगों पर विशेष चौकसी बरते और शराब के पुराने धंधेबाजों की संपत्ति की जांच करें। अगर किसी के द्वारा अधिक संपत्ति अर्जित की गई है वैसे लोगों को पॉन्टिफ करते हुए कार्रवाई का प्रयास करें। पंचायत चुनाव के समय शराब धंधेबाज भी सक्रिय हो सकते हैं। इस लिए अभी से सभी पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में शराब के खिलाफ अभियान चलाएं। जिससे कि क्षेत्र में शराब का स्टॉक नहीं किया जा सके। उक्त निर्देश एसपी किरण कुमार गोरख नाथन ने पुलिस पदाधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में मोहरम है। जिसमें किसी प्रकार की अशांति नहीं फैले इसे लिए वैसे लोगों को निगरान करते हुए निरोधनात्मक कार्रवाई करें। इसके साथ ही सभी पुलिस पदाधिकारी भूमि विवाद को लेकर होने वाले विवादों पर नजर रखें अगर किसी भी क्षेत्र में लगता है कि भूमि विवाद को लेकर समस्या आ सकती है तो वैसे भूमि को पॉन्टिफ करे हुए उनका सभाजने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका समाधान करें। इसके साथ ही शराब के धंधे पर राक के लिए संबंधित धानों की चौकीदारों से मिले सुगम के अनुसार तत्काल छापेमारी अभियान चलाया जाए। जिससे कि शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई की जा सके। अगर किसी चौकीदार के द्वारा शराब बरामदगी में अनाकाली की जा रही है तो वैसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। एसपी ने कहा कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव लाना है।

मधेपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो लोड्डे पिस्टल के साथ तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार

मधेपुरा (एजेंसी)। डकैती की योजना बना रहा तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से दो पिस्टल, पांच कारतूस, बाइक, चार मोबाइल व फिनि पेमेंट बैंक का पत्र मशीन भी बरामद किया है। पुलिस ने सभी बदमाशों को लखनौ भेजने के इंतहारे के समीप मुसमान जगह पर बने एक घर से पकड़ा है। सभी बदमाश घर में डकैती की योजना बना रहा था। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि बदमाशों को गिरफ्तारी के लिए सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था। टीम को सूचना मिली कि पांच-छह बदमाश किसी आपाधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना पर सत्यामत व कांवेई के लिए इंसपेक्टर धाना के सहायक अवर निरीक्षक हवीबुल्लाह अंसारी को दल चल के साथ मौके पर भेजा गया। पुलिस जैसे मौके पर पहुंची कि अपराध की योजना बना रहा सभी बदमाश भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर उसमें से तीन बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़ा गया बदमाशों की कार्रवाई ली गई तो उनके पास से हथियार व कारतूस बरामद हुआ। तीनों को गिरफ्तार कर शना लाया गया। पूछताछ में एक ने अपना नाम रोशन कुमार, दूसरे ने जौम कुमार व तीसरे ने पप्पू कुमार बताया। तीनों इन्हरी गांव का ही रहने वाला है। एसपी ने बताया कि बदमाशों को गिरफ्तार करने में शामिल पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुंगेर में पहाड़ से जमीन पर 200 परिवारों को मिली शरण पर सुविधा देना भूल गई सरकार, इस तरह कर रहे गुजर-बसर

धरहरा (मुंगेर) (एजेंसी)। जिले के नक्सल प्रभावित धरहरा प्रखंड का पैसा गांव पहाड़ की तलहटी में बना था। यहां जो सी आदिवासी परिवार रहते थे। इन लोगों को पुलिस के साथ-साथ नक्सली भी तंग करते थे। इसके बाद वर्ष 2015 में तत्कालीन खोआइजी करण सिंह ने सभी को पहाड़ की तलहटी से हटाकर वन विभाग की जमीन पर बसा दिया।

इस गांव का नाम न्यू पैसरा दिया गया। लोग यहां कच्चे मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन छह वर्ष बाद भी सरकार की ओर से इस गांव को आवश्यक सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है।

छह वर्ष पहले आदिवासी समुदाय के दो सौ परिवार को पैसरा पहाड़ से वन विभाग की जमीन पर बसाया गया आवास और दूसरी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं न्यू पैसरा गांव, आवास योजना का नहीं मिला है लाभ न्यू पैसरा गांव में पौने



के पानी लिए एक चापाकल तक नहीं है। गांव तक आने-जाने के लिए सड़क जरूर नहीं है। किसी को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर वन विभाग की जमीन पर बसे न्यू पैसरा गांव पहुंचते ही विकास और वायदे का तालिसम

बिहार के पूर्वी चंपारण में पत्रकार की निर्मम हत्या: अगवा कर आंख निकाली, फिर गला रेत कर फेंक दिया शव

पूर्वी चंपारण (एजेंसी)। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक न्यूज चैनल के शूरा पत्रकार मनोप कुमार सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। शव को देखने से प्रतीत होता है कि हत्या के पहले उसे यकनार भी दी गई। अपराधियों ने उसे अगवा कर आंख निकाली, फिर गला रेत कर मार डाला। इसके बाद शव को फेंक कर भाग गए। इस घिसमिसे में मृतक के पिता ने उसके दो दोस्तों सहित 17 लोगों के खिलाफ एकआडोआर दर्ज कराई है। मृतक के पिता के अनुसार घटना का एक कारण खबरों को लेकर दुश्मनी भी है। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठ लोहियार चौक से शनिवार को रात से लापता सुरेंद्र न्यूज चैनल के पत्रकार मनोप कुमार सिंह (30 वर्ष) का शव मंगलवार को पच्छिमोत्तर गढ़ी टोला के पास खबर से मिला। इसकी सूचना के बाद वहां भीड़ जुट गई। अराजक के झेरसपी संतोष कुमार ने बताया कि ग्रामज घाते में खद का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान मनोप का जुता और मोजा गिरा। बाद में पुलिस ने शव को पानी से निकाला। आशंका है कि गला रेतकर हत्या के बाद शव को वहां फेंक दिया गया था।

शोरसपी के अनुसार शनिवार के वीडियो फुटेज में मनोप के साथ दो दोस्त अमरेंद्र कुमार और अमजद आलम थे। बाद में दोनों घर चले गए और मर्णाप लापता हो गया। इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोप का बेटा अमरेंद्र कुमार के घर से मिला। अराजक के पहाड़पुर की गई। उन्होंने ब्रेट की हत्या के मामले में उसके दोस्त अमरेंद्र कुमार और अरुण आलम सहित 13 लोगों को नामजद किया है। उधर, घटना से आक्रोशित स्वजनों और ग्रामीण ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। वे ग्रामीण एसपी को बुलाने, सभी आरोपितों को गिरफ्तारी, स्पीड ब्रेकल



थाना क्षेत्र के बघुआडा टोला के रहने वाले मृत पत्रकार के पिता मनोप सिंह भी पत्रकार हैं। वे अरेराज दर्शन नाम से एक पत्रिका निकालते हैं। सजय सिंह आरटीआइ कार्रवाई भी हैं। उनके अनुसार खबरों को उजागर करने के कारण कई लोगों से दुश्मनी है, जो उन्हें धमकियां देते रहें हैं। भूमि विवाद भी है। इनकी कार्रवाइ से उनके बेटे की हत्या चलने, मृतक के परिवार और जिले के पत्रकारों की सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। बाद में एसपी शैल यादव तथा अराजक के झेरसपी संतोष कुमार ने लोगों को शांत कराया। झेरसपी ने कहा कि इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ स्पीड ब्रेकल के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बिहार के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस का उपहार, स्कूल तो खुलेंगे पर बरतें ये एहतियात

पटना (एजेंसी)। बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण पर लगातार लगने के बाद अब अनलाक के पांचवे चरण में पहली से आठवीं तक के स्कूलों को खोलने की बारी है। बिहार में छोटी कक्षाओं को ऐसे स्कूल कोरोनावायरस संक्रमण की राकथाम की गाइडलाइन को शर्तों के अधीन 16 अगस्त से खोलें जा रहे हैं। इसके पहले सरकार ने सात जुलाई से नौवीं व 10वीं के स्कूल खोल दिए हैं। लंबे समय से बर्बात पढ़ाई को देखते हुए इसकी मांग की जा रही थी। बच्चों के लिए यह स्वतंत्रता दिवस का उपहार है। हालांकि, कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए स्कूलों व घरों में एहतियात जरूरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि स्कूलों को खोलने के लिए जरूरी एहतियातों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इनका सख्ती से पालन करना होगा। सरकार के लिए शिक्षा के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा भी प्राथमिकता है। कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों के घटने के साथ अब पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूल तो खोलें जा रहे हैं, लेकिन एहतियात भी जरूरी है। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरा गाइडलाइन जारी की है। आइए देखते हैं नजर-



शेरी। बसों में हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा। बच्चों में बगैर मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चालक व उपचालक को भी मास्क लगाना होगा। मास्क की अदला-बदली पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों को जीविका के माध्यम से दो-दो मास्क दिए जाएंगे। स्कूल के प्रवेश द्वार पर छात्र-छात्राओं व स्कूल कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। आगमन व प्रस्थान के समय स्कूल के प्रवेश द्वार खोलकर रखने होंगे। आने-जाने के लिए अलग-अलग द्वार होंगे। स्कूल में धुकने पर प्रतिबंध के नोटिस वाला बैनर लगाना होगा। स्कूल के मुख्य द्वार से लेकर कक्षाओं व स्टॉक रूम तक हर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। स्कूलों में क्षमता के आधे छात्र-छात्राओं को ही आने की अनुमति दी जाएगी। कक्षाएं एक दिन के अंतराल पर संचालित की जाएंगी। आधे बच्चे एक दिन स्कूल-कॉलेज में आएंगे तो आधे दूसरे दिन। अधिक नामांकन वाले स्कूलों में कक्षाएं दो पालियों में होंगी। स्कूल गैरिसर व कक्षाओं में शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। स्टॉफ रूम, कार्यालय व आगत कक्ष में भी यह नियम लागू रहेगा। स्कूलों में समारोह या त्योहार आयोजित नहीं किए जाएंगे। असेंबली भी नहीं होगी। बच्चे घर से ही अपना लंच लेकर स्कूल आएंगे। स्कूल गैरिसर में खाने-पाने की वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोनावायरस की वैक्सीन से चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।

बिहार में पेट्रोल उत्तरप्रदेश से सात रुपये महंगा, यहां कारोबारियों की टूट रही कमर

भभुआ (एजेंसी)। कोरोनाकाल में किरानों ने अपना जान गवां दी। कई लोगों को रोजगार छिन गए। मध्यम वर्गीय परिवारों को पेट्रोल व डीजल की बढ़ी कीमतें रुखा हो रही हैं। उनके घर का बजट बिगड़ गया है। इससे सीमावर्ती इलाकों में संचालित पेट्रोल पंप के मालिक भी प्रभावित हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल बिहार की अपेक्षा करीब सात रुपये सस्ता है। इस वजह से अधिकांश लोग बिहार के बजाए यूपी में ईंधन लेने चले जाते हैं। इसके कारण पेट्रोल पंप संचालकों की आमदनी घट गई है। सीमावर्ती इलाकों के कुछ पेट्रोल पंप को हालत यह है कि उनका खर्च तक नहीं निकल पाता है। बिहार का कैमूर जिला उत्तर प्रदेश के नौडौर पर स्थित है तो अधिकांश लोग वहीं जाकर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरवा लेते हैं। पेट्रोल पंप वालों को राजस्व तो भी कम प्रति हो रही है। इस वजह से पेट्रोल पंप संचालकों को लग रहा है कि अगर सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दी, तो इससे इस कारोबार को बड़ा झटका आने वाले दिनों में और लग सकता है।



कैमूर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के कायाबन्ध होर प्रसाद सिंह ने बताया कि बिहार की उत्तर प्रदेश में डीजल व पेट्रोल की कीमत में करीब सात रुपये का अंतर है। वहां पेट्रोल मात रुपये कम होने के कारण अधिकांश लोग यूपी चले जाते हैं। इस वजह से पेट्रोलियम कारोबार में बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ येतहास तक के पेट्रोलियम कारोबारियों को परेशान किया है। दरअसल जिनको अधिक पेट्रोल व डीजल लेनी होती है वो कैमूर जिले

में पेट्रोल व डीजल के को पार करते ही यूपी में जाकर तेल भरवा लेते हैं। प्रति लीटर सात रुपये की आंख के जमाने काफी अधिक है। एक पेट्रोल पंप के संचालक ने बताया कि जोटी रोड पर बाहन चालक उनका ही तेल लेते

हैं जितना से कि बाहन यूपी में प्रवेश कर जाए। उसके बाद टैंक फूल यूपी में भरवाते हैं। ऐसा सिर्फ कैमूर में ही नहीं बल्कि रोहतास, औरंगाबाद, गया जिले तक से गुजरने वाले ट्रक चालक व अन्य वाहनों वाले करते हैं। मुगों की मानें तो पश्चिम बंगाल व गुजरात और ईंधन के दाम सस्ते होने के कारण बिहार में अधिकतर बाहन चालक तेल लेने से कतराते हैं। कैमूर जिले के चांद, चैनपुर, रामगढ़, गुआर, दुर्गापुर, मोहिनिया व अशौरा आदि प्रखंड के लोग अधिकांश तेल नगर प्रदेश से ही लेते हैं। अरुणा बस के मालिक जगननाथ सिंह ने बताया कि उनकी बसों में भी यूपी से ही तेल भरवाया जाता है क्योंकि वहां पर सात रुपये तक का पेट्रोल व डीजल

की कीमत कम है। वर्तमान में यूपी में डीजल 90.15 रुपयेलीटर, व पेट्रोल 98 रुपया लीटर के आसपास बिक रहा है। जबकि बिहार में डीजल की कीमत 97.14 रुपये व पेट्रोल 105.98 रुपयेप्रति लीटर बिक रहा है। इस कारण अधिकांश लोग यूपी से तेल ले रहे हैं। पेट्रोलियम एसोसिएशन व बस मालिकों का कहना है कि अगर सरकार बिहार में तेल के टैक्स में गिरावट करती है तो बिहार में फिर से तेल की खपत अधिक होगी, और बिना अधिक होगी। अधिक बिक्री व खपत होने से सरकार के राजस्व पर कोई नुकसान नहीं आएगा। ऐसा ही हालात पड़ोसी राज्य से सटे हुए सभी जिलों का है।

मछली मारने का विरोध करने पर दरवाजा खुलवाया और सीने में मार दी गोली, नालंदा जिले की घटना

नालंदा (एजेंसी)। घर के निकट मछली मारने से मना करने की मामूली सी बात पर हुई कहासुनी से नाराज बदमाशों ने गंगलवार को रात एकांतरसरा में गहन प्रसाद यादव की हत्या उनके दरवाजे पर ही कर दी। दरवाजा खोलवा कर उनके सीने में गोली मारी गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वे 45 वर्ष के थे। वे स्थानीय खानपुर गांव के मूल वासिंदे थे। पिछले कई साल से एकांतरसराव में पशु अस्पताल के सामने अपने मकान में खटलन चलाते थे। मदन की हत्या कर भाग रहे बदमाशों में से एक युवक को गिराफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर दो अन्य की गिरफ्तारी कुछ देर बाद हुई। बदमाशों ने थाना पुलिस के समक्ष जुर्म कबूल कर लिया है। हिलसत खैरसनी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं बदमाशों का फरसा बरामद कर लिया है। कांड में शामिल तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की पत्नी रुबी देवी ने थानावास को बताया कि उसके पति मदन प्रसाद और पुत्र हनुमै कुमार साथ में घर में सोए हुए थे। रात करीब 10:30 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। वे उठकर दरवाजा खोलने गए तो मैं और मेरा बेटा भी उनके पीछे दरवाजे तक आए। बाहर निकले तो देखा कि आधा दर्जन लोग खड़े हैं। उनकी लोहों में से एक ने उनके पति के सीने में गोली मार दी और जानवर अस्पताल की तरफ भाग निकले। शीघ्र मचवा तो पड़ोस के लोग मदद को अस्पताल ले गए। लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। बताया गया कि संयोगवश सहायक अवर निरीक्षक रामपुकार दुबे उसी

रात गश्त करते हुए हिलसा थाने की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस टीम को देख बदमाश पशु अस्पताल परिसर में जा छुपे। उन लोगों को पुलिस ने खदेड़ तो एक युवक पकड़ में आ गया। इसी बीच हिलसा के पुलिस उपनिरीक्षक कृष्ण मुरारी प्रसाद एवं थानाध्यक्ष संतोष कुमार घटना स्थल पर पहुंच गए और हत्या में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं फरसा बरामद किया। गिरफ्तार बदमाश से कड़ाख



पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों के नाम बताए। उसकी मदद से दो अन्य बदमाशों को पकड़ लिया गया। इस कांड में मृतक की पत्नी के बयान पर चार नामजद हुए थे-तीन अज्ञात के विरुद्ध एकआडोआर दर्ज की गई है। स्थानीय शिवदत्त बिगहा निवासी किशोर प्रसाद यादव के पुत्र काया कुमार के अलावा चाचा के खमांडिया मोहल्ले के नेता मोची के पुत्र जीवन कुमार, अरविंद कुमार के पुत्र गोलू कुमार एवं राजेश खंडवाल के पुत्र अश्वक को नामजद किया गया है।

बिहार में कोरोना ने फिर दी दस्तक: अब गया जिले में हर दिन मिलने लगे कोरोना पॉजिटिव मरीज

गवा (एजेंसी)। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरों को हल्के में लेने वाले जग सावधान हो जाए। कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से नहीं दूर हो रहा है। बीते कुछ दिनों से जिले में हर दिन कोई न कोई संक्रमित हो रहा है। मंगलवार को कोच प्रखंड के सिटुआरी गांव की एक 28 साल की महिला संक्रमित हो गई। इनकी रिपोर्ट एंटीजन जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले इसी माह में नीमचक बथानी, डुमुरिया, बैरागी गांव से एक-एक महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जबकि शेरघाटी व गुरुआ में एक-एक पुरुष को रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इस माह में अब तक छह लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी आमजन मास्क पहनकर रहें। शारीरिक दूरी का पालन करें। भीड़-भाड़ में जाने से बचें। हाथों का समय-समय पर सैनिटाइज करते रहें। बीते जुलाई में पूरे महीने भर में सात लोग पॉजिटिव आए गए थे। उस समय तक लोगों को लग रहा था कि अब कोरोना खत्म हो गया। इसी बीच अगस्त के शुरूआती 10 दिनों में ही छह नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि ने विभाग को चिंता बढ़ दी है। अभी अगस्त का पूरा माह बाकी है। ऐसे में लोगों से अपील है कि कोरोना को लेकर सावधान रहें। खुद और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर खाम तौर पर ध्यान दें। मंगलवार को जिले भर में 6408 लोगों की सैपल जांच की गई।



दिष्ट। भविष्य को परिचोजनाओं के बारे में अनिश्चय ने कहा कि अमेज़न प्राइम सेवामेरीज के लिए चर्चा चल रही है, एक बहुभाषी फीचर फ़िरम अथवा ओपेनटैब्लेयफ़ॉर्म के लिए भी है। गो, अनिश्चय खुद को ब्रह्मीयता में कैसे देखते हैं जहां पर लोग के बीच प्रत्येक वर्ष बहुत अंतर है? अनिश्चय ने कहा, अपनी कल्पना और कमजोरी को पहचान करना और उनके अनुसार खुद को स्थिति में लाना बहुत महत्वपूर्ण है, शायद अलग और विशिष्ट सामान्य और अपने शिल्प पर काम करना और अपनी प्रतिभा पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। अनिश्चय के पास इराफ़ा खान, मनोज वाजपेयी और नवाबुद्दीन सिरीकी के रूप में ब्रह्मीयुद्ध के उनके आदर्श हैं। एक आध्यत्मिक रूप से प्रतिभाशाली अनिश्चय के लिए, खुद आता है। भविष्य उनके है जो जीवन में वास्तविक गैरिजिम उठते हैं और अनिश्चय ऐसे ही एक अभिनेता हैं जो कम वाज़ा वाले रास्ते पर चलने और विजेता बनने के लिए तैयार हैं। नज़र ना लगे!

OPEN SEARCH

National English Daily

YEAR : 06 ISSUE : 146

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021 Rs. 1/-

Pages- 8

RNI No. DELENG/2016/67075

E-mail | opensearchenglish@gmail.com

Facebook | <https://www.facebook.com/opensearch.co.in>

Website | www.opensearch.co.in

Neeraj Chopra's gold..P-6



News in Breif

Anurag Thakur says Congress MP's conduct in RS shameful, likens his act to vandalism at Red Fort



New Delhi, Agency. He also lashed out at Congress and other opposition parties over the disruption of the proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha, saying those who have been sent to Parliament by people to raise their issues are resorting to unruly behaviour. Union minister Anurag Thakur on Wednesday likened the unruly behaviour of Congress MP Pratap Singh Bajwa in the Rajya Sabha to the January 26 vandalism at the Red Fort and said throwing a file at the Chair in the House was a "shameful" incident. He also lashed out at Congress and other opposition parties over the disruption of the proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha, saying those who have been sent to Parliament by people to raise their issues are resorting to unruly behaviour. Bajwa was on Tuesday seen throwing an official file at the Chair in the Rajya Sabha after climbing the table occupied by officials during the protest by opposition members when the House was to commence a discussion on farmers' issues. "Throwing a file at the Chair after climbing the table was a shameful incident," Thakur told reporters.

UP records 27 fresh Covid cases; 12 districts free from Corona



Lucknow, Agency. Uttar Pradesh logged 27 new Covid-19 cases and 63 recoveries in the past 24 hours. Additional Chief Secretary, Information, Navneet Sehgal said here on Wednesday. Besides, 12 districts Aligarh, Amethi, Chitrakoot, Etah, Firozabad, Gonda, Hathras, Kasganj, Pilibhit, Pratapgarh, Shamli and Sonbhadra became Corona-free, he said. Currently, there are 505 active Corona patients in the state Mr Sehgal said, adding that so far, 16,85,555 residents of the state have recovered from the infection. The positivity rate remains 0.01 and the recovery rate is 98.6 per cent. In the testing of 2,39,909 samples done in the last 24 hours, not a single new case of infection was found in 59 districts, while patients were found in single digit in 16 districts. So far, 6,81,37,752 Covid samples have been investigated in the state, highest in the country. UP is the only state where more than 5,50,52,000 vaccine doses have been administered so far. More than 4,64,33,000 people have received a single dose of the vaccine. Till date, more than 86 lakh people have received both the doses of Covid vaccine in the state. Now Saturday has been kept reserved for the second dose of vaccine. Besides appropriate arrangements should also be made for vaccination of Buddhist monks, foreign nationals and helpless/desitutes.

Uproar in HP Assembly over RSS remarks, Cong walks out to protest Speaker's attitude



Shimla, Agency. The opposition Congress members walked out of the Himachal Pradesh Assembly over the issue of comments made by Speaker Vipin Singh Parmar supporting Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). The trouble started when Congress members alleged that Kinnair M.A Jagat Singh was not allowed to speak and two members of BJP threatened to physically harm him. They alleged that the speaker did not intervene in the issue and despite that he supported erring ruling members. The speaker stated that he is expected to defend the cabinet ministers since he was on the chair adding that Congress members have blamed him and the government for promoting and appointing people of a certain ideology on various key positions. "I belonged to RSS and if any minister or government functionary hails this ideology, it is a matter of honour as the entire government and country belonged to this ideology."

Inflammatory slogans at Jantar Mantar : Court reserves order on Ashwini Upadhyay's bail plea

New Delhi, Agency.

The Delhi Police said Upadhyay was a speaker at the event and whether he was present during the time of sloganeering is under investigation. Delhi Police Tuesday opposed the bail application of Supreme Court lawyer and former Delhi BJP spokesperson Ashwini Upadhyay, who is currently in judicial custody for alleged inflammatory and anti-Muslim slogans at Jantar Mantar. Police told the court Upadhyay was a speaker at the event and whether he was present during the time of sloganeering is under investigation. After police's submission, Duty Metropolitan Magistrate at Patiala House Court Udhav Kumar Jain reserved his order on Upadhyay's bail plea. Senior Advocates, Vikas Singh, Siddharth Luthra and advocate Ashwani Dubey argued on behalf of Upadhyay. Singh told the court that Upadhyay was not present during the time of the incident as per the timing of the videos that went viral and informed, he was in Ghaziabad. "I will be the last person to represent somebody who made such reprehensible slogans."

If the allegation was, I was the organiser and this took place in front of me, I would not have represented him...He is a very respected person...It is a very serious case. Police can't indiscriminately arrest him. He should be released today itself. This is an illegal incarceration," Singh told the court. Luthra told the court, "Very often in life we may be a part of a public function, that does not mean that if a fracas breaks out when we are not there, we should be held responsible. That should not be held against him." The public prosecutor told the court that the gravity of the offence and the sensitivity of the case have to be looked into. He told the court that at the time when Covid-19 restrictions were in place, the monsoon session was underway as were preparations for Independence Day celebrations. "They should have been calculating while arranging this gathering. It was to create a ruckus, what was the need to do this at this time? They did not have permission. They did not respect the DCP order. Policemen on the ground had been telling them about social distancing and wearing masks but they were disobeyed," the prosecutor told the court. The prosecutor told the court that Upadhyay was a speaker at the event and his involvement must be looked into. "Look



at their involvement. They are saying he was present. He said he was a speaker. There is an admission. Whether he was there or not during the hate speech, we don't know but he was a speaker," the prosecutor told the court. The prosecutor said Upadhyay should have first complained to police, which instead undertook this case on its own. He said videos investigated by the investigating officer contained hate speech which was evident. "His version is that he had left. When he left is a matter of investigation. There is no evidence as such that he left. It is their version. Exactly what is the nexus, who gave the speeches? We are at a nascent stage of the investigation," the prosecutor told the court. Singh told the court, "You pick anyone that cannot be justified. We were saying we are not involved in the incident. Look at the video footage." "It is against the rule of law to arrest anyone. Tomorrow you will pick me up saying someone made hate speech and we will arrest you. There is no link between us," Singh told the court. Dubey rebutted the prosecutor's claim that Upadhyay did not bring the incident to the notice of police. He told the court, "Upadhyay wrote an email to the DCP to arrest these persons. He eventually gave a three-page letter and pendrive to police... It is not that he has no respect for law."

10,000 RT-PCR tests to be ensured in Punjab Schools daily

Chandigarh, Agency.

Chief Secretary Vini Mahajan directed the departments concerned to step up RT-PCR testing and to conduct atleast 10,000 RT-PCR tests related to schools daily and the DCs to ensure that only fully vaccinated teaching and non-teaching staff was allowed to attend the schools. She directed that target of 40,000 samples per day must be achieved and testing shall be further increased if the Covid cases rise.

Chairing a meeting to review the Covid situation in the state with the senior officials of the Health, Medical Education, School Education departments and all Deputy Commissioners, Ms Mahajan expressed concern over the movement of people to Punjab from neighbouring states, where the virus cases were once again on the rise, and asked the officials concerned to keep a close watch on the positivity rate ahead of the festival season when extra vigil was required to prevent the surge of virus. Instructing all the districts to continue aggressive



testing and contact tracing and testing to check the spread of the pandemic, she said epidemiologists have been appointed in all the districts and all-out efforts should be made to thwart the possible third Covid wave. Quoting the forecast from University of Cambridge, Ms Mahajan said going with the forecast, new cases can be expected to double in about 64 days (under the assumption that the growth rate remains constant). She expressed satisfaction over the fact that 2,45,823 samples have been taken in the past week from August 3 to 9, and only 352 had tested positive, which accounted for a positivity rate of 0.1 per cent.

Uttar Pradesh allows markets to open on weekends

Lucknow, Agency.

Uttar Pradesh government on Wednesday allowed opening of markets on weekends as second wave of covid-19 is ebbing in the state. During meeting with Team 9, formed by the state government to deal with coronavirus second wave, Chief Minister Yogi Adityanath announced partial relaxation in covid curbs by allowing markets to open on weekends. "Covid protocol should be followed in every case at every place. There should not be unnecessary congestion anywhere. Police patrolling will continue and appropriate guidelines should be presented regarding the new system," the CM said. In another announcement, Mr Adityanath said physical education is starting in secondary, higher, technical and vocational educational institutions after



Independence Day. In view of this, vaccination camps should be organised in the university/school/college premises for the vaccination of students above 18 years. In the schools of Basic Education Council, the presence of teachers / personnel is increasing and vaccination camps should be organised in these school premises as per the requirement. According to the recommendations of the State Level Health Expert Advisory Committee, physical presence of students will be started

with 50 per cent capacity in secondary, higher, technical and vocational educational institutions after Independence Day. Classes everywhere will be conducted in two shifts and Covid protocol should be followed, Mr Adityanath said. The CM said in the schools of Basic Education Council, the process of new admission should be started in classes from class 6 to 8. Assessing the situation, teaching-learning can be started in these schools from September 1 too.

Uddhav Thackeray had announced that people who have been fully vaccinated and completed 14 days

Help desks in 53 Mumbai stations to verify vaccination certificates

Mumbai, Agency.

In the remaining 55 stations of Mumbai Metropolitan Region, the respective municipal corporations or local bodies like in Thane, Navi Mumbai, Palghar and Raigad will set up help desks.

With Maharashtra government allowing people fully vaccinated against Covid-19 to travel in local trains from August 15, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) on Tuesday said it will set up 358 help desks in 53 stations of Mumbai to facilitate offline verification of vaccination certificates. The facility will be available from Wednesday. In the remaining 55 stations of Mumbai Metropolitan Region, the respective municipal corporations or local bodies like in Thane, Navi Mumbai, Palghar and Raigad will set up help desks. On August 8, Chief Minister Uddhav Thackeray had announced that people who have been fully vaccinated and completed 14 days after receiving the second dose will be allowed to travel in Mumbai suburban local trains from August 15. Thackeray had announced that an online and offline system would be set up for commuters



to verify the authenticity of their CoWin-generated vaccination certificates to make them eligible for a monthly pass. While the government is yet to start the online system, the BMC on Tuesday rolled out the standard operating procedure (SOP) on how the offline system will operate. Across Mumbai, 358 help desks will be set up at 53 stations. These help desks will be operational on all seven days in two sessions - 7 am to 3 pm and from 3 pm to 11 pm. The SOP issued by BMC stated that fully vaccinated commuters, who have completed 14 days after the second

dose and wish to avail the monthly season pass, can approach these help desks. The commuters have to show their vaccination certificate, along with a government issued photo ID (preferably Aadhaar card) card. They also need to carry a photocopy of the photo ID for stamping purposes.

The staffers at the help desks will verify the authenticity of the vaccination certificate by scanning its QR code. If found authentic, they will stamp the certificate as well as the photocopy of the photo ID. The commuter can then use the same to procure the monthly pass at the ticket counters. Commuters are required to carry all three-tickets, vaccination certificate and ID card while travelling. "A strict system of checking will be in place with the police only allowing those with monthly pass and vaccination certificate along with a photo ID card to enter platforms," a senior railway official said. Those found with fake documents will be liable for criminal action under the Epidemic Control Act, Disaster Management Act and the Indian Penal Code. Municipal Commissioner

Iqbal Singh Chahal told mediapersons on Tuesday. "The chief minister has announced that the eligible citizens who have completed vaccination against Covid-19 (including 14 days after second dose) will be able to travel by local train from August 15. This will be facilitated both online and offline. However, the process of creating a mobile app and starting the online process may take a little more time. Hence, the offline process will start from Wednesday." He also appealed to people not to unnecessarily crowd at stations. The Central Railway administration said it will open sufficient number of booking windows to avoid crowding. People working in government and semi-government offices as well as those involved in providing essential services will continue to travel by local trains as per prevailing practice, even if they are not vaccinated. Suburban train services were shut down on March 23 last year during the lockdown. The Central Railway and Western Railway used to operate 1,774 and 1,367 services each day, respectively, before the pandemic. Subsequently, train services were resumed but access was limited to specific categories of people.

The Deputy Commissioner reviewed the works of the Circle Office



Dhanbad.

The Deputy Commissioner inspected the Dhanbad circle office today to review the works of the zone. He investigated cases related to filing-rejection, public grievance, encroachment, register-2, illegal jamabandi and pension. During inspection, he found that the encroachment register is not maintained in the circle office. The Deputy Commissioner directed the Circle Officer to review the encroachment register from time to time. He found that there is a lot of difference in the name, account, plot etc. in the old and new register-2. In this regard, after submitting the report to the Circle Officer, he directed to form a team at the district level and take action. The Deputy Collector of Land Reforms said that during the inspection of the complaint register, the Deputy Commissioner noticed that there are big places in Light 1, 2 and 3. He said that at present, the approval and approval of the beneficiaries of Putki zone under social security pension is also being done from Dhanbad zone itself. In this regard, the Deputy Commissioner has directed to maintain the register of pension applications by separating the jurisdiction of both the zones in coordination with the Social Security Cell. During the inspection, the Deputy Commissioner, Deputy Collector of Land Reforms, Circle Officer Dhanbad and others were present.

MLA Dhullu Mahto laid the foundation stone for construction of shed in Mansa temple

Dhanbad.

Baghmara MLA Dhullu Mahto today laid the foundation stone for construction of sheds at Mayrakuli in Katras Bazar and Mansa Mandir of Katras Kewat Toia. Addressing the function, MLA Dhullu Mahto said that he is committed to the development of Baghmara. According to the people of Baghmara, Baghmara will develop. He said that five street lights have been installed for public convenience in the cremation ground of Katras Lilauri temple. There the light is shining now. Nityanand Dey, Manik Da, Pranav Banerjee, Chandan Modak, Pintu Dey, Shrikant Chatterjee, Gaur Chandra Kewat, Arun Kewat, Malu Kewat, Gopal Kewat etc. were present in the foundation stone laying ceremony.



Public notice issued to clear illegal construction across forest land in Faridabad

New Delhi. A fortnight after officials from Faridabad said illegal encroachments would be removed from Aravalli forest land and PILPA notified land across the district in the coming days, like it was done at Khori village, a public notice has been issued in this regard. "It has come to our notice that non-forestry activities and unauthorised construction have been done on land notified under sections 4 and 5 of the Punjab Land Conservation Act (P.L.P.A.), 1900," said District Forest Officer Raj Kumar.



Dhanbad MP PN Singh meets Union Minister of State for Fertilizers

Dhanbad.

Dhanbad MP Pashupati Nath Singh met Union Minister of State for Fertilizers Bhagwant Khuba at Parliament House today and demanded from him to increase public facilities in Sindri. The MP asked the Union Minister of State that his ministry should work to increase public convenience and speed up development works in Sindri and surrounding areas. The Minister said that he would visit Sindri in September and take whatever steps are necessary for the development of Sindri. Karnataka BJP state president Nalin Kumar Katil was also present during the conversation.



Aanchal Mahila Samiti distributed material among poor women

Putkee.

Mosquito nets, masks, soaps and sanitizers were distributed among 40 poor and needy women in Samsikharu Panchayat of Munidih by the members of Aanchal Mahila



Samiti of Munidih located in western Jharia area. Dyuti Mustafi, Akanksha Karm, Jhulan Panja, Babita Baruiwal, Sunita Weaver, Mamta Puri, Savita Kumari, Poonam Jha etc. were present in the program along with Bharti Mohapatra, President of the Women's Committee.

BJYM celebrated black day

Loyabad. Black Day was celebrated today by Bharatiya Janata Yuva Morcha Loyabad against the lathi-charge by the police on the girl students along with the SDO. The speakers said that the agitation will continue till the SDM of Dhanbad is not sacked. On this occasion, Loyabad Divisional President Ram Singh, Minority Front District Upadhyay W Alam, Abhijit Bhattacharya, Raj Singh, Avinash Srivastava, Mahtab Alam, Sumit Pramanik, Sandeep Sao etc. were present.



Signal Tele rail workers will get night allowance

Decision taken in meeting of PNM with ECRKU.

Dhanbad.

On the instructions of the branch officer, the payment of night allowance to the railway workers of signal tele of Dhanbad division has been stopped for the last one year. The employees concerned are compelled to do duty at night without night allowance. Along with this, the payment of National Leave Allowance for duty on national holidays was also stopped. This caused considerable financial loss to the signal personnel. Giving the above information, ECRKU Central President PNM in-charge DK Pandey said that there is a lot of resentment among the Signal Tele employees due to such unjust behavior. Due to the Corona crisis, the solution of this problem could not be found in the virtual meeting with the administration. The meeting of Permanent Dialogue Mechanism of Divisional Railway Manager was concluded today with the delegation of ECRKU, which was conducted by Senior Divisional Personnel Officer Jaiprakash Singh. DK Pandey led on behalf of the Sangh. Expressing displeasure over the said matter, the union members demanded payment of night allowance and national holiday allowance to tele workers without delay. Newly appointed Senior Divisional Engineer Signal Tele Gautam Gupta said that in this matter instructions are being issued to all the depots without delay. Action will be taken on the payment of night allowance and national



holiday allowance to all the employees on the basis of the decision of the Railway Board and the divisional joint process. On the spot, the union representatives demanded payment of withheld allowances since last year, on which the branch officer agreed to take action with the consent of the finance manager. In the meeting, Assistant Personnel Officer Trilok Nath Verma, Additional General Secretary of ECRKU Ziauddin, Assistant General Secretary Om Prakash, Union Organization Minister PK Mishra and VD Singh, Central Treasurer cum AIRF Zonal Secretary OP Sharma along with Basant Kumar Dubey, TK Sahu, AK. Da, Netaji Subhash, BK Jha, BB Singh, IM Singh, KK Singh, Chandan Kumar Shukla, RN Chaudhary, Ajit Kumar Mandal, Sunil Kumar Singh, VKD Dwivedi, CP Pandey and women representative Smt. Meena Kundu and office in-charge Somen Dutta were present.

Shadow mourning in Lodna area due to the death of INTUC leader Bhootnath

Alakdiha/Baliyapur.

73-year-old Bhootnath Dev, secretary of Jharkhand INTUC Lalan faction and labor leader of South Tisra Loading Point resident of Suranga Basti of Lodna area of BCLL, died late on Monday night. He was treated at a hospital in Kolkata for a week. He had heart and kidney disease. Bhootnath's death has dealt a big blow to the movement of laborers and ryots of INTUC, Lodna region. They have always fought for their rights. There is mourning in the entire Lodna area after hearing the news of his sudden demise.

He undisputedly led the workers of South Tisra and North Tisra loading point for the last forty years, due to which today the workers of the area are saddened by the demise of their leader. The loading work was stopped today in mourning. Bhootnath was associated with INTUC and Congress for years. At present, he continued to do social service by joining many social organizations while being the Vice President of the District Congress and the Chairman of the Managing Committee of Kusmatand High School. On receiving the news of Bhootnath's death, supporters and well-wishers thronged Suranga's house since morning to have a glimpse of their leader. Tribute and condolence meeting was organized at his residence after bringing his body from Kolkata at 10 am on Wednesday. Hundreds of people draped Bhootnath's body in the Congress flag and offered flowers, garlands and petals and prayed to God for the departed soul to rest in peace. The funeral procession was performed at Mohabani Muktidham after taking out the dead body from Suranga. On this occasion former minister Mannan



Mallick, former MLA Anand Mahto, INTUC general secretary Lalan Choubey, Dharmendra Singh, JMM leader Yudheshwar Singh, Atul Singh, Chandicharan Dev, PO Pankaj Kumar, manager DK Manjhi, RJD leader Rambabu Yadav, Manoj Yadav, Suranga Panchayat Principal Lalita Devi, Sanatan Ravidas, Mallu Singh, Pramod Singh, BMS leader Ajay Dev, Vikas Mahto, Congress leader Mukhtar Khan etc. have expressed deep grief over the death of Bhootnath. The members and teachers of Kusmatand High School Management Committee are deeply saddened by the death of Bhootnath. On behalf of the committee, a condolence meeting was organized in the school premises and tribute was paid by paying floral tributes to his picture. Manik Gop, Shaktipada Dheevan, Appu Mishra, Sandeep Mahto, Santosh Mahato etc. were present on this occasion.

MALE and MCC staged a sit-in for employment

Dhanbad.

To demand employment for the unemployed, today a dharna was held at Randhir Verma Chowk under the joint aegis of Marxist Coordination Committee and Communist Party of India (MALE).

Hundreds of leaders including former Nirsia MLA Arup Chatterjee and Bagodar CPI-ML, MLA Vinod Singh attended the dharna. Bagodar MLA Vinod Singh said that the Hemant government of Jharkhand, which gave majority to the present Hemant government by bid farewell to the previous Raghuvar government, is not living up to the expectations of the people. In such a situation, there is a need to solve all the problems including employment, honorarium of various contract workers by the Hemant government at the earliest. He said that the Hemant government should take immediate action



even in the case of brutal lathi charge on girl students by the administrative officer in Dhanbad. He said that employment should be provided to all the unemployed in Jharkhand without any delay, so that the public's hope on the Jharkhand government remains intact.

Courtesy of MLA Poornima, poor woman got sewing machine

Jorapukhar.

On behalf of Jharia MLA Poornima Neeraj Singh, MLA representative KD Pandey handed over the sewing machine today on the demand of Priyanka Devi, wife of Dinesh Prasad Mathuri, a resident of Baniyahi No. 10. Priyanka Devi met MLA Poornima Neeraj Singh and told her problem. She told that her husband is a daily wage labourer. Due to the deteriorating economic condition due to lack of regular work, the situation of starvation has come in front of the family.

Priyanka had demanded a sewing machine and said that she would take sewing-weaving training. She had said that by sewing at home, she could feed her family including a daughter, a son. On this, the MLA immediately gave a sewing machine while fulfilling the social responsibility. MLA representative KD Pandey handed over the machine to Priyanka Devi at Katras Mod office. Along with this, by



paying auto fare, Priyanka was sent to her house. The MLA said that he has tried to solve the problem of Priyanka's family with a little help. Ratnesh Yadav, Siyaram Prasad, Umesh Singh, Anil Prasad, Rahul Kumar, Mahesh Tyagi etc. were present on this occasion.

Prc Ramgarh Displays Military Pipe And Brass Band

Ramgarh.

On the auspicious occasion of 75th year of Indian Independence, the Punjab Regimental Centre, Ramgarh organised Military band display in training ground, near Subhash Chowk, Ramgarh as on 09 Aug 2021 with great fervor and enthusiasm. The band holds a distinct identity in playing Quick March, Slow March, Strathspey and Reel with patriotic tunes like Deson ka Sartaj Bharat, India Gate, Yeh Bharat Desh Hai Mera, Saare Jahan Se Achha etc. The scintillating performance by the Band mesmerised the complete audience including civilians and students. They cheered and were motivated by the energetic and synchronised display by Military Band. In 1940, Netaji Subhash Chandra Bose organised a 'Disagreement Rally' near Subhash Chowk to coincide with 53rd session of Indian National Congress under the presidency of Maulana Abul Kalam Azad. The Military band displayed



the Martial tunes on the training ground, which was used by expeditionary forces during World War-II. The Pipe and Brass band tunes were played to commemorate the Swarnim Vijay Varsh, 50 years of Indo - Pak War 1971.

MLA Amba Prasad inaugurates electric transformer

Ramgarh.

In Shivadih and Barua villages of Barkagaon block, the villagers were helpless and forced to live in the dark due to transformer failure for the past several days. The local villager kept his problem with the MLA in which there were complaints of frequent burning of the transformer. MLA Amba Prasad made available the transformers in both the villages. She duly inaugurated on Wednesday. The ribbon was cut by Prasad. When electricity came in both the villages, all the villagers expressed their gratitude to the MLA Amba Prasad. On this occasion, the MLA said that the villagers are constantly trying to get electricity smoothly in the entire area, she is ready to solve the problems of the people on time. The MLA said that if any transformer fails in the entire assembly constituency, contact directly, without any hesitation, tell so that the problem can be removed. Congress Committee President Visheshwar Nath Choubey, Sanjay Mahato, Pramod, Sukhdev, Ramvilas, Karthik, Bajinath, Sita Marandi, Mana Urao, Mahadev Hansda, Vijay, Vinay Murmu, Rajesh Murmu etc. were present on the occasion.



Weekend lockdown relaxed on Saturdays in Noida and Ghaziabad

New Delhi. As per the latest government orders, regular movement of persons can take place between 6 am to 10 pm on Saturdays from the coming weekend onwards in Noida and Ghaziabad. Weekend relaxation on Saturday has been allowed in view of declining Covid cases across the state. As per the latest government orders, regular movement of persons can take place between 6 am to 10 pm on Saturdays from the coming weekend onwards. The night curfew and Covid lockdown on Sunday will continue to function in the districts, officials said. A review meeting was held among state government officials to take a decision regarding Covid guidelines.

Marwadi Brahmin Family Ramgarh organised Teej celebrations

Ramgarh.

Social worker Sunita Choudhary participated as chief guest in the Teej and Sindhara program organized by the women of Marwadi Brahmin family. She was welcomed by the women of the society and honored by with a Sketch. On the occasion, the chief guest was congratulated on the Sawan festival by applying mehndi to her hands. Along with this, dance and music were organized by children



and women. On the occasion, the chief guest said that it is very good to see the solidarity of the women of Brahmin society, such events should be organized in every festival by children and women. After the conclusion of the program Sunita Choudhary presented trophies to the winners and promised to help them in every possible way for their bright future. Madhu Sharma, Aarti Sharma, Babli Sharma, Poonam Sharma, Seema Sharma, Pinky Sharma, Madhu Sharma, Kiran Sharma, Manju Sharma, Archana Sharma, Kumkum Sharma, Anjali Sharma were present on the occasion.

Employment training given to women

Jorapukhar.

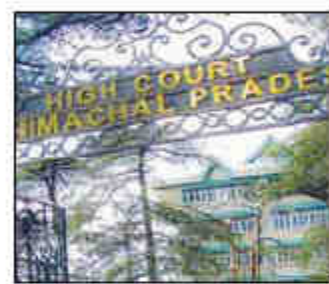
Employment training for women was organized by Vanchit Mukti Morcha today in West Bandha Basti, which was led by Karishma Khatoun, President of the Morcha. District President Shivshankar Prasad, Jharkhand General Secretary Sunil Kumar Varman, Jharkhand State President Ashok Kumar Pandey and Jharkhand in-charge Ramashish Chauhan were mainly present in the training. Shri Chouhan said that he has come from Patna to give employment training so that you can become self-reliant. People from here go to other states in search of employment and play an important role in the development of those states. Our organization wants that your contribution should be in the development of Jharkhand instead of other states. Presently, you will be linked with employment by organizing tailoring training camps. Apart from this, people will also be connected with trade through products like tea, surf, spices, oil etc. President Karishma Khatoun said that I thank Jharkhand in-charge cum Bihar State President Ramashish Chauhan for bringing such products. I demand from them that through the government, employment should be arranged in backward villages only so that people can live with their families. State President Ashok Kumar Pandey promised that the front would make continuous efforts to get employment in your village itself. On this occasion Secretary Parveen Khatoun, Treasurer Rita Rai, Members Shahjahan Bibi, Manju Kumari, Sumitra Rai, Savina Bibi, Noorjahan Bibi, Roshan Ara, Sanjita Sharma, Babita Mandal, Baby Mandal, Sandhya Mahato, Sulochana Mahto, Manju Rai, Maneka Rai, Manju Verma and others were present.



HP: Make all court building accessible to differently abled

Shimla, Agency.

Himachal Pradesh High Court on Wednesday passed an order asking the state government to make all the Court buildings in the state of Himachal Pradesh fully accessible to the differently abled people. The acting Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh, Justice Ravi Malimath directed the Registrar (GAD) of High Court and all the District & Sessions Judges in the state to take immediate steps to comply with the provisions of the Disabilities Act, 2016. The acting Chief Justice directed all the District and Sessions Judges in the state to take immediate remedial steps for making provision of ramp with railings and construction of disabled friendly toilets in all the judicial complexes. He has also directed them to make provision of lift, where the complex is multistoried and to call for an urgent meeting of the District Court Management Systems Committee, to consider the availability of the aforesaid facilities in the court buildings and also the facility of auditory and visual signage and Braille button in a lift in all multistoried buildings. The acting Chief Justice directed the Registrar (GAD) to take immediate steps for construction of disabled friendly toilets in the High Court and to ensure the compliance of the provisions of the Disabilities Act, 2016, to make the court building fully accessible to the differently abled persons.



'Chhari-Sthapana' ceremony performed at Amareshwar Temple in Srinagar

Srinagar, Agency.

'Chhari-Sthapana', a ritual associated with the annual pilgrimage to holy Amarnath cave shrine in south Kashmir Himalayas, was performed at Shri Amareshwar Temple Akhara Building in the summer capital, Srinagar, on Wednesday. The ceremony was performed with chants of Vedic hymn at the temple by a group of Sadhus led by Mahant Deependra Giri, custodian of the holy silver Mace of Lord Shiva. The Puja lasted for about 2 hours. Chhari-Mubarak (Holy Mace), one depicting Lord Shiva and another Goddess Parvati, shall be kept in the Temple at Akhara Building Srinagar for 'Darshan' till it leaves for main course of pilgrimage on August 22. Devotees, who strictly follow COVID-19 protocols, shall have the privilege to have 'Darshan' of Holy Mace kept in Shri Amareshwar Temple Dashnami Akhara Budshah Chowk Srinagar from 1000 hrs to 1100 hrs and 1800 hrs to 1900 hrs, Giri said. He said traditional 'Chhari-Pujan' shall be performed on Friday on the occasion of 'Nag-Panchami'.



(Shravan Shukla Paksha Panchami) at Dashnami Akhara, Srinagar. 'The True Trust', founded by Mahant Deependra Giri in year 2004, has made all the necessary arrangements like yesteryears for the main course of pilgrimage. The pilgrimage was cancelled for the second consecutive year due to COVID-19 pandemic. In 2019, it was cut short and the yatriis were directed to leave J&K

after the Centre abrogated Article 370 and divided the erstwhile state into two Union Territories (UTs) on August 5. However, all age-old traditions associated with the yatra are being performed. On Monday, the Holy Silver Mace of Lord Shiva 'Chhari Mubarak' was taken to ancient Sharika Bhawani Temple at Hari Parvat in the downtown Srinagar as per age-old tradition associated with annual

■ The Puja lasted for about 2 hours. Chhari-Mubarak (Holy Mace), one depicting Lord Shiva and another Goddess Parvati, shall be kept in the Temple at Akhara Building Srinagar for 'Darshan' till it leaves for main course of pilgrimage on August 22.

pilgrimage. The holy mace later returned to Amreshwar temple, where 'Chhari-Sthapana' ceremony was performed on Wednesday. Temple Akhara Building Budshah Chowk Srinagar and traditional 'Chhari-Pujan' shall be performed on the occasion of 'Nag-Panchami' that falls on August 13, 2021. Chhari-Mubarak shall leave for Holy Shrine situated at an altitude of 13,500 feet in South Kashmir from Dashnami Akhara Srinagar for main course of pilgrimage on the auspicious occasion of 'Shravan-Purnima' (Raksha-Bandhan) falling on August 22 this year.

Police use lathis, water cannon on Youth Congress workers marching to gherao CM's house



Bhopal, Agency.

Workers were protesting against inflation and unemployment and in support of OBC reservation. IYC president Srinivas among those detained. Police Wednesday resorted to lathicharge and used water cannons to disperse thousands of Youth Congress workers marching towards Shymala Hills in Bhopal on Wednesday to gherao the Chief Minister's residence. The workers were protesting against inflation and unemployment and in support of OBC reservation. While many workers suffered injuries, National Youth Congress president Srinivas BV, state president Vikrant Bhuria and MLA Jaivardhan Singh along with hundreds of party workers were bundled into police vans and detained. The roadshow with over 2,000 workers started from Congress office after the address by the president of the Congress Committee, Kamal Nath, around 1 pm. Srinivas, Bhuria, and Kunal Chaudhary led the protest. However, just a few meters ahead, they were stopped by the police who had barricaded the roads and deployed at least four water cannons amid heavy police bandobast. The workers began crossing

over the barricades when the police, headed by DIG Irshad Wali, used water cannons and lathi charge to thwart them. The initial plan to 'Gherao Vidhan Sabha' was changed to that of the gherao of CM House after the four-day long monsoon session was adjourned since die on Tuesday, a day before the protest. The protesters subsequently were on their way to Chief Minister Shriyaji Singh Chouhan's House demanding OBC reservation and to protest the government's failure to check rising prices and fuel rates among other things. Srinivas said, "The police lathis, water cannons or even police firing will not stop the youth of the country. The use of water cannons will not break the spirit of the Youth Congress, we are followers of Mahatma Gandhi. Our ancestors have gotten the country free from the rule of British and now we will free the country from the rule of British informers." MLA Jaivardhan Singh said that "every drop of Congress worker's blood spilled is dedicated to Madhya Pradesh," adding "we are committed to the people of the state and our struggle will continue." The BJP government headed by Shriyaji Singh Chouhan has become insensitive to the people of the state.

The Government of Bihar has signed a Memorandum of Cooperation with the Bill & Melinda Gates Foundation

Patna.

The Government of Bihar (GoB) has signed a Memorandum of Cooperation (MoC) with the Bill & Melinda Gates Foundation (Gates Foundation), as part of which the Foundation will provide technical support to select departments for the next five years, effective April 2021 to March 2026. The MoC, was signed today, in the august presence of Chief Minister Shri Nitish Kumar, Deputy Chief Ministers, Shri Tarkishore Prasad and Smt. Renu Devi, and Health Minister, Shri Mangal Pandey. It focuses on institutional capacity building to sustain the transformative progress in Bihar over the past decade. GoB and Gates Foundation first signed an MoC in 2010, which was renewed in 2016 and continued till March 2021. The signatories to the current MoC are Chief Secretary, GoB Shri Tripurari Sharan and India Director, Gates Foundation, Shri Hari Menon.

On the occasion, Health Minister, Shri Mangal Pandey said, "The Bihar Government is committed to improving the quality of life for the people of the state. We are delighted to have the continued support from Gates Foundation in providing us technical expertise and assistance as we collectively work towards Bihar's progress." Pratyaya Anrit, Additional Chief Secretary, Department of Health said "This will help us to design, build and provide technical support to operationalize an open source, digital



public health platform". Shri Hari Menon, Director, Gates Foundation, said, "Bihar has made significant progress in improving various health, social and development indicators for its population. We are honoured to continue on this journey with the state, and support this work further, to help improve health, and nutrition outcomes, and reduce the burden of disease and poverty, by enabling livelihoods and access to quality services, in line with the state's development goals." Through the MoC, Gates Foundation will provide technical support to the departments of health, social welfare, agriculture and rural development, particularly Jeevika, finance and planning. Both the parties have agreed that significant steps are necessary to improve the reach, coverage, quality and programme components of health, nutrition and sanitation services,

agricultural productivity, financial inclusion and gender equality in the state of Bihar to ensure progress towards the Sustainable Development Goals (SDG) 2030. The other objectives of the MoC are to reduce maternal, neonatal, infant and child morbidity and mortality, unmet need for contraception specially for lower parity couples and for spacing / reversible methods, improve maternal and child nutrition, including anaemia, reduce stunting and improve sanitation outcomes by providing techno-managerial support in the respective departments in the GoB. The focus will also be to eliminate communicable diseases like tuberculosis, visceral leishmaniasis and lymphatic filariasis and build state institutional capacity to do research in diseases like acute encephalitis syndrome and visceral leishmaniasis.

Amarinder meets PM, seeks repeal of farm laws

New Delhi : Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh on Wednesday urged Prime Minister Narendra Modi to immediately initiate steps for the repeal of

the controversial farm laws, and amendment to the relevant law for including farmers in free legal aid category. The Chief Minister, who called on the

Prime Minister here late Wednesday evening and submitted two separate letters, called for immediate review and revocation of the three farm laws that had trig-

gered widespread resentment among farmers of Punjab and other states, who had been protesting at the Delhi borders since November 26 last year.

Delhi Jal Board should make efforts on war footing to clean Yamuna within next three years : Satyendar Jain



Delhi Water Minister Satyendar Jain held a meeting with the Delhi Jal Board senior officials to review the progress on the work of cleaning Yamuna river and 24-hour water supply scheme

STP is being revamped with low cost and efficient interventions to boost the cleaning process: Satyendar Jain

further said that it is very important for government departments to keep learning as it increases creativity and also saves the public's money. The meeting was attended by senior officials of Delhi Jal Board, who laid down various issues like augmentation and closing of STPs which would boost the capacity of STPs. Shri Satyendar Jain said that, "STP is being completed ahead of time and at cost." Officials of the Delhi Jal Board also informed that all the boring works for the water harvesting wells will be completed by the end of this year. Water Minister Satyendar Jain also added that, "All the concerned departments will contribute 100% in order to ensure a 24-hr water supply in Delhi till the next summer season." PWD, Delhi Jal Board and DSIID are involved in both these projects at different levels. Water Minister Shri Satyendar Jain is guiding these three departments to complete these projects in a time bound manner. Shri Satyendar Jain also stressed on the importance of learning for the administration and government departments, as it helps in finding new ways of doing things, while also saving the public's money and time.

OPEN SEARCH

NEW DELHI : Water Minister Shri Satyendar Jain met with the officials of the Delhi Jal Board on Wednesday to review the progress of cleaning the Yamuna and the 24-hour water supply scheme. Satyendar Jain said that, with the up gradation of STP, cleaning of Yamuna

will be done on war footing within the next 3 years. Apart from this, he also told about the state-of-the-art wells being built in the capital to ensure 24-hour water supply during the next summer season. The Water Minister said that, these tasks are called impossible by experts but, with creativity and dedication, we will fulfill our commitment. He



STERLING TOOLS LIMITED

Registered Office : UNIT NO. 515, DLF TOWER A, JASOLA DISTRICT CENTER, NEW DELHI-110025

CIN: L29222DL1979PLC009668, Website: www.stfasteners.com Ph.: 0120-2270621-25, Email Id: csec@stfasteners.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2021

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		QUARTER ENDED (UNAUDITED)		YEAR ENDED (AUDITED)		QUARTER ENDED (UNAUDITED)		YEAR ENDED (AUDITED)	
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021
1	Total Income from Operations	9,043.92	12,770.25	2,141.32	35,813.42	9,070.98	12,781.24	2,146.36	35,851.11
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	576.44	1,359.88	(1,145.39)	3,359.17	421.35	1,221.78	(1,190.17)	3,033.76
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	576.44	1,117.50	(1,145.39)	3,116.99	421.35	1,221.78	(1,190.17)	3,033.76
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	447.95	950.57	(877.34)	2,441.81	312.57	1,050.58	(921.89)	2,350.91
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	458.08	1,093.81	(874.78)	2,592.72	322.70	1,193.82	(919.33)	2,501.82
6	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 2/- each)	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48	720.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet for the Previous Year				32,742.67				32,426.79
8	Earnings Per Share (₹ 2/- each)- (for continuing and discontinued operations) Basic and Diluted (₹)	1.24	2.84	(2.44)	8.78	0.87	2.92	(2.56)	6.53

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly Audited/Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the Financial Results of the company is available on the website of Bombay Stock Exchange Limited (BSE) (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE) (www.nseindia.com) and the Company (www.stfasteners.com).
- The standalone and consolidated results for the quarter ended June 30, 2021 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on August 11, 2021.

Place: Faridabad
Date: 11th August, 2021

For and on behalf of the Board of Directors
STERLING TOOLS LIMITED
Sd/
ANIL AGGARWAL
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN No. 00027214

Open Search EDITORIAL

Why India's military leaders must have a free and frank discussion on demarcation of air power roles and missions

The conundrum that needs to be resolved is the IAF's certainty about the indivisibility of air power, versus the army and navy's belief that aviation must be available at their disposal overlap and confusion, and this led the US Congress to enact the National Security Act of 1947, which, apart from unifying the armed forces, created an independent US Air Force. However, many issues related to resources as well as institutional boundaries remained unresolved and bitter infighting broke out between the US Navy and the USAF over aviation "roles and missions". Given the urgency of addressing these contentious issues, in March 1948, the US Secretary of Defence cloistered himself with the service chiefs, and, together, they hammered out a consensus. This was enshrined in the "US Code of Federal Laws", and remains the legal basis for roles and missions of the US military. In India, no such discussion has ever taken place and there is no mutually agreed upon or government-mandated demarcation of aviation roles and missions. Periodic "sniping" and even "poaching" has, therefore, taken place, leaving the IAF beset with a deep sense of insecurity, for reasons that I outline. The 1970s saw an acrimonious debate between the IAF and the Indian Navy (IN) about the discharge of the maritime reconnaissance (MR) role, which the air force had inherited at independence. The penetration in 1971 of our waters by Pakistani submarines, having brought matters to a head, the government decided to hand over the MR role and aircraft to the IN in 1976. The Indian Army, too, had been demanding the creation of an integral air arm, citing unsatisfactory aviation support by the IAF in forward areas. The issue became another inter-service squabble till the government intervened in 1986 and sanctioned the transfer of assets from the IAF to the newly formed Army Aviation Corps. The controversy did not end here as control of attack helicopters remained an issue of inter-service contention. The IAF, having seen sister services appropriate its roles and assets, remained wary about jointness. Concepts of CIBS and integrated commands which would require air assets being placed under non-IAF control, ring alarm bells in Air HQs. There are misperceptions on both sides of the "air-power divide", and the crying need of the day is for the tri-service leadership to sit around a table and provide mutual reassurance regarding service "roles and missions". Air power, in the post-Cold War era, acquired a new aura. Based on the lethality and speed of modern air power, it is claimed that once "air dominance" has been achieved, the war is virtually won. In this paradigm, close support of surface forces receives low priority because quick military victories can be won from the air at minimal cost. However, such euphoric assumptions were based on recent conflicts where modern air forces wielding advanced technology had encountered irregular forces. India, on the other hand, is faced with well-equipped, motivated and competent adversaries. The IAF, although numerically inferior, is a professional peer and has the assurance of Chinese support.

Why the collegium system, while the best for judicial appointments, needs course corrections

Rekha Sharma

Lord Denning said, "Every judge, in a sense, is on trial to see that he does his job honestly, and properly", and that "justice is rooted in confidence, and confidence is destroyed when right-minded people go away thinking that the judge is biased". It goes to the credit of our earlier judges, though appointed by the state, that they administered justice judicially, and with the requisite detachment within the rule of law. The situation, however, changed with Indira Gandhi assuming office. In the matter of appointment of judges, political philosophy, and the political leaning of a candidate became a major consideration. And then came the Emergency. Judges were put to test in the matter of ADM Jabalpur, and barring one brave exception, the judges failed the Constitution, and thus the nation. They just forgot, nay ignored, the words of Lord James Mansfield in Rex versus Wilkes: "The constitution does not allow reasons of State to influence our judgments: God forbid it should! We must not regard political consequences; how formidable soever they might be! Rebellion was the certain consequence, we are bound to say 'fiat justitia, ruat caelum', meaning, let justice be done though the heaven falls." Realising the gravity of the said situation, and with an ardent desire to stop the judiciary from becoming an organ of state power, it was felt that the role of the state in the appointment of judges in terms of Article 124 (2) and 217 needed to be reconsidered. But then, in 1982 in S P Gupta's case, the Supreme Court gave its approval to the primacy of the state in the matter of appointment of judges. Mercifully, that judgment of a bench of five judges was overturned subsequently by a bench of nine judges. It held that the provisions for consultation with the Chief Justice of India, and the Chief Justices of the high courts in Articles 124 (2) and 217 of the Constitution were introduced because of the realisation that the Chief Justice is best equipped to know and assess the worth of a candidate, and his/her suitability for appointment as a superior judge. It also held that the initiation of the proposal for appointment of a judge to the SC must be made by the CJI after wider consultation with senior judges, and likewise in the case of high courts. And no appointment of any judge to the SC or any high court can be made unless it conforms with the opinion of the CJI. Thus, what is known as the "collegium system" was born. Governments, irrespective of which party is in power, have from time to time expressed their reservations about the courts taking upon themselves the power to appoint judges. The present government tried to dilute the primacy of the judiciary by introducing Article 124 (A) by a constitutional amendment, and by enacting National Judicial Appointments Commission Act, 2014. The SC has struck down both the amendment and the Act. Hence, the judiciary continues to enjoy primacy in the matter of appointments. Has the collegium system succeeded? Unfortunately, in some cases, it has not covered itself with glory. There have been cases where the nearest relative of Supreme Court judges has been appointed as a high court judge, ignoring merit. During the regime of Chief Justice Ranjan Gogoi, judges far lower in the combined All India Seniority of High Court judges were appointed to SC, and the reason assigned was that those selected were found more meritorious.

The repeal of the retrospective tax shows Modi government means business on reforms

Surjit S Bhalla

The repeal of the retrospective tax was long overdue, and strongly signifies that the reformist trend in Modi 2.0 is not only continuing, but also strengthening. The institution of the tax in 2012 meant that the state could impose a tax on an activity ex-post, that is, the government could change the goalpost according to its fancy was a stunner. Rumour has it that very few people in the Ministry of Finance, or outside, knew about this policy. Did PM Manmohan Singh know? Likely, but not entirely certain. Most experts believed that this policy was uniquely Indian, one befitting a country which had the word "socialism" inserted into the preamble to the Constitution some quarter century after the Constitution was written. We were foolish to think that a retrospective tax could not happen in modern India. A year after the retro tax, it came to light that ITC had been fighting a retrospective excise tax case for 17 years, and that the Supreme Court had decided in its favour. The allegation ITC had evaded excise taxes for four years from March 1983; it had allegedly sold cigarettes at a higher price than that printed on the packaging. It was widely anticipated that the retro tax would be thrown into the dustbin of history (where it belonged) in the interim budget of 2014. The tax lingered till now, with assurance by the late Arun Jaitley that the Indian government would not impose any new retro taxes. Mercifully, the BJP has kept to that principled promise. In recent days, instead of losing cases in its own Supreme Court (the ITC case noted above), it has been losing in international courts (Cairn and Vodafone). According to some critics, this delivery on a pre-2014 election promise is little more than window dressing on a tax that de facto does not exist anymore. The Modi government could easily claim that it was only following Indian law, an Act of Parliament, by pursuing the Cairn and Vodafone cases to their logical losing conclusion. So why make de facto de-jure? And why now? The reason offered by FM Nirmala Sitharaman is, "the country today stands at a juncture where a quick recovery of the economy after the Covid-19 pandemic is the need of the hour and foreign investment has an important role to play in promoting faster economic growth and employment." Was that the reason? Possible, but it is contradicted by the fact that India is enjoying one of the best years of foreign direct investment and foreign portfolio investment. What more could foreign investors want? It is not just a question of what investors (domestic or foreign) want. The larger answer is that this is what Modi and his team wanted before the 2014 election, and they are holding to their promise. Not only the promise of not imposing new retro taxes, but also the promise of repeal. Like many others, I had



consistently argued that a modern nation, especially a democratic nation, does not go about imposing retroactive taxes. It is had enough that for many decades, India had one of the highest effective corporate taxes in the world. (An effective tax is simply the ratio of the tax paid to income earned. The difference between the stated nominal and the actual effective arises because of legal tax deductions). At around 27 per cent, India had one of the highest effective corporate tax rates in 2019 (and earlier). That changed in October 2019, when Sitharaman reduced corporate taxes to near world competitive levels. In parallel, after having one of the highest real policy rates in the world, the Shaktikanta Das-induced trend is for India to have a competitive real policy rate. This march towards an internationally competitive economy needed the stamp of a tax litigation friendly regime an empty dream with the retro-tax still a possibility. Why should investors, domestic and foreign, trust that India will no longer indulge in the unthinkable? The end to the retro tax is a pointer of more capital reforms to come. The Commerce Department HLAG committee report was published in September 2019. That report had argued for several reforms, including some major reforms in the capital market. A long-neglected aspect of Indian exports are exports related to financial services. In 2018, Indian financial sector exports were a paltry \$5 billion. Putting this in perspective is the reality that food exports from a food-deficit India in 1980 were of a higher value \$10 billion. Major foreign investment banks enjoy one of the largest rents from participating as "monopolists" in the Indian equity markets. If rumours become reality, Indian investors will soon be able to directly buy and sell securities in foreign capital markets and enjoy zero commissions on most trades. And no fees to financial intermediaries. These purchases will be curtailed at \$2,50,000 per individual as part of the long-standing RBI Liberalised Remittance Scheme. Today, financial transactions can easily be tracked by tax authorities. Think what would happen to portfolio

inflows into India if a foreigner could purchase securities directly from the Indian capital market. Where would tax havens go? Commission rates in India will go down for all investors, including domestic. Markets will be more stable, as a collection of individual investors is unlikely to collude as big investors allegedly do. At present, the only way a foreign individual can participate in Indian markets is via the expensive high commission (low returns?) monopolistic FII route. Another financial market reform, and one directly influenced by this goodbye to the retro tax, is that Indian sovereign (and corporate) bonds can become part of global bond indices. The cost of borrowing for governments and corporates will come down as individuals across the world invest in the now high nominal (and real) Indian yields. Today, Europe and Japan have zero nominal 10-year yields, and the US is at 1.3 per cent. More capital will mean more investment and more investment means higher growth. The 2020s are being defined by the US-China cold economic war. China has enjoyed superlative economic growth for three decades. There is the important stylised inverted U-shaped pattern of catch-up growth. In early stages, a country is far from the productivity frontier defined by the advanced countries. Little investment goes a long way and a country grows faster than the average GDP growth of 2 per cent of an advanced country. After the peak (of the inverted U), growth decelerates and the economy begins to approach the low productivity growth of the West. China's GDP growth peaked more than a decade ago. The deceleration of Chinese growth will likely increase in the coming decade. There is only one country in the world that has the scale to match China. India can enjoy a late-comer advantage for the next two decades. But it cannot do so with a retrogressive tax regime. India needs to be trusted completely on the rule of law. The rule of law will also help privatisation and other associated best practices. This is likely the real reason why the retro tax had to be formally booted out.

As climate deadline looms, a look at what science says, what politics delivers, and what the economy demands

Arunabha Ghosh

Is there a way to shift from the sensational to the strategic? Earlier this week the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reported on climate science, warning against the fully of a business-as-usual development model. Past assessments have been disregarded as sensationalist. For attention to shift from a day of front-page news to a more strategic conversation, we must understand what the science says, what the politics delivers, and what the economy demands. Globally, average surface temperatures have already risen by 1.09°C between 1850-1900 and 2010-2019 thanks to anthropogenic emissions of greenhouse gases. What happens next depends on our development and technological choices. The IPCC document explores several scenarios based on shared socioeconomic pathways and different levels of radiative forcing (or the change in the energy balance in the atmosphere due to natural or human causes). If we followed high fossil fuel development (doubling emissions by 2050), temperatures would rise by 4.4°C (range of 3.3-5.7°C) by 2100. If a more sustainable pathway were pursued (with net-zero emissions by 2060 and negative emissions thereafter), average global temperature rise would be 1.4°C (range of 1.0-1.8°C).

Regardless, it is likely that average rise in temperatures will breach the 1.5°C barrier within the next two decades. If emissions are not mitigated rapidly, we are staring at rising climate risks and catastrophic impacts. Science has become better at attributing warming to human influence and extreme events to a changing climate. Less than 0.1°C of the warming observed since the pre-industrial era is thanks to natural reasons. Human influence is very likely the main reason behind glacial retreat since the 1990s. Since observations began, glaciers have lost the maximum mass during 2010-19. India is particularly vulnerable. If warming exceeds 4°C, India could see about 40% increase in precipitation annually, leading to extreme rainfall events. My colleagues at CEEW find



The claim on a fair share of the carbon budget is not a licence to pollute. India must adopt a more climate-friendly development pathway for its own sake. Its per capita incomes, energy consumption and carbon footprint are well below the global average but it must deliver high rates of economic growth within a shrinking carbon budget.

that three-quarters of India's districts are now hotspots of extreme weather events. Since 1990, more than 300 such events have resulted in damages exceeding INR 5.6 lakh crore. Just because our time horizons are limited does not mean that the climate will stop changing at the end of the century. Average rate of sea-level rise was 1.3 mm per year during 1991-71. Scientists say with high confidence that this rate increased to 3.7 mm annually during 2006-18. Even with warming restricted to 1.5°C, we are still on course for more than 2 metres of sea-level rise beyond this century. We are bequeathing a very different world to future generations. The world needs transformational change but countries have more myopic outlooks. The IPCC says that in order to stabilise rise in temperatures, two things have to happen: Anthropogenic emissions must become net-zero and in the interim cumulative emissions cannot exceed a global carbon budget. To stay within the 1.5°C limit, starting in 2020 the remaining global carbon budget is 300-500 gigatonnes of carbon dioxide (GtCO₂) (with a likelihood of 50%-83%). But who will cut their emissions? Of late, several large emitters have promised net-zero

emission targets. But China and the United States have already emitted 129 GtCO₂ and 344 GtCO₂, respectively, between 1990 and 2010. CEEW analysts calculate that despite their self-laundry targets, China would consume 87% of the global carbon space (if it reached net-zero in 2060) and the US would eat up 26% (if it reached net-zero in 2050). Clearly mere announcements of net-zero targets do little to retard the "carbon grab" of the largest emitters.

To use a Tokyo Olympics analogy, the largest current and historical polluters are putting gold medals on themselves, while poorer participants are left to compete on a very uneven playing field. The carbon budget did not, however, begin in 2020. What's left of it is a consequence of past inactions. In a pathbreaking study, CEEW researchers find that rich countries, as a whole, emitted ~25 gigatonnes of carbon dioxide equivalent (GtCO₂eq) more than their estimated emission allowance during 2008-20, thanks to non-participation in pre-2020 climate agreements and misuse of accounting loopholes. To put it in context, this is more than half the world's greenhouse gas emissions in 2019, or nine years' worth

of India's 2016 emissions. Climate justice demands that developed countries now take steps to free up carbon space for others. If climate science is stark and climate politics has been unjust, how do we meet our development aspirations? The claim on a fair share of the carbon budget is not a licence to pollute. India must adopt a more climate-friendly development pathway for its own sake. Its per capita incomes, energy consumption and carbon footprint are well below the global average but it must deliver high rates of economic growth within a shrinking carbon budget. India has an energy revolution underway. This ranges from household electrification to smart meters, scaling up solar and wind to new ambitions in biofuels and hydrogen, energy efficiency to clean cooking for millions, electrification of railways to electric vehicles, first country with a cooling action plan to skilling thousands in green jobs. Next, the discourse must shift from energy to the economy. There are very few sunrise sectors that are not low-carbon. India must tap new technology frontiers (green hydrogen), new business models (distributed and digitalised services, for distributed energy, EV charging, cold chains), new construction materials (low-carbon cement, recycled plastic), new opportunities in the circular economy of minerals, municipal waste and agricultural residue, and new practices for sustainable agriculture and food systems. Many of these technologies and business models are proven but need policy and regulatory support. Finally, it will become imperative to remove greenhouse gases from the atmosphere and repair the climate in critical regions, such as the poles. If those tipping points are breached, there will be disastrous consequences. This will require new levels of international cooperation. Climate science is not sensationalism but gets plugged that way because of our short attention spans. The climate crisis is a strategic threat to our development prospects. It deserves sober, continuing analysis, deliberation and action. The headlines look bad; reality will get worse.

Japanese opposition demands Parliamentary hearing on Sri Lankan woman's death

Tokyo, Agency.

Four opposition parties in Japan, the Constitutional Democratic, the Democratic Party for the People, the Communist and the Social Democratic, demanded that the case of the death of a Sri Lankan woman in the immigration center be brought before the parliamentary committee on legal issues, the national NHK broadcaster reported. On Tuesday, Justice Minister Yoko Kamikawa apologized for the inaction of the immigration center staff in the city of Nagoya, which resulted in the death of 33-year-old Wishma Sandamali from Sri Lanka in March. The minister promised to take measures to reform the work of immigration centers. The young woman's death in a temporary detention center for immigrants, where she was placed after it was revealed that she was in Japan on an expired student visa, caused a wave of criticism both domestically and abroad. Human rights activists insist that the victim was denied the necessary medical assistance. During the investigation, it turned out that the employees of the center neglected their duties, in particular, they did not notify the management about the woman's requests for a medical examination. In addition, on the day of her death, an ambulance was not called for her. After the incident, several protests against immigration policy took place across the country. As a result of growing discontent, in May, the Japanese authorities decided to withdraw a bill to amend the immigration law stipulating that the authorities could forcibly deport those who had been denied refugee status three times.



Andrew Cuomo's downfall paves the way for Kathy Hochul to make history

Tehran, Agency.

When Kathy Hochul is sworn in, she will make history as the first woman to serve as New York's governor. In two weeks, New York will get a new governor: Kathy Hochul, a daughter of western New York who has risen through public life on the strength of her generosity and work ethic, and amid the fallout of male politicians resigning in disgrace. Gov. Andrew Cuomo announced Tuesday that he would step down, following a state attorney general's report that found he had sexually harassed at least 11 women, many of them state employees. He will formally leave office in 14 days, at which point his long-serving lieutenant governor, Hochul, 62, will take his place. Should she run in next year's election for a full term, as expected, she will have the benefit of being the incumbent candidate.

When she is sworn in, she will make history as the first woman to serve as New York's governor. That her ascension came by way of a man's downfall is a testament to the state's long history of male political dominance, and its equally long history of male misbehavior, something that has become a growing political liability amid shifting social mores around power and gender dynamics. It is only recently that



women have begun to assume the highest offices in the state, and as often as not, they have done so after the men who came before them resigned in disgrace. "Why is it that these women are the second step? Why weren't they there in the first place?" said Christina Greer, an associate professor of political science at Fordham University, who argued that New Yorkers' reluctance to elect women to higher office showed that the state was not nearly as progressive as it purports to be. Assemblywoman Amy Paulin, who represents a district in Westchester, noted that Andrea Stewart-Cousins became the first female majority leader of the state Senate only recently. Both Stewart-Cousins and Letitia James, the state's first female

Her parents began their married life in a trailer while her father got his college degree. Her father ended up running an information technology company, while her mother co-founded a shelter for survivors of domestic abuse. She would go on to graduate from Syracuse University, earn a law degree from Catholic University of America, and enter private practice. Before long, she started working for the government, first as an aide to Rep. John J. LaFalce and then for Sen. Daniel Patrick Moynihan. She ultimately returned to western New York and jumped into local politics, first as a member of the Hamburg town board and then as Erie County clerk, where she gained national prominence for challenging Gov. Eliot Spitzer's bid to grant driver's licenses to immigrants without legal status. In 2011, opportunity struck, in the form of a congressman named Christopher Lee, a Republican who resigned after he sent a woman a shirtless photo of himself that ended up on the internet. Hochul won the ensuing special election in one of New York's most conservative districts, playing on fears that Republicans would eliminate Medicare. The next year, after reapportionment made her district even more conservative, she lost her seat to Chris Collins, a Republican who would also later resign in disgrace.

India-gifted Mi-35 attack helicopter lands in Taliban hands?



Kabul Agency

One of the Mi-35 attack helicopters, gifted by India to the Afghan Defence forces two years ago, may have fallen in the hands of Taliban which have reportedly captured the Kunduz airport. Even though there is no official confirmation yet from either the government of Afghanistan or India, messages and videos circulating on the social media, including the ones posted from pro-Taliban handles, suggest that a Mi-35 helicopter was taken into custody at the Kunduz airport by the fundamentalist militia after taking over the key Afghan city on Sunday. In the videos and photos, the helicopter is seen with the rotor blades removed. Videos and photos posted by security expert Joseph Dempsey of the International Institute for Strategic Studies show a Taliban militant posing next to a Mi-35 helicopter parked somewhere on an

October 15, 2019, in support of the country's counterterrorism efforts. India's Ambassador to Afghanistan, Vinay Kumar, and the then acting Afghan Defence Minister, Asadullah Khalid, had attended the ceremony of the formal handing over of the helicopters to the Afghan Air Force at a military airbase in Kabul. The two multi-role Mi-35 – as well as a pair delivered earlier in 2019 – were replacements for four helicopters India transferred to Afghanistan between 2015 and 2016.

**GOVERNMENT OF MANIPUR
PUBLIC WORKS DEPARTMENT**
TENDER NOTICE NO: EE/ND/TDR/2021-22/1
Dated, 11th August, 2021

The Executive Engineer, Noney Division, PWD, Manipur on behalf of the Governor of Manipur invites sealed item rate tender through manual tender from approved and eligible contractor registered PWD, Manipur for 8 Nos. Plan works under MH:5054.2 Nos. Plan works under MH: 4059, 1 Nos. Plan works under MH:2059 & 26 Nos. Non-Plan works under MH:3054 (Road works, Building, culvert, compound wall, Land development, etc.) at a cost at Rs.1057 Lakhs within Noney District, Manipur.

The procurement, officer is Executive Engineer, Noney Division, PWD, Manipur. The tender details and documents shall be available from the office of the Executive Engineer, Noney Division, PWD, Manipur.

Bid submission start date-> 12-08-2021, time 11:30 a.m.
Bid submission end date-> 06-09-2021, time 3:30 p.m.
Date of opening of Bid-> 07-09-2021 at 11:30 a.m.
Venue:- Office of the Executive Engineer, Noney Division, PWD, Manipur.

Sd/-
Executive Engineer,
Noney Division, PWD, Manipur.

GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED
CIN: L67190DL1995PLC069768
Regd. Off: R-815 NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI-110060
Email Id: genesislimited1995@gmail.com, Website: www.genesisdevelopersholdings.com
Ph: +91-11-28742357, +91-9891095232
Unaudited Financial Result for the Quarter Ended 30.06.2021

S.N	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		CURRENT QUARTER	PREVIOUS QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	YEAR TO DATE FIGURES
		01.04.2021 to 30.06.2021 (₹) Unaudited	01.01.2021 to 31.03.2021 (₹) Audited	01.04.2020 to 30.06.2020 (₹) Unaudited	01.04.2020 to 31.03.2021 (₹) Audited
1	Total Income from operation	-	-	-	-
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	(0.41)	1.19	(0.10)	4.17
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional items)	(0.41)	1.19	(0.10)	4.17
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional items)	(0.41)	1.19	(0.10)	4.17
5	Total [Comprehensive income/ loss for the period [comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	(0.41)	1.19	(0.10)	4.17
6	Paid up equity share capital	816.52	816.52	816.52	816.52
7	Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in the balance sheet for previous years	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) not Annualised- Basic & Diluted	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.03)

Note 1. The above unaudited standalone financial results for the quarter ended June 30, 2021 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors and taken on record at the meeting held on 11/08/2021.

Note 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations 2015. The full format of the quarterly unaudited financial result are available on the company's website www.genesisdevelopersholdings.com and also on the website of MSEI Limited i.e www.msei.in

Date: 11.08.2021
Place: New Delhi

DEEPAK TYAGI
Managing Director
DIN: 02760361

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED
CIN:L65929DL1985PLC021037
Regd. Off: R-815 NEW RAJINDER NAGAR NEW DELHI North East DL 110060 IN
Corporate Off: 47/18, Basement Rajendra Place Metro Station New Delhi-110060
Email Id- alstonetextiles@gmail.com, Website- www.alstonetextiles.in Ph. 011-25755261
Unaudited Financial Result for the Quarter Ended 30.06.2021

S.N	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		CURRENT QUARTER	PREVIOUS QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	YEAR TO DATE FIGURES
		01.04.2021 to 30.06.2021 (₹) Unaudited	01.01.2021 to 31.03.2021 (₹) Audited	01.04.2020 to 30.06.2020 (₹) Unaudited	01.04.2020 to 31.03.2021 (₹) Audited
1	Total Income from operation	-	-	-	-
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exceptional items	(0.39)	(2.73)	(4.23)	(8.77)
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional items)	(0.39)	(2.73)	(4.23)	(8.77)
4	Net Profit/ Loss for the period after tax (after exceptional items)	(0.39)	(2.73)	(4.23)	(8.77)
5	Total [Comprehensive Income/ loss for the period [comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	(0.39)	(2.73)	-	(8.77)
6	Paid up equity share capital	1,274.80	1,274.80	1,274.80	1,274.80
7	Reserve (excluding revaluation reserve) as shown in the balance sheet for previous years	11,153.75	11,153.75	11,153.75	11,153.75
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) not Annualised- Basic & Diluted	(0.00)	(0.02)	(0.03)	(0.15)

Note 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations 2015. The full format of the quarterly unaudited financial result are available on the company's website www.abhijittrading.in and also on the website of BSE Limited i.e www.bseindia.com

Date: 11.08.2021
Place: New Delhi

For and on behalf of board of directors of
ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED

Deepak Kumar Bhojak
Managing Director
DIN: 06933359

Apply For CANADA Permanent Residency
6 Bands in IELTS
Master Degree
3 Years Experience
For more Info.
8588061313
9999974013
8700165599

Crack IELTS With High score, Don't settle for average

Messi lands in France to join Paris Saint-Germain

Paris, Agency.

Lionel Messi arrived at Le Bourget airport in Paris to finalise his signing with Ligue 1 giants Paris Saint-Germain, following his tearful farewell to Barcelona on Sunday. Hundreds of fans have been waiting on Tuesday afternoon at the airport since Monday as the 34-year-old Argentine has been linked with the capital-based club right after his shock departure from Barcelona was announced. Messi, wearing a T-shirt which wrote "ici c'est Paris (this is Paris)", waved to the fans when walking out of the airport. PSG has released a video later in the afternoon on its official website which heavily implied that the signing is completed. A news conference will take place in the auditorium of the Parc des Princes on Wednesday at 11:00 am on Wednesday. According to French media L'Equipe, Messi has agreed on a two-year deal with the option of a third year with PSG. Messi is the latest big-name arrival at PSG on a free transfer this summer after coach Mauricio Pochettino's side snapped up Spanish defender Sergio Ramos after he left



Real Madrid. Dutch midfielder Georginio Wijnaldum also joined after running down his contract with Liverpool. Italy's Euro 2020-winning goalkeeper Gianluigi Donnarumma has also joined after his contract with AC Milan ran out, while Moroccan fullback Achraf Hakimi joined from Inter Milan for a reported 60 million euros. The arrival of Barcelona's all-time record scorer will definitely boost PSG's ambition to win the Champions League for the first time. Messi and his family were also pictured at Barcelona's El Prat airport earlier this afternoon and when asked by reporters whether his son would be joining PSG, Jorge Messi answered "yes".

Former New Zealand all-rounder Chris Cairns in intensive care after heart surgery

Melbourne, Agency.

Former New Zealand all-rounder Chris Cairns is in an intensive care unit at a Sydney hospital after undergoing cardiovascular surgery following a major heart incident in Canberra last week. St Vincent's Hospital in Sydney said Cairns, who was admitted on Tuesday, was in "a serious but stable condition" in intensive care. His wife Melanie Cairns said the cricketer had surgery in Canberra after a "major medical event" late last week but the seriousness of his condition required him to be transferred to St Vincent's for another operation.

Chris' family and friends are heartened by the respectful and warm manner in which this terrible news has been reported, and received by the public, both in New Zealand and around the world, and thanks everyone for their warm wishes, prayers, and kind words, she said in a statement on Wednesday. New Zealand media outlet NewsHub on Tuesday reported 51-year-old Cairns had suffered an aortic dissection - a tear in the body's main artery. "We're deeply concerned to hear of Chris Cairns' medical emergency," Cricket New Zealand boss David White said in a statement. "Our



thoughts are with his family in Aus and here in NZ. Chris is a much loved husband, father, and son - and remains one of our finest all-rounders. We hope he's able to make a full recovery." Cairns played 62 tests, 215 one-day internationals and two Twenty20

matches for New Zealand between 1989-2006. His father Lance also represented New Zealand in cricket. News of his health setback rocked New Zealand, where former team mates expressed sympathy for his family. "It's absolutely devastating. It's

the worst news you could possibly get," former New Zealand team mate Chris Harris told local media. Cairns has lived in Canberra for several years. After retiring from international cricket, he was the subject of allegations of matchfixing in India as captain of the Chandigarh Lions in the defunct Indian Cricket League (ICL) in 2008. He denied any wrongdoing and fought several legal battles to clear his name, winning a libel case against former Indian Premier League chairman Lalit Modi in 2012. In 2015, he was cleared of perjury in relation to the libel case after being charged by Britain's Crown Prosecution Service. Former New Zealand captain Brendon McCullum, who testified against Cairns during the perjury trial, said the cricket community was suffering along with Cairns' family. "It's a difficult subject to obviously talk about. We haven't seen each other for quite a long time," McCullum, a host on New Zealand radio station SENZ, said. "Our relationship is unimportant in the whole thing, the fact is that Chris is a father and also a son to Lance and (mother) Sue. Today my family and myself are thinking of those people who are suffering."

Jasprit Bumrah returns to top 10, Virat Kohli slips in ICC Test Players rankings



Dubai, Agency.

Riding on his fine show in the opening Test against England, India pacer Jasprit Bumrah has returned to the top 10, but skipper Virat Kohli slipped to the fifth position in the latest ICC men's Test player rankings. Bumrah, who held a career-high third position in September 2019, has improved 10 slots to grab the ninth place among bowlers after a match haul of nine for 110 in the Nottingham Test. Kohli, however, slipped a place following his duck in the first innings of the series opener. He was overtaken by England skipper Joe Root, who grabbed the fourth position in the batters' list after his Player of the Match performance of 64 and 109 earned him 49 rating points.

Opener Rohit Sharma and wicketkeeper-batsman Rishabh Pant were static at the sixth and seventh spots respectively. India all-rounder Ravindra Jadeja progressed three slots to 36th among batters with a first innings half-century and opener KL Rahul has re-entered the rankings in 56th position with scores of 84 and 26. Jadeja also improved a spot to take the second position in Test all-rounder ranking list, which also had senior India spinner Ravichandran Ashwin at the fourth spot. Ashwin continued to stay at the second place in the bowlers list, which was topped by Australia's Pat Cummins. Shardul Thakur was also up 19 places, to 55th, while England seam bowlers James Anderson (up one place to seventh) and Ollie Robinson (up 22 places to 46th) also moved up in the latest men's weekly

■ **Bumrah, who held a career-high third position in September 2019, has improved 10 slots to grab the ninth place among bowlers after a match haul of nine for 110 in the Nottingham Test.**

rankings update issued every Wednesday. Bangladesh's Shakib Al-Hasan was back to number one position among all-rounders in T20I rankings, having reached that spot last in October 2017. He has also gained three slots to reach 53rd among batters and advanced six positions to reach 12th among bowlers. Captain Mahmudullah has gained two slots and is now in 33rd position. Fast bowler Mustafizur Rahman is back in the top 10, gaining 20 slots after taking five wickets in four matches, while Mohammad Saifuddin (up 26 places to 43rd) and Nasum Ahmed (up 103 places to 66th) are among the others to make headway. Australia all-rounder Mitchell Marsh has gained four slots to reach 21st position among batters, after aggregating 111 runs in the last four matches of the five-match series in Bangladesh, played over the last week. Left-arm spinner Ashton Agar has gained one slot to reach seventh place among bowlers while fast bowler Josh Hazlewood is up 43 places to 34th position.

Eurosport India secures broadcasting rights of 2020 Tokyo Paralympic Games

Mumbai, Agency.

The Paralympic Committee of India on Wednesday awarded broadcasting rights of the upcoming Tokyo 2020 Summer Paralympic Games, to be held between August 24 and September 5, to Eurosport India. With a focus on local heroes, Eurosport India's coverage of the 2020 Paralympic Games will start on August 27 to coincide with the men's and women's archery events at Yumenoshima Park Archery Field. The Eurosport feed will also be LIVE on the discovery+ app for the fans to stay up to speed with all the action from Tokyo. India will be fielding its largest ever contingent this year with 54 Paralympic athletes participating across nine sporting disciplines. Mariyappan Thangavelu gold medalist men's high jump T-42 category in 2016 Rio Paralympic Games will be the flag bearer for the Indian team. Gursharan Singh, Secretary-General, Paralympic Committee of India said, "At the brink of a historic national sporting movement, our Indian Para Sportsmen are inspired and excited to win glory and pride for Country at



the upcoming Tokyo 2020 Paralympic Games. Such honouring moments must and would be shared and celebrated. Indians masses across the globe should be able to bask in the triumphant performance of our Paralympic Stars. Eurosport will be our official media broadcasting partner to share the exciting minute to minute live telecast of the said biggest Para Sporting Event. Fans will be able to cheer every Indian hero throughout the Games, including world No 3 and world No 2 Sumit Antil and Sandeep Chaudhary in Javelin; Manish Narwal (10m air pistol), Singhraj (10m air rifle), 50m air rifle) in shooting and Mariyappan Thangavelu in High Jump. Badminton will make its debut at the Games, which will feature as many as five shuttlers in the men's category -

Pramod Bhagat, Manoj Sarkar, Tarun Dhillon, Suhas Yathiraj and Krishna Nagar alongside the women's doubles pairing of Parul Parmar, Palak Kohli. "This is a milestone event in the short life of Eurosport India. Eurosport is the Home of Olympics in Europe and our association with Tokyo 2020 Summer Paralympic Games will be the first step towards a similar journey in India," said Mr Vijay Rajput, Senior Vice President. Affiliate sales and Product Distribution, Asia - India Sales & Distribution at Discovery Inc. and Head of Eurosport India. "While the Olympics may receive all the glory, and rightfully so this year with a scintillating performance from India, it's now time to promote our incredible Paralympic athletes who have made the country proud time and again," he added.

Naveen felicitates Hockey Olympians from Odisha with cash award, assures full support in future

Bhubaneswar, Agency.

Chief Minister Naveen Patnaik on Wednesday felicitated the players from Odisha in the Indian Hockey team after their return from Tokyo Olympics at a function in Kalinga Stadium. Deep Grace Ekka, Namita Toppo, Bhendra Lakra and Amit Rohidas were part of the Indian Hockey teams which created history at the Tokyo Olympics. Mr Patnaik handed over the cash award of Rs 2.5 crores to Bhendra Lakra and Amit Rohidas and handed over the other letter for appointment as Deputy Superintendent of Police in the State Police department. He appreciated the performance of the players in winning the Bronze medal for the country. Mr Patnaik also handed over a cash award of Rs 50 lakhs each to Deep Grace Ekka and Namita Toppo, who were part of the Indian Women's Hockey team at the Tokyo Olympics. He commended the spirited fight of the women's team in reaching the semi-finals and creating history in Indian Hockey. Lauding their performance, the chief minister advised them to continue their hard work and bring more laurels to the country while assuring them full support in future. Kalinga Stadium has become the global hub of Hockey. The next edition of the Men's Hockey World Cup will also be played at Kalinga Stadium, Bhubaneswar. The Players were excited to be back at their home turf where they had competed against the best in the world which helped them in their journey to the Olympics. The hockey players expressed their deep sense of gratitude towards the Chief Minister for supporting



Indian Hockey which led to wonderful results in the Tokyo Olympics. The Olympians were elated that the State Government had fulfilled its commitment of cash rewards and jobs on their arrival in the State. Bhendra Lakra, Vice-Captain of the men's team, presented to the Chief Minister the Team Jersey with the signatures of all the team members. Deep Grace Ekka, Vice-Captain of the Women's team also presented to the Chief Minister of the Team Jersey with the signatures of all the team members. The hockey players from the High-Performance Center and the Sports Hostel were present during the ceremony. Chief Minister Naveen Patnaik assured all support to the emerging players from Odisha. Odisha Sports and Youth Services minister Tusharkanti Behera and Chairman, Odisha Hockey Promotion Council, Dilip Tirkey, Secretary S-T Shri VK. Pandian and Secretary Sports R. Veenil Krishna also graced the ceremony.

Neeraj Chopra's gold winning feat named one of 10 magical moments of track and field in Olympics

New Delhi, Agency.

WA noted that Neeraj Chopra had 143,000 followers before the Olympics, but now has a staggering 3.2 million (on Instagram), making him the most followed track and field athlete in the world. Star javelin thrower Neeraj Chopra's historic gold-winning feat in the Olympics was listed as one of the 10 magical moments of track and field in the Tokyo Games by World Athletics. The 23-year-Chopra clinched the country's maiden Olympic medal in athletics with a best throw of 87.58m on Saturday to become only the second Indian to win an individual yellow metal in the Games. "Most keen followers of the sport had heard of Neeraj Chopra before the Olympic Games. But after winning the javelin in Tokyo, and in the process becoming India's first athletics gold medalist



in Olympic history, Chopra's profile sky-rocketed." The global governing body said on its website. WA noted that the 23-year-old Chopra had

143,000 followers before the Olympics, but now has a staggering 3.2 million (on Instagram), making him the most followed track and

■ **The 23-year-Chopra clinched the country's maiden Olympic medal in athletics with a best throw of 87.58m on Saturday to become only the second Indian to win an individual yellow metal in the Games.**

field athlete in the world.

In a tweet posted after winning the gold in Tokyo, Chopra has said, "Still processing this feeling. To all of India and beyond, thank you so much for your support and blessings that have helped me reach this stage. This moment will live with me forever." Gymnastics legend Nadia Comaneci was one of those former international stars who congratulated Chopra on Twitter.

England, India docked two WTC points; penalised for slow over-rates in 1st Test

Dubai, Agency.

England and Indian cricket team on Wednesday were fined 40 per cent of their match fees and penalised two ICC World Test Championship points each for maintaining slow over-rates in the first Test in Nottingham. The first Test of the five-match series between England and India at Trent Bridge ended in a draw on Sunday. With the game evenly poised, both teams were left frustrated on the final day as the game was called off without a ball being bowled. ICC Elite Panel of Match Referee Chris Broad imposed the sanctions after both sides were ruled to be two overs short of their targets after time allowances were taken into consideration. "In accordance with Article 16.11.2 of the ICC Code of Conduct for Players and Player Support Personnel, which relates to minimum over-rate offences, players are fined 20 per cent of their match fees for every over their side fails to bowl in the allotted time," the ICC said in a statement. "In addition, as per Article 16.11.2 of the ICC World Test Championship playing conditions, a side is penalised one point for each over short." It added, Captains Joe Root and Virat Kohli pleaded guilty and accepted the proposed sanctions, so there was no need for formal hearings. On-field umpires Michael Gough and Richard Kettleborough, third umpire Richard Illingworth and fourth umpire David Mills leveled the charges. Both the teams now have two points each in the ICC World Test Championship 2021-23 standings heading into the second Test at Lord's, which begins on Thursday.



News in Breif

RBL Bank empanelled as Agency Bank to RBI



Mumbai, Agency. RBL Bank on Wednesday said that it has been empanelled by the Reserve Bank of India (RBI) as an 'Agency Bank' to conduct banking business for the Central and State Governments. The authorisation will enable RBL Bank to handle a broad range of transactions related to government business, such as distributing Subsidies, Pension payments, collecting Central and State taxes including Income Tax, Excise Duties, Customs, GST, Stamp Duty, Registration, State Excise (VAT) and professional tax, in both online and offline modes. The accreditation comes on the heels of the RBI's guideline authorising scheduled private sector banks as Agency Banks to carry out specific government-related business transactions. It will allow RBL Bank to offer best-in-class tech-enabled platforms and digital products to government departments and enterprises, thereby making their banking journey convenient and seamless. Parool Seth, Head - FIG, Inclusive FI, MNC and New Economy Client Coverage, RBL Bank said, "We are pleased that the Government has opened up the Agency business to a few private sector banks as well. With the RBI's accreditation, we will be in a position to offer to the Centre and the State Governments, cost and time-efficient best-in-class products and solutions. We look forward to being the preferred choice and trusted partner of the government by efficiently discharging our responsibilities under the RBI's mandate."

Payworld to expand operations in South



Chennai, Agency. PayWorld, the fastest growing FinTech company in India, today announced expansion of its operations in South Zone. The company already has a strong foothold in the Tamil Nadu market where the average per day sale of its active retailers crosses millions. PayWorld facilitates digital transactions with services like mobile recharge, e-payment, railway reservation, and remittance services. PayWorld is a one stop solution for digital transactions with a network of 5,25,000-plus retailers in 700 districts across the nation. With this expansion, the idea is to transform and bring the marginalized areas of our nation together. All retailers on board are local and are well versed with the local language and dialects to understand the pain points of the customers, a Payworld release said. Currently, the average sale of our active PayWorld retailers in Tamil Nadu alone crosses millions on daily basis. On average, the retailers there do a minimum of 5,000+ digital transactions on daily basis. With such huge potential, it is believed that expansion will only add to the numbers and will garner huge profits and benefits for retailers and low-income groups in the Southern region. So far PayWorld has already signed 1,04,508 retailers in the South region adding to its active list of 5,25,000+ retailers across India. Commenting on the expansion, Mr. Praveen Dhabhai, COO, PayWorld said "We have already tied up with 1,04,508 retailers in the Southern market, and the number is only growing strong from here. With this expansion, we are hoping to capitalize and increase our retailer profits at the same time aid rural customers through digital utility services." "Right now, our primary focus is to grow in Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana markets. However, Tamil Nadu will continue to serve our main market but we hope to make digital payments a universally accepted model in rural India," he said.

Justin Trudeau condemns Chinese court's sentence in Canadian's espionage case

Beijing, Agency.

Canada's Prime Minister Justin Trudeau said a Chinese court's sentencing of Canadian businessman Michael Spavor to 11 years in prison for espionage on Wednesday was "absolutely unacceptable" and called for his immediate release. The United States embassy in Beijing also condemned the sentencing in a statement, saying that proceedings against Spavor and another Canadian charged with espionage were an attempt to "use human beings as bargaining leverage".

The espionage cases are embroiled in a wider diplomatic spat involving Washington and Beijing, and Spavor's sentencing comes as lawyers in Canada representing the chief financial officer of Chinese telecoms giant Huawei make a final push to convince a court not to extradite her to the United States. "China's conviction and sentencing of Michael Spavor is absolutely unacceptable and unjust," said Trudeau in a statement. "The verdict for Mr. Spavor comes after more than two and a half years of arbitrary detention, a lack of transparency in the legal process, and a trial that did not satisfy even the minimum standards required by international law," he said.



that this is the next step in the process to bring Michael home and we will continue to support him through this challenging time," the Spavor family said in a statement. Noting the presence of diplomats from 25 countries gathered at the Canadian embassy, Kerton said that "our collective presence and voice sends a strong signal to China and the Chinese government in particular, that all the eyes of the world are watching". The Dandong Intermediate Court also said 50,000 yuan of Spavor's personal assets will be confiscated. He will be deported on completion of his sentence, Barton said. The potential sentence ranged from 5 to 20 years. China detained Spavor in December 2018 and

he was charged with espionage in June 2019. The Dandong court concluded a one-day trial in March 2021 and waited till Wednesday to announce the verdict. Spavor's family said in March the charges against him are vague and have not been made public, and that he has had "very limited access and interaction with his retained Chinese defense counsel". Kovrig's espionage trial concluded in March with the verdict to be announced at an unspecified date. Some observers have said convictions of the two Canadians could ultimately facilitate an agreement in which they are released and sent back to Canada. China has a conviction rate of well over 99%, and public and media access to trials in sensitive cases is typically limited. Since Meng's arrest, China has sentenced four Canadians to death over drug charges. They are Robert Schellenberg, Fan Wei, Ye Jianhui and Xu Weihong. China has rejected the suggestion that the cases of the Canadians in China are linked to Meng's case in Canada though Beijing has warned of unspecified consequences unless Meng was released. Meng was charged with misleading HSBC Holdings PLC about Huawei's business dealings in Iran, potentially causing the bank to violate American economic sanctions against Tehran.

Prince Andrew likely to try to avoid testimony at all costs

London, Agency.

Prince Andrew may contest the U.S. court's jurisdiction, or ignore the civil lawsuit altogether, taking a chance the court might find him in default and order him to pay damages. Britain's Prince Andrew is likely to do anything he can to avoid giving evidence in a U.S. lawsuit filed by an American woman who alleges that he sexually assaulted her when she was 17, lawyers on both sides of the Atlantic say. Andrew may contest the U.S. court's jurisdiction, or ignore the civil lawsuit altogether, taking a chance the court might find him in default and order him to pay damages. No matter which way he goes, though, he will face the constant drumbeat of unsavory media coverage. "There's no good option," said Albert D'Aquino, a New York attorney who has defended clients in similar cases. The prince has repeatedly denied the allegations in the lawsuit, brought by one of convicted sex offender Jeffrey Epstein's longtime accusers, Virginia Giuffre. "I don't think he will submit to the court's authority to order him to give a deposition, or to answer questions on which he wishes to demur," said D'Aquino, a partner at Goldberg Segalla in Buffalo, New York. "He runs too much risk of self-incrimination, which could then spawn a criminal action against him," D'Aquino said. However he decides to respond, the lawsuit filed Monday is another unwanted story for Queen Elizabeth II, reminding people of Andrew's links to Epstein two years after the convicted sex offender's death. Britain's royal family is also still recovering from allegations of racism and insensitivity leveled at them by Prince Harry and his wife, Meghan, earlier this year. Buckingham Palace tried to move past the story two years ago, forcing Andrew to step away from royal duties after he gave a disastrous TV interview in which he failed to express regret over his relationship with Epstein or offer sympathy for Epstein's victims. "It's another big scandal for them," said Pauline MacLaran, a royal expert and author of 'Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture'. "You just have to feel very sorry for the queen. You know, just as Meghan and Harry had sort of started to quiet down... then this comes back again. And, of course, the whole seediness of it is dragged through the media yet again." Lawyers for Giuffre filed the suit Monday in the U.S. District Court for the Southern District of New York, alleging that Epstein forced her to have sex with Andrew in 2001, when she was 17. The suit says she had sexual encounters with Andrew in London, New York and the U.S. Virgin Islands, and that the prince knew she had been trafficked by Epstein. Giuffre, now 37, has made similar allegations in the past, but the lawsuit is the first time she has directly confronted Andrew in court. Andrew's representatives declined to comment on the lawsuit. In a 2019 interview with the BBC, he denied ever meeting Giuffre. "It didn't happen," he said. "I can absolutely categorically tell you it never happened. I have no recollection of ever meeting this lady, none whatsoever." David Boies, Giuffre's attorney, said his team tried to open settlement talks with Andrew's lawyers but they were ignored. Because of this, he said, Giuffre was forced to file the lawsuit before the deadline set by New York state law. "He can ignore me and he can ignore Virginia, which is what he's been doing for the last five years... But he can't ignore judicial process," Boies told Britain's Channel 4 television. "This is now a matter for the courts to decide." There is only a "small chance" Giuffre's lawsuit will ever be presented to a judge or jury because most civil cases in the U.S., especially high profile ones, are settled out of court, said Arick Fudali, a lawyer at The Bloom Firm, which has represented some of Epstein's victims. "The lawsuit does, however, increase pressure to settle the case." "It certainly puts his name back in the news, back in the international news, back in American news and back associated with Jeffrey Epstein," Fudali told the BBC. But D'Aquino said a settlement is unlikely at this point. If Andrew had wanted to settle the case, he would have done so before the lawsuit was filed when it could have been handled privately and kept out of the press, he said. Mark Stephens, a specialist in international law at Howard Kennedy in London, said Andrew's lawyers could pursue another strategy, opting to delay the suit as long as possible.



Afghan officials : Three more provincial capitals fall to Taliban

Kahul, Agency.

The Taliban seized three more provincial capitals in Afghanistan and a local army headquarters in a blitz across the country's northeast, officials said Wednesday, with the insurgents now controlling some two-thirds of the nation as the US and NATO finalize their withdrawal after its decades-long war there. The fall of the capitals of Badakhshan and Baghlan provinces to the northeast and Farah province to the west put increasing pressure on the country's central government to stem the tide of the advance, even as its lost a major base in Kunduz. Afghan President Ashraf Ghani rushed to Balkh province, already surrounded by Taliban-held territory, to seek help pushing back the insurgents from warlords linked to allegations of atrocities and corruption. While Kabul itself has not been directly threatened in the advance, its stunning speed raises questions of how long the Afghan government can maintain control of its countryside. The multiple fronts of the battle have stretched the government's special operations forces while regular troops have often fled the battlefield and the violence has pushed thousands of civilians to seek safety in the capital. The US military, which plans to complete its withdrawal by the end of the month, has conducted some airstrikes but largely has avoided involving itself in the ground campaign. "The Afghan government and military did not respond to repeated requests for comment about the losses. Humayoon Shahidzade, a lawmaker from the western province of Farah, confirmed Wednesday to The Associated Press his province's capital of the same name fell. Neighboring Nimroz province was overrun in recent days after a weeklong campaign by the Taliban. In Farah, Taliban fighters dragged the shoeless, bloody corpse of one Afghan security force member through the street, shouting: "God is great!" Taliban fighters carrying M-16 rifles and driving Humvees and Ford pickup trucks donated by the Americans rolled through the streets of the capital. "The situation is under control in the city, our mujahideen are patrolling in the city," one Taliban fighter who did not give his name said, referring to his fellow insurgents as "holy warriors." The crackle of automatic weapon fire continued throughout the day.



The fall of the capitals of Badakhshan and Baghlan provinces to the northeast and Farah province to the west put increasing pressure on the country's central government to stem the tide of the advance.

in Farah. Hujatullah Kheradmand, a lawmaker from Badakhshan, said the Taliban had seized his province's capital, Fozabad. An Afghan official, who spoke on condition of anonymity to speak about an unacknowledged loss, said Hagharan's capital, Pol-i-Khumri, also fell. The insurgents earlier captured six other provincial capitals in the country in less than a week, including Kunduz in Kunduz province a significant gain and one of the country's largest cities. On Wednesday, the headquarters of the Afghan National Army's 217th Corps at Kunduz airport fell to the Taliban, according to Ghulam Rabani Rabani, a provincial council member in Kunduz, and lawmaker Shah Khan Sherzad. The insurgents posted video online they said showed surrendering troops. The corps is one of seven across the army and its loss represents a major setback. It wasn't immediately clear what equipment was left behind for the insurgents. Some civilians who have fled Taliban advances have said that the insurgents imposed repressive restrictions on women and burned down schools. There have also been reports of revenge killings in areas where the Taliban have gained control. Speaking to journalists Tuesday, a senior EU official said the insurgents held some 230 districts

of the over 400 in Afghanistan. The official described another 65 in government control while the rest were contested. The official spoke on condition of anonymity to discuss the internal figures. Most of northeast Afghanistan has fallen to the Taliban, except for Balkh province. There, warlords Abdul Rashid Dostum, Atta Mohammad Noor and Mohammad Mohaqiq planned to mobilize forces in support of the Afghan government to push back the Taliban. Dostum in particular has a troubled past, facing investigations after the 2001 US-led invasion for killing hundreds of Taliban fighters last year by letting them suffocate in sealed shipping containers. After a 20-year Western military mission and billions of dollars spent training and shoring up Afghan forces, many are at odds to explain why the regular forces have collapsed, fleeing the battle sometimes by the hundreds. The fighting instead has fallen largely to small groups of elite forces and the Afghan air force. The success of the Taliban blitz has added urgency to the need to restart the long-stalled talks in Qatar that could end the fighting and move Afghanistan toward an inclusive interim administration. The insurgents have so far refused to return to the negotiating table. US peace envoy Zalmay Khalilzad brought a warning to the Taliban on Tuesday that any government that comes to power through force in Afghanistan won't be recognized internationally. Tens of thousands of people have fled their homes in the country's north to escape battles that have overwhelmed their towns and villages. Families have flowed into the capital, Kabul, living in parks and streets with little food or water.

Biden rules out changes in US troop withdrawal plan from Afghanistan

Washington, Agency.

President Biden in April ordered the withdrawal of all the US troops from Afghanistan by September 11 to end America's longest war. President Joe Biden has ruled out any change in the US plan to withdraw its troops from Afghanistan despite the Taliban increasingly gaining control over large swaths of the war-torn country, saying Afghan leaders need to come together and fight for themselves and their nation. President Biden in April ordered the withdrawal of all the US troops from Afghanistan by September 11 to end America's longest war.

The Pentagon's massive task of removing service members and equipment out of Afghanistan is nearly complete and the US military mission is slated to end by August 31. "No," Biden told reporters on Tuesday at the White House when asked if his current plan to withdraw troops could change at all. "Look, we spent over a trillion dollars over 20 years. We trained and equipped over 300,000 Afghan forces. Afghan leaders have to come together. We lost thousands lost to death and injury thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation," he



asserted. "The United States... I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support, making sure that their air force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But they've got to want to fight. They have outnumbered the Taliban," Biden said. As the US troops withdrew from Afghanistan, the Taliban has made stunning battlefield advances despite being vastly outnumbered by the Afghan military. Over the weekend, the Taliban seized five provincial Afghan capitals. Biden said the Afghans are beginning to

realise they've got to come together politically at the top. "But we are going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision," he said. Earlier, White House Press Secretary Jen Psaki told reporters the US went to Afghanistan to deliver justice to those who attacked them on September 11, to disrupt terrorists seeking to use Afghanistan as a safe haven to attack the US. "We achieved those objectives some years ago," she said. "We judge the threat now against our homeland, which is his responsibility as commander-in-chief to focus on, as being one where the threat emanates from outside of Afghanistan," she added. The President asked for a clear assessment, for a review from his team on what the possible implications could be, she said. "He asked them not to sugarcoat that. He asked them to lay out specifically and clearly what the consequences could be," she added. "I'll also note that we have provided a great deal and a range of assistance to the Afghan National Security Defence Forces and also proposed a significant amount of funding in the FY 2022 budget request for USD 3.3 billion for the Afghan Security Forces," she said. "So, he made a decision as commander-in-chief. Those are difficult decisions to make."

Aditya Birla Sun Life Insurance launches Guaranteed Annuity Plus

Kolkata, Agency.

Aditya Birla Sun Life Insurance (ABSLI), the life insurance subsidiary of Aditya Birla Capital Limited (ABCL), has announced the launch of an annuity plan - ABSLI Guaranteed Annuity Plus. This single premium plan offers guaranteed regular income for one's retirement and future financial needs, ensuring a stress-free and sustained lifestyle. This annuity plan with multiple annuity options can be customised to perfectly suit customers' unique financial needs during retirement. This non-linked, non-participating plan also provides customers the flexibility to choose either an immediate or deferred annuity. The deferred annuity option is specially designed for individuals who wish to invest early for a secured retirement and lock current annuity rates for guaranteed, life-long payment, during the retirement years. Customers planning to leave behind a legacy for their dependents can select the level or increasing annuity option. The plan allows individuals aged minimum forty-five years to choose from 10 annuity options: from single life to joint life, each tailored to an individual's post-retirement goals. The product is available on both individual and group platforms. Commenting on the launch, Kamlesh Rao, MD & CEO, Aditya Birla Sun Life Insurance, said, "As we forge forward in life, and deal with the disruption caused by the pandemic, people are adopting practical yet cautious approach towards managing their finances. They are seeking out options to generate guaranteed returns. ABSLI Guaranteed Annuity Plus provides for this critical need and allows one to generate regular income during one's retirement, without worrying about the rising prices, increasing health care costs, higher life expectancy etc. Keeping our customers' unique needs in mind, we have ensured that the plan provides multiple annuity options to choose from, ensuring our customers and their loved ones continue to enjoy their current lifestyle, during the golden years of their life."



Amit Trivedi, Varun Grover team up for Grahan

Mumbai, Agency.

Music composer Amit Trivedi and lyricist Varun Grover have come together to create two songs for the upcoming Disney Plus Hotstar VIP mystery drama Grahan, the streaming platform announced on Monday. Starring



Pavan Malhotra and Zoya Hussain, the series is directed by Ranjan Chandel with Shailendra Jha as showrunner. According to the streamer, "Chori Chori", the first of three original songs in the show, breathes life into the endearing, old-world love story of Rishi and Manu whose lives unravel as the story progresses. Written by National Award-winning lyricist Varun Grover, the track is sung by Abhijeet Srivastava and Rupali Moghe. Amit Trivedi, known for his work on films like Dev.D, Ishqzaade and Manmarziyaan, said this song captures and enhances different aspects of the show. "Grahan has an engrossing storyline along with visually-stunning scenes, and I wanted to create music that would match up to that intensity... For me, it was about creating a melody that would match up to the different moods of these characters who are all battling different demons in their life," the National Award-winning composer said in a statement. Swanand Kirkire, also a National Award winner, has penned the third song in the series. Inspired by author Satya Vyas' popular book Chaurasi, Grahan is produced by Jar Pictures. The eight-episode series is set to be released on Thursday for all subscribers of Disney Plus Hotstar VIP and Disney Plus Hotstar Premium.

Sawai Bhatt evicted from Indian Idol 12, Amitabh Bachchan's granddaughter Navya Naveli heartbroken

Mumbai, Agency.

On Sunday, Sawai Bhatt got evicted from Indian Idol 12 after receiving the least number of votes. As people on social media showed their displeasure over his exit, the singer's loyal fan Navya Naveli Nanda too seemed heartbroken. The granddaughter of Amitabh Bachchan is quite a fan of the singing reality show and has been publicly supporting the singer from Rajasthan. Taking to her Instagram story, Navya shared a picture of Sawai Bhatt from Indian Idol 12 and wrote, "Keep singing and shining!!!!!!" She also added a bunch of crying and heartbreak emojis. The young singer is yet to respond to this message. Earlier, Navya had posted a video of Sawai singing Kailash Kher's popular rendition "Teri Deewani". Along with the video, she wrote, "yassssss Sawai" and added fire emojis to it. Such adulation from Navya made Sawai feel 'honoured' and 'encouraged'. "It is my honour to receive so much love and affection from the granddaughter of Shri Amitabh Bachchan Sir whose name is Ms Navya Nandaji. I am encouraged by her support towards my performances



week on week. It definitely heightens my spirit and motivates me to perform better," Sawai told SpotboyE. He also expressed gratitude towards Indian Idol 12 for providing him a platform to showcase his talent to a wider audience. Sawai Bhatt hails from Rajasthan's

Nagaur and works there as a puppeteer and singer. He was in the bottom of the table this week, along with Mohammad Danish and Nihal Tauru. While Sawai was ousted from Indian Idol for getting the least number of votes, fans were not convinced. Calling the show a scripted

one, a Twitter user posted, "scripted #SawaiBhatt is the best singer in @indian_idol12. It is very unfair we want to ask @indian_idol12 why you give chance to public for voting when you have to eliminate the contestant a/c to u #bycottindianidol if pawandeep was in bottom 2 so how can he got highest votes?" Another one shared how it's hard to believe that the elimination happened on the basis of votes. "SawaiBhatt he is an amazing singer, he plays and sings so well, there are inferior people than him in the competition, I hardly believe that, this was based on people's votes. bring him back," they tweeted, while another comment read, "SawaiBhatt elimination was not expected. #ShanmukhaPriya or #idoldanish should have given way considering their weak performances in the last few episodes #IndianIdol2021". A couple of months ago, Sawai wanted to quit the reality show since his mother was not keeping well. It was on the persuasion of judges, Vishal Dadlani and Himesh Reshammiya, that he agreed to stay and realise his dream of becoming a popular singer. Hosted by Aditya Narayan, Indian Idol 12 airs on Sony TV.

Kabir Singh is 2 : Shahid Kapoor, Sandeep Reddy Vanga and Kiara Advani get nostalgic



Bengaluru, Agency.

It has been two years since the release of Shahid Kapoor and Kiara Advani starrer Kabir Singh. The film's director Sandeep Reddy Vanga and stars Kiara and Shahid marked the day with posts and photos. Sandeep shared a photo of Shahid from the film and wrote, "Mann se main, tann se tu, prem jo jode ek hi rooh - KABIR SINGH #2YearsOfKabirSingh Thank you all!" Kiara, on the other hand, has been reposting fans videos and photos on this day.

One of Kiara's fan clubs posted a video of various clips of the actor from the film and wrote, "Celebrating 2 yrs of the Most Loved Role of @advani_kiara i.e. Preeti Sikka From #KabirSingh. Preeti Touched Millions of Hearts and The way #KiaraAdvani Portrayed Each Emotion of Preeti is Incredible. We Love You Preeti #2yearsOfPreetiSikka #2YearsOfKabirSingh." Another fan @Sidian_Sania tweeted, "Its 2 years of preeti sikka. Ki as preeti is such a precious one Congrats to my girl @advani_kiara #2YearsOfKabirSingh #KiaraAdvani."

Shahid Kapoor got into his Kabir Singh mode a day before the film's anniversary. On the eve of the film's two years of release, Shahid shared a series of photos and videos of himself. Shahid posted two Instagram reels and a photo, which had the Kabir Singh theme music playing in the

■ **Shahid Kapoor and Kiara Advani-starrer Kabir Singh was an official remake of the director Sandeep Reddy Vanga's own Telugu film titled Arjun Reddy.**

background. Sharing one of his reels, Shahid wrote, "Looking back at Kabir." The film Kabir Singh was an official remake of the director's own Telugu hit, Arjun Reddy.

Despite being criticised for celebrating toxic masculinity, Kabir Singh was appreciated by the audience and emerged as Shahid's biggest hit till date. Indian Express film critic Shubhra Gupta wrote in her Kabir Singh review, "To watch a character like Kabir Singh do this thing for nearly three hours plonks the viewer squarely in a place of conflict."

Here's a fellow who thinks that going through life yelling and shouting, snorting-and-drinking on the job, assuaging his raging libido with crass directness, basically being a sexist so-and-so, is an acceptable thing." Kabir Singh was also the third highest grossing Bollywood film of 2019.

Thalapathy 65 first look poster : Vijay is a shotgun-wielding 'Beast'

Bengaluru, Agency.

It has become a tradition of sorts to reveal the title and first look posters of Vijay's upcoming films on the eve of the Tamil superstar's birthday. And keeping the tradition alive, Sun Pictures on Monday released the first look poster and title of Thalapathy 65. Written and directed by Nelson Dilipkumar, the film has been titled Beast. The poster shows Vijay's character wielding a shotgun with a mounted telescopic sight. But, the poster doesn't clarify whether Vijay plays a cop on a mission or a hitman for hire. The first look of Beast was released on the eve of Vijay's birthday. The actor turns 47 on June 22. The 65th film in Vijay's career went on floors in March this year before the second wave of coronavirus brought the country to a standstill again. And in April, Vijay and Nelson left for Georgia, where the shooting began. The director reportedly shot Vijay's introduction scene and an action set piece in the first shooting schedule. The shooting in Georgia lasted for



about 20 days, following which the cast and the crew returned to India. However, the filmmakers couldn't continue the production due to the restrictions imposed by the Tamil Nadu government to battle the growing Covid-19 cases. It remains to be seen whether the delay in production would impend the plans of the makers to release Beast in theatres for Pongal festival. Besides Vijay, Beast stars Pooja Hegde as

the female lead. The film will mark her comeback to Tamil cinema after a gap of nine years. Pooja made her silver screen debut with director Mysskin's crime drama Mugamoodi in 2012. And since then, the bulk of her work has happened outside the Tamil film industry. Beast is Vijay's fourth film with Sun Pictures. The production house has previously bankrolled Vijay's Vetalaikaran, Sura and Sarkar.

Mahesh Manjrekar to host Bigg Boss Marathi 3

Mumbai, Agency.

Bigg Boss Marathi is set to launch its third season soon, and makers have confirmed that actor-filmmaker Mahesh Manjrekar would return to host the show. On Monday, Endemol Shine India, producers of Bigg Boss, had released the first teaser of the upcoming show. Tagging Mahesh in the post, the caption read that the doors of Bigg Boss would open soon, and the only sound heard would be of Bigg Boss Marathi. As per sources, Bigg Boss Marathi 3 would launch next month. The makers are currently in the final process of locking the contestants. Once contracts are signed, each one of them would be put under quarantine for a specified period before they are sent to the Bigg Boss house. After emerging as a successful franchise in Hindi market, Bigg Boss entered the regional space a few years back. The show, till now has been made in Bangla, Telugu, Kannada and Tamil, and the Marathi version was launched in 2018 on Colors Marathi. Speaking exclusively to indianexpress.com, Mahesh Manjrekar had shared in the past how he was excited to host Bigg Boss Marathi.

"When I got to know Bigg Boss is being made in Marathi, I knew the show would require a host, who has a lot of character. At the back of my mind I knew I would be able to do it but with so many big faces already there in the Marathi industry, I did not know it could come my way. So when Nikhil (Nikhil Sane - Business Head of the channel) called me asking if I would do it, I was like don't



ask, I am already on-board," he said. Ruling that the limited audience will not deter its popularity, the actor-director added, "Yes, it is a concentrated audience but everyone in India likes to gossip. And there is always excitement about getting to know the real faces behind the celebs. It's highly entertaining to see the mask falling off when they get exposed to some tough challenges. Emotions will come out and that's the fun. I believe even when you lock up a small family of four people in a house, they will start fighting, and here, strangers are put under the same roof. The first few days are sweet but then, the real fun begins." The last two seasons of Bigg Boss Marathi have been won by Megha Dhade and Shiv Thakare.

Ted Lasso Season 2 trailer: Jason Sudeikis is back as the amateur football coach brimming with positivity

New Delhi, Agency.

It seems like nothing can get Ted Lasso's positivity down, not even Richmond's relegation. At least that is what it looks like in the trailer for 'Ted Lasso' Season 2, featuring Jason Sudeikis in the lead role. In the clip, we see Ted facing several questions about his team's demotion.

But Sudeikis' Ted is unfazed as he boldly answers all the potentially embarrassing queries. In an earlier interview with indianexpress.com, Jason Sudeikis had spoken about the 'universal theme' of Ted Lasso. "Because life and death, good and evil are ubiquitous and there are themes of Ted Lasso that are more on a human level, although it is all pulled through the prism of an American eye. But yes, we took on the



international challenges willfully," he said. The official synopsis for Ted Lasso Season 2 reads, "Golden Globe® winner Jason Sudeikis is Ted

■ **In an earlier interview with indianexpress.com, Jason Sudeikis had spoken about the 'universal theme' of Ted Lasso. "Because life and death, good and evil are ubiquitous and there are themes of Ted Lasso that are more on a human level, although it is all pulled through the prism of an American eye.**

Lasso, an American football coach hired to manage a British soccer team despite having no experience. But what he lacks in knowledge, he makes up for with optimism, underdog determination...and biscuits." Ted Lasso Season 2 arrives on July 23 on Apple TV Plus.

Loki: Marvel Studios reveal first poster of Lady Loki in all her dangerous glory

New Delhi, Agency. Marvel Studios has been super secretive about their latest series Loki, starring Tom Hiddleston in the lead role. However, on Monday evening, the makers shared a poster of Lady Loki, offering yet another tantalising glimpse into what lies ahead for fans of Loki. The poster



sees Lady Loki with her golden horns and a black cape, as she was presented in the second episode of the show. The caption of the image read, "This isn't about you." A new episode of Marvel Studios' #Loki lands Wednesday on @DisneyPlus. Sadly, there has been no teaser yet for the third episode, which means the audience will have to wait until Wednesday to know more. In the second episode of the show, we had seen the variant finally reveal itself as Lady Loki towards the climax. In the concluding portions, we saw Lady Loki, aka the dangerous variant, play with the Sacred Timeline as Loki followed her into a new dimension. So far, so good. The critical reception to Loki has largely been positive with Indianexpress.com's first impression of the show stating, "Both the episodes are absolute blast from start to finish. An emotional core is not what you would expect from a Loki TV show, but that is exactly what you get here." The third episode of Loki will stream from June 23 on Disney Plus Hotstar.